चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 07 सितंबर–13 सितंबर 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

प्रधानमंत्री का खाता-बही

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान देश की जनता से अच्छे दिन लाने का वादा किया था. यह अलग बात है कि अब उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता इसे जुमला बताते हैं या इससे इंकार भी करने लगे हैं. लेकिन, यह सच्चाई यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच उम्मीदों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था. ऐसा कोई भी क्षेत्र (सेक्टर) नहीं बचा, जिसके लिए मोदी ने वादों की बौछार न की हो. देश की जनता, खासकर नौजवानों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें बंध गई थीं. उन्होंने इतने वादे किए थे, जिन्हें वर्गीकृत करके बता पाना भी मुश्किल है. कुल मिलाकर कहें, तो देश के हर एक तबके के लिए उनकी झोली में कुछ न कुछ ज़रूर था. नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी अपार बहुमत से प्रधानमंत्री चुने गए. प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने वादों को क्रियान्वित करने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं. मसलन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया, सोलर पॉवर, जनधन, बीमा, पेंशन, आदर्श ग्राम आदि. इन सभी योजनाओं के पीछे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करना या शंका करना ग़लत होगा. लेकिन, यह देखना भी ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साल के कार्यकाल के दौरान घोषित इन योजनाओं का आज एक साल बाद क्या हाल है. ये किस स्थिति में हैं, ये अपने मकसद में कितनी कामयाब हो रही हैं और इनके क्रियान्वयन की जो गति है, क्या वह संतोषजनक है?

शफीक आलम

चौथी दुनिया ने मौजूदा सरकार के पहले साल में घोषित आठ योजनाओं की समीक्षा करने की कोशिश की है. इस समीक्षा में सरकारी आंकड़ों के साथ-साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के भी आंकड़े शामिल हैं, ताकि एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके और एक निष्पक्ष तस्वीर जनता के समक्ष रखी जा सके. इस विश्लेषण का मकसद इन योजनाओं की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करना नहीं है, बल्कि इसके ज़रिये इनके क्रियान्वयन पर एक समीक्षात्मक नज़र डालना है. पेश है, इन योजनाओं की मौजूदा स्थिति का एक लेखा-जोखा.

मेक इन इंडिया, लेकिन किसके लिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन से मेक इन इंडिया नामक एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में बदलने के साथ-साथ युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना भी है. इस अभियान की रूपरेखा इसकी औपचारिक शुरुआत के पूर्व ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अपने पहले संबोधन में पेश कर दी थी. उन्होंने दुनिया के उद्यमियों का आ वान करते हुए कहा था, आप भारत में आइए, यहां निर्माण कीजिए और दुनिया के किसी भी देश में ले जाकर बेचिए. हमारे पास कौशल है, प्रतिभा है, अनुशासन है और कुछ कर गुज़रने की इच्छाशक्ति है. बहरहाल, मेक इन इंडिया की शुरुआत हुए तक़रीबन एक वर्ष हो गए हैं. शुरुआती उदासीनता के बाद अब इस अभियान में कुछ प्रगति होती दिख रही है. कई विदेशी कंपनियों ने भारत में पूंजी निवेश के प्रस्ताव रखे हैं और कुछ ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है. भारत सरकार की संस्था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) द्वारा 15 जुलाई 2015 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विदेशी निवेश में 48 प्रतिशत इजाफ़ा हुआ है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि में विदेशी संस्थागत निवेशकों या वित्तीय बाज़ारों के माध्यम से आने वाली कुल धनराशि 40.92 अरब डॉलर थी. डीआईपीपी के आंकड़ों के मुताबिक, ज़्यादातर निवेशक फ़िलहाल टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर , ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स में अधिक रुचि ले रहे हैं. मोबाइल निर्माण करने वाली कंपनियों जिओमी, मोटोरोला और लेनोवो की एसेम्बलिंग यूनिट्स में काम भी शुरू हो गया है. सैमसंग, माइक्रोमैक्स और स्पाइस की एसेम्बलिंग यूनिटें भारत में पहले से काम कर रही थीं. ताइवान की कंपनी फोक्सकॉन ने पांच अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव रखा है. भारतीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, पिछले दो महीनों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में भारत सरकार को तकरीबन 90 हज़ार करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. ये प्रस्ताव रखने वाली कंपनियों में फिलिप्स, थॉम्सन, सैमसंग, एलजी और फ्लेक्सट्रोनिक्स आदि शामिल हैं.

विदेशी निवेश को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से पांच अगस्त 2015 को दी गई जानकारी के मुताबिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में 14.5 हज़ार करोड़, ऑटोमोबाइल में 6.35 हज़ार करोड़, ट्रेडिंग में 4 हज़ार करोड़, सर्विस सेक्टर में 3 हज़ार करोड़, टेलीकम्युनिकेशन में 2 हज़ार करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग

(शेष पृष्ठ 2 पर)

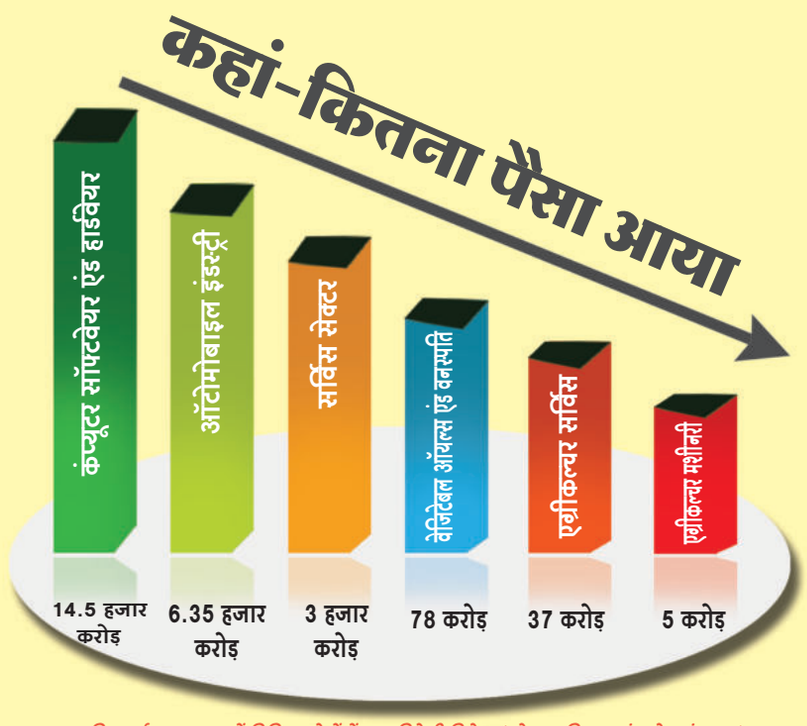

वित्त वर्ष 2015-16 में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ विदेशी निवेश (स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

मेक इन इंडिया के तहत विदेशी निवेश तो हुआ है, लेकिन यहां दिए चार्ट में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर पैसा आईटी, ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर में आया है. देश की सत्तर प्रतिशत आबादी, जो कि कृषि पर निर्भर है और जहां 54 प्रतिशत कामगार कृषि क्षेत्र में काम करते हों, उस कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों में बहुत ही मामूली निवेश हुआ है. सवाल है, आख़िर मेक इन इंडिया किसके लिए है?

पेज 2 और 3 पर पढ़ें बाक़ी योजनाओं का हाल

- सोलर पावर यात्रा : लक्ष्य हिमालयी, चाल कछुए की
- खेती से जुड़े 54 प्रतिशत कामगारों का कौशल विकास कैसे होगा
- ऐसे कब तक बन पाएगा स्वच्छ भारत
- योजना से नहीं, स्थानीय नेतृत्व से बनेगा 'आदर्श ग्राम'
- प्रधानमंत्री जन धन योजना : 46 प्रतिशत खातों में एक भी पैसा नहीं
- बीमा और पेंशन : कई सवाल अनसुलझे हैं
- अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं की मौजूदा स्थिति

प्रधानमंत्री का खाता-बही

पृष्ठ 1 का शेष

में 373 करोड़, मेटलर्जिकल सेक्टर में 466 करोड़, इंडस्ट्रियल मशीनरी में 413 करोड़, चीनी उद्योग में 90 करोड़, मशीन टूल्स में 22 करोड़ रुपये का ही विदेशी निवेश प्राप्त हुआ. यानी इन क्षेत्रों में निवेशकों की उदासीनता बरकरार है. डीआईपीपी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत अभी तक कुछ गिने-चुने क्षेत्रों के प्रति ही निवेशकों का उत्साह है. स्टील, इलेक्ट्रिकल स्विचगेयर और कृषि से संबंधित मशीन टूल्स के प्रति उनकी उदासीनता बरकरार है. इन आंकड़ों से ज़ाहिर होता है कि निवेशकों की रुचि उन्हीं क्षेत्रों में है, जिनकी स्थिति भारत में पहले से मज़बूत थी. अगर भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है और मेक इन इंडिया के तहत रोज़गार के अवसर पैदा करने हैं, तो उसे कृषि से जुड़े उद्योगों के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों में भी निवेश को आकर्षित करना होगा. उसके बाद ही देश की बड़ी आबादी को मेक इन इंडिया का लाभ दिया जा सकता है. इसमें कोई शक नहीं कि मेक इन इंडिया में विदेशी निर्माताओं के सामने 10 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है, वह असंभव नहीं है. विदेशी कंपनियां इसी नीयत से इसमें रुचि भी दिखा रही हैं.

उधर चीन में आर्थिक संकट गहरा रहा है और वह अपनी मुद्रा युआन का अवमूल्यन दिया है. इस वजह से चीन के शेयर बाजार सहित दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है. इस वजह से शेयर बाज़ार में निवेशकों की रुचि कम हो रही है. ग़ौरतलब है कि वैश्विक निर्यात में चीन की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है. इस स्थिति को बाज़ार विशेषज्ञ भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ अर्थशास्त्री चीन की ही मिसाल देते हुए इस दिशा में फूंक-फूंक कर क़दम बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध का हवाला देते हुए अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला लिखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी विकासशील देश को अपनी आधुनिक तकनीक हस्तांतरित नहीं करती हैं. तकनीक हस्तांतरण के लिए इन कंपनियों पर दबाव बनाना पड़ता है. ज़ाहिर है, अगर तकनीक का हस्तांतरण नहीं होगा, तो इसका मतलब यह कि मेक इन इंडिया कुछ विदेशी कंपनियों के दायरे में सिमट कर रह जाएगा. चीन की विकास दर में आ रही गिरावट के पीछे उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता को बताया जा रहा है. ऐसे में, भारत को तकनीक के विकास के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक ज़ोर देना चाहिए और कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए. बहरहाल, मेक इन इंडिया अभियान में अब तक की प्रगति देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनने के लिए अभी काफी लंबा रास्ता तय करना बाकी है.

सोलर पावर: लक्ष्य हिमालयी, चाल कछुए की

भारत ने अपनी सोलर पावर यात्रा महत्वाकांक्षी जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के तहत 2010 में शुरू की. मोदी सरकार ने जून 2015 में वर्ष 2022 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पांच गुना बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट करने की योजना को मंजूरी दी. सौर ऊर्जा को तीन घटकों से जोड़ा गया है. पहला बड़े ग्रिड, दूसरा छोटे ग्रिड और तीसरा ऑफ ग्रिड. इनमें पहले काम को छोड़कर दूसरे और तीसरे का क्रियान्वयन गैर-पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय कर रहा है. फिलहाल बड़े ग्रिड पर ज़्यादा काम हो रहा है. आने वाले समय में ऑफ ग्रिड पर ज़्यादा काम होने की संभावना है. दरअसल, जेएनएनएसएम के तहत एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, जो बड़े निवेश और उपकरणों की उपलब्धता के बिना संभव नहीं है.

भारत की मौजूदा सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता केवल 4,060 मेगावाट है. मोदी सरकार की इस पहल को छह लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है. हर साल औसतन 15 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करके ही मिशन में निर्धारत लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है. बीते एक साल में सौर ऊर्जा के संबंध में सरकार और निजी क्षेत्रों की ओर से घोषणाएं तो बहुत हुईं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उतना काम नहीं दिख रहा. सरकारी सूत्रों की मानें, तो अब तक सरकार को लगभग 85 हज़ार मेगावाट के सोलर पावर प्रपोजल मिल चुके हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सोलर पावर से एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करना है. नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2014 तक सौर ऊर्जा की कुल क्षमता 2,631.9 मेगावाट थी, जो 13 जुलाई 2015 तक सिर्फ़ 1,464.7 मेगावाट बढ़कर 4,096.6 तक पहुंची है. चिंताजनक बात यह भी है कि 2014-15 के दौरान तेलंगाना और त्रिपुरा के अलावा अन्य किसी राज्य के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है. कई राज्यों, जिनमें बिहार प्रमुख है, में एक भी सौर परियोजना की शुरुआत नहीं हुई है.

वर्ष 2014 में राजस्थान सरकार ने 26 हजार मेगावाट की संचयी क्षमता के साथ सौर पार्क विकसित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए. तमिलनाडु सरकार और अडानी पावर लिमिटेड ने रामनाथपुरम ज़िले में 200 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने के लिए ऊर्जा खरीद समझौते (पीपीए) पर जून 2015 में हस्ताक्षर किए. मध्य प्रदेश सरकार ने 750 मेगावॉट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की रीवा ज़िले की गढ़ तहसील में स्थापना के लिए संयुक्त उपक्रम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. केंद्र सरकार इस संयंत्र की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपये मुहैया कराएगी. कर्नाटक सरकार ने सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए निविदा निकाली है, जिसके तहत तीन मेगावाट से ऊपर के सोलर पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए जाने हैं. डॉयचे बैंक इंडिया 2020: यूटिलिटी एंड रिन्यूएबल नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी क्षेत्रों ने थर्मल पावर के बजाय सोलर पावर की ओर अपनी रुचि बढ़ा दी है. बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी एनटीपीसी के साथ-साथ अडानी और रिलायंस पावर भी आने वाले दो-तीन सालों में सोलर पावर पर बड़ा निवेश कर सकती हैं.

कृषि से जुड़े 54 प्रतिशत कामगारों का कौशल विकास कैसे होगा

स्किल इंडिया सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. यह योजना पहले से चली आ रही है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है और इसमें कई सारी योजनाएं को भी शामिल किया है. इस मंत्रालय का नाम है, कौशल विकास एवं उद्यमिता. स्किल इंडिया के तहत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है. आइए जानते हैं कि इसकी मौजूदा स्थिति क्या है?

नए मंत्रालय ने 35 वर्ष तक के 24 लाख युवाओं के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है, लेकिन प्रत्येक वर्ष 1.2 करोड़ लोगों को नौकरी की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारा देश युवाओं का है और यहां 65 प्रतिशत लोग 35 साल से कम उम्र के हैं. दुनिया में सबसे अधिक युवा हमारे देश में हैं. आज पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत को एक कुशल कार्यबल की ज़रूरत है. किसी समय हमें अच्छे ड्राइवर की आवश्यकता होती है, लेकिन वह नहीं मिलता. कभी हमें एक अच्छे प्लंबर की ज़रूरत होती है, लेकिन वह नहीं मिलता. फिलहाल, दस लाख रोज़गार की आवश्यकता हर महीने है और यह संख्या प्रत्येक वर्ष उत्पन्न हो रही है. मोदी ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में जान फूंक दी है और उसे 24 लाख लोगों को हुनर सिखाने का काम सौंपा है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई थी. अर्थव्यवस्था और प्रत्येक वर्ष 1.2 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) 25 वर्ष से कम 23.1 करोड़ युवाओं का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था. लेकिन, भारत की असली कौशल परीक्षा खेती-किसानी से जुड़े 54 प्रतिशत कामगारों को लेकर है.

ऐसे कब तक बन पाएगा स्वच्छ भारत

प्रधानमंत्री मोदी ने दो अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान लांच किया था, जिसके तहत उन्होंने आह्वान किया था कि जनता देश को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी निभाए. शुरू-शुरू में लोगों ने इसमें सहयोग भी किया, लेकिन बाद में उनका उत्साह कम होने लगा. बहरहाल, इस अभियान का मकसद खुले में शौच की आदत और मैला ढोने का प्रथा को समाप्त करना तथा शौचालयों का निर्माण करना था. प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण में कहा था कि देश को मंदिर से अधिक शौचालय की आवश्यकता है. लिहाज़ा शौचालय स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम हिस्सा है. वर्ष 2019 तक खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक, वर्ष 2014-15 में 58.56 लाख शौचालय बनवाए गए, जो कि वर्ष 2013-14 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक हैं. ज़ाहिर है, यह सरकारी दावा है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) स्वच्छ भारत अभियान पर अपनी रिपोर्ट इस साल अक्टूबर में जारी करेगा. यह सही है कि वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान देश में शौचालय निर्माण में वृद्धि हुई है, लेकिन वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान इस गति से कहीं अधिक काम हुआ था.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अभी भी देश की कम से कम 55 प्रतिशत आबादी के पास शौचालय नहीं है. मैला ढोने की प्रथा अब तक जारी है, जिसे ख़त्म करना स्वच्छ भारत अभियान का एक बड़ा लक्ष्य था. जिस गति से काम हो रहा है, उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि तय समय सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्य शायद ही पूरा किया जा सकेगा. शौचालय निर्माण से इतर यदि सिर्फ़ स्वच्छता अभियान की बात करें, तो शुरू में प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक ने सड़क पर उतर कर झाड़ू लगाई थी. मीडिया में इसका ज़ोर-शोर से प्रचार प्रसार भी हुआ. लेकिन खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का अगर आप दौरा कर लें, तो इस अभियान की सत्यता मालूम हो जाएगी. ऐसे में, बाकी सांसदों के क्षेत्रों की बात करना भी बेमानी है. लेकिन, यह भी ज़रूरी है कि ऐसे अभियानों में जनता खुद आगे बढ़कर आए. सरकार भी ऐसे प्रयास करे, जिनसे इस अभियान में जन-सहभागिता सुनिश्चित हो.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

- **सरकार का लक्ष्य: वर्ष 2022 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 1,00,000 मेगावाट करना. एक साल में 85 हज़ार मेगावाट के सोलर पावर प्रस्ताव प्राप्त.**
- **13 जुलाई 2015 तक सौर ऊर्जा क्षमता 4,096.648 मेगावाट.**
- **हर साल 15,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन की ज़रूरत.**
- **एक साल में केवल 1,464.7442 मेगावाट की बढ़ोत्तरी.**
- **छह लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता.**
- **किसान और मज़दूर के रूप में खेतों में काम करने वालों की आबादी 54 प्रतिशत है.**
- **कौशल विकास न होने के कारण बड़ी संख्या में लोग कृषि मज़दूर बनने को मजबूर हैं.**
- **केवल दो प्रतिशत (90 लाख) भारतीय कामगार प्रशिक्षित हैं.**

अब तक कितने शौचालय बने

वर्ष	घर, जिनमें शौचालय बने
2008-09	1,12,65,882
2009-10	1,24,07,778
2010-11	1,22,43,731
2011-12	87,98,864
2012-13	45,59,162
2013-14	49,76,294
2014-15	58,55,666

(स्रोत: फैक्टचेकर डॉट इन-जो लोकसभा में दिए गए जवाब पर आधारित है.)

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 07 अंक 27
दिल्ली, 07 सितंबर-13 सितंबर 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के - 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को संसद में दिए गए अपने पहले बजट भाषण में अल्पसंख्यकों के लिए उस्ताद नामक योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं एवं व्यवसाय को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक बनाना और इस संबंध में अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित करना था. इसके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने देशी एवं विदेशी बाज़ार और एक ई–बिजनेस पोर्टल उपलब्ध कराने का भी वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका.

प्रधानमंत्री का खाता-बही

पृष्ठ 2 का शेष

योजना नहीं, स्थानीय नेतृत्व से बनेगा आदर्श ग्राम

11 अक्टूबर 2014 को आदर्श ग्राम योजना शुरू करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर 800 सांसद वर्ष 2019 तक तीन गांवों का विकास करेंगे, तो देश के 2,500 गांवों का विकास हो जाएगा. ग़ौर करने वाली बात यह है कि देश में क़रीब छह लाख गांव हैं. यदि पांच साल में 2,500 गांव आदर्श ग्राम बनते हैं, तो छह लाख गांवों को आदर्श ग्राम बनने में कितने साल लगेंगे? वैसे 11 अक्टूबर 2016 से पहले इस योजना की समीक्षा और इसे सफल या असफल बताना थोड़ी जल्दबाजी होगी. फिर भी मोटे तौर पर दस महीनों के दौरान इस योजना पर हुए कामों की समीक्षा की जा सकती है. दस माह पुरानी इस योजना में अब तक गिने–चुने गांव ही ऐसे मिले हैं, जिन्हें मोदी सरकार की सालाना प्रगति पुस्तक–संवाद में जगह दी गई है. खुद

सांसद, जिन्होंने अब तक गांव का चयन नहीं किया

लोकसभा

कुल सांसद-543

गांव का चयन न करने वाले सांसद-44

राज्यसभा

कुल सांसद-247

गांव का चयन न करने वाले सांसद-54

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गए गांव जयापुर में निश्चित तौर पर काम हो रहे हैं और वहां विकास की रोशनी पहुंचनी शुरू हो गई है. लेकिन, बाकी सात सौ गांवों की हालत भी जयापुर जैसी हो गई है, कहना ग़लत होगा. सरकारी तौर पर गांवों में विकास के कार्य अगस्त 2015 से शुरू होने थे और 2016 के अंत तक पूरे किए जाने हैं. सरकारी वेबसाइट के मुताबिक, योजना की घोषणा के दस महीने बाद भी क़रीब सौ सांसद ऐसे हैं, जिन्होंने गांव गोद नहीं लिया. लोकसभा के 543 में से 44 और राज्यसभा के 247 में से 54 सांसदों ने अब तक गांव का चयन नहीं किया है.

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस योजना के लिए सांसदों को अलग से पैसा नहीं दिया गया है. इसके लिए उन्हें अपनी सांसद निधि खर्च करनी पड़ रही है. सवाल यह है कि यदि वह एक गांव के विकास पर ही पूरी सांसद निधि खर्च कर देगा, तो अपने संसदीय क्षेत्र के बाकी सैकड़ों गांवों के लिए पैसा कहां से लाएगा? सपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने जिस गांव को आदर्श बनाने के लिए चुना था, उसे वापस कर दिया. उन्होंने कहा कि यह योजना तो गांवों में झगड़ा करा देगी. विकास होना है, तो सभी गांवों का हो. दूसरे, योजना में पैसा तो है नहीं, विकास कहां से होगा? सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है कि विभिन्न मंत्रालयों की पहले से चली आ रही योजनाओं का कुछ हिस्सा इन आदर्श ग्रामों को दे दिया जाए. गांवों के लिए अधिकतर योजनाएं यूपीए सरकार की हैं, जो पहले से जारी हैं. दरअसल, आदर्श ग्राम योजना एक आदर्शवादी योजना है, जिसमें व्यक्तिगत विकास, मानवीय विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास, बुनियादी सहूलियतें, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर शासन जैसे मुद्दे शामिल हैं. ये सारे मुद्दे निश्चित तौर पर सराहनीय हैं और अगर ये सचमुच लागू हो जाएं, तो हमारे गांव आदर्श ग्राम से बढ़कर गांधी जी के रामराज्य वाली कल्पना साकार कर उठेंगे.

प्रधानमंत्री जनधन योजना : 46 प्रतिशत खातों में एक पैसा नहीं

जनधन योजना के तहत खुले खातों की स्थिति

बैंक	खातों की संख्या	रूपे डेबिट काड्र्स की संख्या	खाते में बैलेंस	जीरो बैलेंस खातों का प्रतिशत
सरकारी बैंक	136.4	125.4	1772731.2	46
ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक	31.1	22.7	36845.6	49
निजी बैंक	7	6.2	10750.1	46
कुल	174.5	154.3	220326.8	46

स्रोत : वित्त मंत्रालय. सभी आंकड़े मिलियन में हैं. (एक मिलियन = दस लाख). यह आंकड़ा 5 अगस्त 2015 तक का है.

भारत सरकार ने 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच जनधन योजना के तहत 15 करोड़ नए खाते खोले. आज देश के 95 प्रतिशत लोग बैंक से जुड़ गए हैं. इन 15 करोड़ खातों में ग़रीब लोगों ने 15,800 करोड़ रुपये जमा कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि इन 15 करोड़ में से आधे खातों में एक पैसा नहीं है. जनधन योजना के तहत एक ही दिन में डेढ़ करोड़ खाते खोले गए. सरकार ने जनधन योजना को वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूजन) की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण क़दम बताया है. सरकार चाहती है कि उसकी ओर से मुहैय्या कराई जाने वाली वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे. इसके साथ ही जनधन खाताधारक को एक लाख रुपये का मुफ्त दुर्घटना बीमा का प्रावधान है.

बीमा और पेंशन: कई अनसुलझे सवाल

बीमा और पेंशन ऐसे विषय हैं, जिन पर विस्तार से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बीमा की असलियत पॉलिसी के

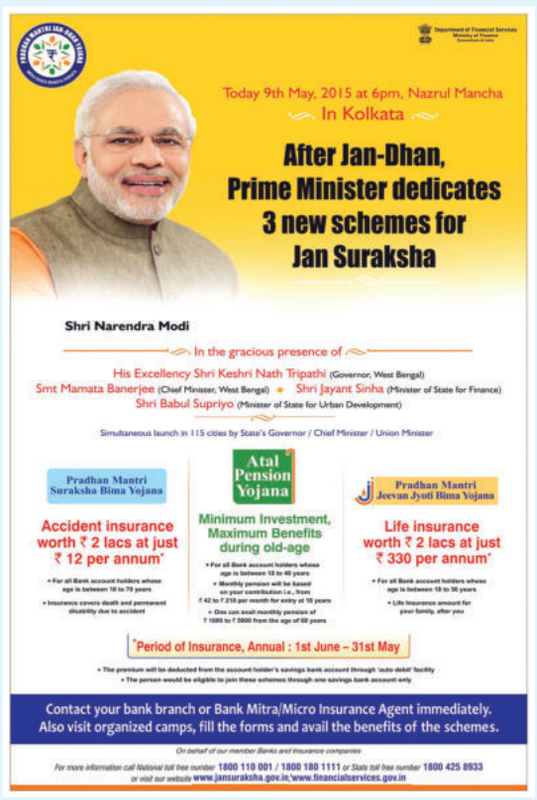

विवरण में होती है, न कि प्रीमियम में. वहीं दूसरी तरफ़ पेंशन वृद्धावस्था का एकमात्र सहारा है, लेकिन भारत में बीमा लगभग भगवान भरोसे ही है. अमेरिका में ओबामा हेल्थ केयर बीमा पर भले ही बहस होती रही हो, लेकिन भारत में जो बीमा योजनाएं सरकार लॉन्च करती है, उन्हें लेकर राजनीतिक दल चर्चा तक नहीं करते. कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना मोदी सरकार ने लॉन्च की. आइए, जानते हैं इन योजनाओं की हक़ीक़त.

अटल पेंशन योजना : इसके तहत आप एक हजार से पांच हजार की सालाना किस्त देकर एक हज़ार से लेकर पांच हज़ार रुपये तक की पेंशन पा सकते हैं. सरकार के अंशदान का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो आयकर दाता नहीं होंगे. इस योजना का सारा काम बैंक के ज़रिये होगा. क्या बीमा क्षेत्र को सहारा देने के लिए बैंकों के बने–बनाए ढांचे का इस्तेमाल किया जा रहा है? यह योजना 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए है. 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों को इससे क्यों बाहर कर दिया गया? वरिष्ठ नागरिक भी इसमें शामिल नहीं हैं. लोगों का मानना है कि अटल पेंशन योजना के तहत वही पैसा आपको साठ साल बाद मिलेगा, जो आपने जमा किया है. यही नहीं, जितने लोग बीमा लेंगे, उनमें मरने वालों की संख्या बहुत कम होगी और ज़्यादातर लोग बच जाएंगे. ऐसे में, प्रीमियम राशि बैंकों की जेब में चली जाएगी.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना : इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये है. इसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति के विकलांग होने या मृत्यु पर घटना के 30 दिनों के अंदर दावा (क्लेम) करना होगा. दावे के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है. यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में बीमार हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होते. ऐसे में, व्यक्ति की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम कराना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करना एक मुश्किल काम है. इसलिए ऐसे बीमा का क्लेम हासिल करना टेढ़ी खीर साबित होगा.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : 330 रुपये सालाना प्रीमियम वाली इस योजना का लाभ 20 करोड़ से ज़्यादा लोग नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 19 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, जिनकी आयु 50 साल से ज़्यादा है और इस योजना में प्रावधान है कि केवल 18 से 50 साल तक के लोग ही इससे जुड़ सकते हैं. दूसरी तरफ़ इस योजना में बीमा कवर 55 साल तक ही मिलेगा. यानी बीमाधारक की मृत्यु यदि 55 साल की उम्र तक होती है, तभी उसके नामित को दो लाख रुपये मिलेंगे. जबकि बाज़ार में मौजूद अन्य कंपनियों की पॉलिसी में 100 साल तक बीमा का लाभ लिया जा सकता है.

अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं की मौजूदा स्थिति

अब एक नज़र अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर डालते हैं.

हमारी धरोहर : इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्गों की पारंपरिक कलाओं एवं व्यवसाय को सुरक्षित करना और इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है. इस योजना के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, यह अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया. आठ जुलाई 2014 को राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्लाह ने बताया था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) के तहत देश भर में अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 117 आईटीआई, 44 पॉलिटेक्निक, 645 छात्रावास, 1,092 स्कूल भवन और 20,656 अतिरिक्त कक्षाएं बनाने की स्वीकृति दी गई है, लेकिन आज सितंबर 2015 में जब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस दिशा में कितना काम हुआ, तो हमें मंत्रालय की ओर से कोई जानकारी नहीं मिलती.

मौलाना आज़ाद सेहत योजना : मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए एक नई योजना मौलाना आज़ाद सेहत योजना नाम से शुरू की थी. इससे अल्पसंख्यक वर्ग कितना लाभांवित हुआ, अभी तक किसी को नहीं मालूम.

पढ़ो प्रदेश: यूपीए सरकार के दौरान 2013–14 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन उस समय यह योजना लागू नहीं हो सकी थी. 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इसे लागू किया गया. वर्ष 2014–15 में इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से चार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इस योजना से अब तक सिर्फ़ 573 अल्पसंख्यक विद्यार्थी लाभांवित हुए.

सीखो और कमाओ : अल्पसंख्यकों की हुनरमंदी के विकास के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीखो और कमाओ नामक एक योजना शुरू की है. इसके तहत मंत्रालय ने वर्ष 2014–15 में 34.67 करोड़ रुपये जारी किए और प्रशिक्षित लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां दिलवाईं. इसके अलावा मंत्रालय ने अपने अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं आर्थिक निगम (एनएमडीएफसी) और मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर कराकर अल्पसंख्यकों के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण की व्यवस्था की, जिसके तहत दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश में 2,515 अल्पसंख्यक युवाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया.

उस्ताद : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को संसद में दिए गए अपने पहले बजट भाषण में अल्पसंख्यकों के लिए उस्ताद नामक योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं एवं व्यवसाय को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक बनाना और इस संबंध में अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित करना था. इसके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने देशी एवं विदेशी बाज़ार और एक ई–बिजनेस पोर्टल उपलब्ध कराने का भी वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका.

नई रोशनी : अल्पसंख्यक महिलाओं की नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 2012–13 में नई रोशनी नामक एक योजना शुरू की थी. इसके तहत अल्पसंख्यक महिलाओं को साफ़–सफ़ाई, बच्चों की बीमारियां एवं उनका उपचार, महिलाओं से संबंधित समस्याएं, जन वितरण प्रणाली, लाइफ स्किल्स आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है.

नई मंज़िल : अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्लाह ने आठ अगस्त, 2015 को बिहार की राजधानी पटना में नई मंज़िल नामक एक नई योजना शुरू की. इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को शिक्षित बनाने के साथ–साथ उन्हें अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है. ■

(साथ में चौथी दुनिया टीम)

feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधानसभा चुनाव 2015

कांग्रेस के लिए सुनहरा मौका है

कांग्रेस अध्यक्ष घोषित होने से पहले अपनी नेतृत्व क्षमता को सिद्ध करने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के रूप में राहुल गांधी के पास सुनहरा अवसर है. यदि राहुल गांधी इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और अपनी सारी ताकत इसमें झोंकते हैं तो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा हो सकता है क्योंकि बिहार का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अनुकूल है. यदि कांग्रेस पार्टी सही फैसले करती है तो राहुल गांधी का राजनीतिक कद बढ़ेगा और वह देश के सबसे ताकतवर विपक्षी नेता बन सकते हैं. सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति कांग्रेस के अनुकूल क्यों हैं और राहुल गांधी कैसे इस अवसर को नतीजे में तब्दील कर सकते हैं?

मनीष कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव–2015 कांग्रेस पाटी के लिए एक सुनहरा अवसर है. कई दशकों तक बिहार में कांग्रेस पार्टी का एकक्षत्र राज रहा, लेकिन वी पी सिंह की राजनीति ने बिहार से कांग्रेस को ऐसा उखाड़ फेंका कि पार्टी हाशिए पर चली गई. चुनाव दर चुनाव बिहार में कांग्रेस पार्टी सिमटती चली गई. कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई कि पिछले विधानसभा चुनाव में वह 243 सीटों में से केवल 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी. जबकि राहुल गांधी ने उस दौरान काफी मेहनत की थी. साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी एक साल पहले से ही तैयारी में जुट गये थे. उन्होंने जगह–जगह जाकर, प्रचार–प्रसार करके पार्टी संगठन को मजबूत किया था. लेकिन कांग्रेस की हार के साथ ही राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे थे. इस बार बिहार में कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक स्थिति में है जहां से वह पार्टी को नया जीवन दे सकती है, एक ताकत बनकर उभर सकती है. चुनावी नतीजे आने के बाद निर्णायक भूमिका में आ सकती है. लेकिन राजनीति में सिर्फ अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं होता है, यहां अवसर को नतीजे में तब्दील करना ही असली चुनौती होती है.

सीटों का बंटवारा पहले से तय था

बिहार में कांग्रेस पार्टी लालू यादव और नीतीश कुमार के महा–गठबंधन के साथ है. बिहार विधानसभा चुनाव–2015 में कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है. ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह आश्चर्य का विषय है कि लालू यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस को 40 सीट देने पर सहमत कैसे हो गए. ज्यादातर विश्लेषक यह मान रहे थे कि महा–गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक 20 सीटें मिलेंगी. लेकिन राहुल गांधी अपनी कुशलता के बल पर 40 सीटें प्राप्त करने में सफल रहे. हक़ीकत यह है कि वह लालू यादव के साथ गठबंधन में शामिल होने के पक्षधर नहीं थे. उनकी बात नीतीश कुमार से हो रही थी. दिल्ली में नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत में यह तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी, जनता दल (युनाइटेड) के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. जिसमें कांग्रेस कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच यह करार हो चुका था.

लेकिन, जब नीतीश कुमार और लालू यादव ने जनता परिवार के तहत एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया तो चुनावी समीकरण बदल गये. राहुल गांधी 50 सीटों की अपनी मांग पर डंटे रहे. इसी बीच कई समाचार चैनलों पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे आने शुरु हो गए. हर सर्वे का नतीजा यह था कि लालू यादव और नीतीश कुमार बिना कांग्रेस की मदद के बगैर भाजपा गठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे. इन चुनावी सर्वे की वजह से राहुल गांधी की दावेदारी को बल मिला. जब बातचीत चल ही रही थी तब बिहार में विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा गठबंधन ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की. सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव ने भले ही इसे महत्वहीन करार दिया, लेकिन परिणामों से उन्हें भाजपा गठबंधन की ताकत अंदाजा हो गया. जब सीटों के बंटवारे की बातचीत अंतिम दौर में पहुंची, तब भी राहुल गांधी अपनी दावेदारी पर कायम रहे. नीतीश कुमार भी लालू यादव को यह समझाने में सफल रहे कि कांग्रेस की मदद के बगैर भाजपा गठबंधन को हराना मुश्किल है. इन्हीं वजहों से महा–गठबंधन के सीट बंटवारे में लालू यादव को 100, नीतीश कुमार का 100 और कांग्रेस को 40 सीटें मिलीं. अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इन 40 सीटों के साथ क्या करेंगी? क्या इस विधानसभा चुनाव के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस कम–बैक(वापसी) करने में सफल होंगे? क्या वह इस सुनहरे अवसर का फायदा उठा पाएगी या फिर गंवा देगी?

बिहार कांग्रेस के पास फंड की कमी

बिहार–कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं. लेकिन दिल्ली से उन्हें वैसी मदद नहीं मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए. पटना में तैनात पार्टी संगठन के अधिकारियों की स्थिति ऐसी है कि उन्हें हर काम के लिए फंड की कमी का सामना करना पड़ता है. वैसे, यदि कोई यह कहे कि कांग्रेस के पास पैसे की कमी है, तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा. लेकिन हक़ीकत यह है कि कांग्रेस की बिहार इकाई पैसे की कमी की समस्या से जूझ रही है. संगठन के कई पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है वे अपनी जेब से पैसे लगा सकें. फंड की कमी की वजह से कांग्रेस पार्टी प्रचार–प्रसार में सबसे पीछे है. यहां तक कि पप्पू यादव का प्रचार–प्रसार भी कांग्रेस से बेहतर है. जबकि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (युनाईटेड), राष्ट्रीय जनता दल, यहां तक कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के कोने–कोने में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगा चुकी है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी का न तो कोई पोस्टर है, न राहुल का कोई होर्डिंग और न ही सोनिया गांधी की तस्वीर कहीं दिखाई देती है. सोनिया गांधी की जो तस्वीर नज़र भी आई, वह भी स्वाभिमान रैली के दौरान लालू और नीतीश के साथ थी. लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि महा–गठबंधन की इस रैली के होर्डिंग्स से राहुल गांधी की तस्वीर गायब है. अखबारों में भी कांग्रेस पार्टी को जगह नहीं मिल रही है.

चुनाव प्रचार में पिछड़ी कांग्रेस

लोकसभा चुनाव के बाद प्रचार–प्रसार का महत्व हर राजनीतिक दल को समझ में आ चुका है. चुनाव की घोषणा के बाद वैसे भी सारे होर्डिंग और बैनरों को उतारना पड़ता है. चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले जहां अन्य पार्टियों ने प्रचार–प्रसार कर अपने पक्ष में माहौल बनाने का सफल प्रयास किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अलग–अलग इलाकों में रैलियां कीं और पूरे बिहार में होर्डिंग, बैनर और रेडियो के जरिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया. वहीं, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए चुनाव प्रचार की तर्ज पर बिहार में प्रचार–प्रसार में जुटे हैं. बाकी पार्टियों की तुलना में कांग्रेस पार्टी का प्रचार–प्रसार नगण्य है, शून्य है. हैरानी तो इस बात की है कि राहुल गांधी देश के अलग–अलग इलाकों में जा रहे हैं लेकिन जहां सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है वहां उन्होंने अब तक एक भी रैली नहीं की. अब यह पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी किसी रणनीति के तहत प्रचार–प्रसार नहीं कर रही है या फिर दिल्ली में बैठे कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बिहार में दूसरी पार्टियों को वाक–ओवर देने का फैसला कर लिया है. कांग्रेस पार्टी की यदि स्वयं को बिहार में पुनर्जिवित करने की योजना है तो यह कहना पड़ेगा कि पहले राउंड में कांग्रेस ने यह अवसर गंवा दिया है.

सही उम्मीदवारों के चयन की चुनौती

कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह कि वे 40 उम्मीदवार कौन होंगे, जिनके कंधों पर पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी. समस्या यह है कि पार्टी ने पिछले कई सालों में बिहार में किसी नेता को तैयार नहीं किया. लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, नन्दकिशोर यादव, शाहनवाज हुसैन आदि की तरह कांग्रेस में एक भी बड़ा नेता नहीं है. बिहार कांग्रेस में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसे बिहार के हर इलाके के लोग जानते हों. कांग्रेस का बिहार में अध्यक्ष कौन है, या पांच बड़े नेता कौन हैं, यह आम जनता को पता ही नहीं है. जो पुराने नेता हैं वे या तो सक्रिय नहीं है या फिर सिर्फ चुनाव के समय ही अवतरित होते हैं. चुनाव के समय बिहार कांग्रेस में एक और अनोखी बात होती है, जीतने वाले उम्मीदवार की दुहाई देकर ऐसे पैसे वालों को टिकट मिल जाता है जिनके बारे में इलाके के लोग शुरूआत से ही जानते हैं कि यह जीतने वाला उम्मीदवार नहीं है. अब यह पता नहीं कि जिन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है उन्हें कांग्रेस के रणनीतिकार चुनाव से पहले किस दिव्य–दृष्टि से जीतने वाला मानकर टिकट दे देते हैं. कांग्रेस के युवा नेता दबी ज़बान से बताते हैं कि ज्यादातर टिकट बेच दिए जाते हैं. कांग्रेस पार्टी के कुछ महान नेता पैसे लेकर टिकट दिलवाने में एजेंट का काम करते हैं. ऐसी ही शिकायत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मिली थी.

पुरानी गलतियों से सीख

राहुल गांधी बिहार में पिछले दस सालों से काम कर रहे हैं. उन्होंने बिहार में युवाओं को जोड़ने का काम किया. उन्होंने राज्य के कई इलाकों का दौरा भी किया, कई जिलों में संगठन को भी मजबूत किया, लेकिन राहुल गांधी बिहार के नई पीढ़ी के नेताओं को ग्रूम करने में विफल रहे. इसका सबसे बड़ा ख़ामियाजा चुनाव के दौरान के भुगतना पड़ता है. पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने युवाओं को पार्टी से जोड़ा लेकिन टिकट वितरण में युवा नेताओं को तरजीह नहीं दी गई, उनके साथ न्याय नहीं हुआ. कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं घिसे–पिटे पुराने लोगों को टिकट दिया जिन्हें जनता कई साल पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है. इस बार भी शायद ऐसा ही हो क्योंकि इसकी सुगबुगाहट होने लगी है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब से 40 सीटों की घोषणा हुई है कई इलाकों में पुराने कांग्रेसी नेता फिर से सक्रिय हो गए हैं. पैसे वाले अमीर उम्मीदवारों नें दिल्ली के चक्कर लगाने शुरु कर दिये हैं. कांग्रेस के कई युवा नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी निराश हैं कि जिन लोगों ने पिछले कई सालों से पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, वे टिकट के लिए अपनी दावेदारी पुख्ता करने के लिए दिल्ली में लॉबी और सेटिंग कर रहे हैं. जो गलती कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में की थी, यदि वही गलती इस बार भी हुई तो निश्चित तौर पर नतीजे पिछले चुनाव से बेहतर नहीं होने वाले हैं.

युवा उम्मीदवारों को वरीयता

बिहार में ज्यादातर युवा कांग्रेसी नेता साफ सुथरी छवि वाले, पढ़े–लिखे और वैचारिक दृष्टि से कमिटेड कार्यकर्ता हैं. ज्यादातर युवा वे हैं जो राहुल गांधी के कैंपेन की वजह से पार्टी में हैं. राहुल गांधी से उन्हें बहुत आशाएं हैं. उन्हें बिहार की वास्तविकता की अच्छी समझ है. वे पार्टी की कमियों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, वे भारतीय जनता पार्टी की ताकत और खूबियों को भी बखूबी समझते हैं. लेकिन उनकी शिकायत यह है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. अब तक फैसले दिल्ली में होते रहे हैं. फैसला वे लोग करते हैं जो बिहार की राजनीति की बारीकियों से अनभिज्ञ होते हैं. लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी में भी बदलाव आया है. अब वह आम कार्यकर्ता की बातों को ध्यान से सुनते हैं. इससे कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवा नेताओं का हौसला बढ़ा है. कांग्रेस के युवा नेता बिहार के महा–गठबंधन में 40 सीटें लेने को राहुल गांधी की जीत बताते हैं. लेकिन इसे वास्तविक जीत में बदलने के लिए राहुल गांधी की आगे भी सजग रहना होगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, उन सीटों पर यदि जद(यू) या आरजेडी के डमी उम्मीदवार खड़े हो गए तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी.

युवा मतदाताओं का रुख

वर्तमान में बिहार की राजनीति की हकीकत यह है कि भले ही लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया हो. लेकिन जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक नहीं हैं. आज भी वे एक दूसरे को विरोधी मानते हैं. दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर मतभेद उभरेंगे. दोनों ही पार्टियों के नेता निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और क्षति पहुंचाएंगे. कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर यह है कि वह महा–गठबंधन के आतंरिक विरोधाभास की चपेट से बाहर है. जनता दल (युनाइटेड) के समर्थक हों या राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक, उन्हें कांग्रेस को वोट देने में कोई गुरेज नहीं है. आम जनता भी नए चेहरे को मौका देने के मूड में है. ज्यादातर युवा किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं इसलिए वे अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं. बिहार के युवा मतदाता अब पुराने चेहरों से ऊब चुके हैं. कहने का मतलब यह कि बिहार चुनाव में कांग्रेस के लिए एक अनुकूल स्थिति है. इस चुनाव में न तो यूपीए के कामों की विवेचना होगी और न ही घोटालों की परछाई उन्हें सताएगी, अल्पसंख्यकों का पूरा वोट मिलेगा, लालू यादव और नीतीश कुमार के समर्थकों के वोट भी बिना किसी भीतरघात के उन्हें आसानी से मिल जायेंगे. लेकिन यह तभी संभव है जब कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र की बारीकियों को समझते हुए नए चेहरों और ऊर्जावान युवाओं को मैदान में उतारेगी.

कांग्रेस नेतृत्व की सक्रियता में कमी

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस पार्टी को योजनाबद्ध और प्राफेशनल तरीके से चुनाव लड़ना होगा. सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार को ध्यान में रखकर चुनाव कैंपेन चलाना होगा. बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर परिपक्व है. वह किसी राष्ट्रीय नेता के भाषण को सुनकर वोट नहीं देती है. बिहार की राजनीतिक परिस्थिति कांग्रेस के अनुकूल है, लेकिन यह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी कितना सूझबूझ दिखाती है और इसका फायदा कितना उठाती है. यदि कांग्रेस पार्टी पिछली विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराती है तो यह अवसर शोक में बदल सकता है. राहुल गांधी को इसका नुकसान सबसे ज्यादा होगा. कांग्रेस पार्टी को इन नतीजों का खामियाजा बंगाल और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ेगा. अगर राहुल गांधी बिहार में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राहुल गांधी की 2019 के चुनावों की दावेदारी पुख्ता हो जाएगी, साथ ही उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर उठ रहे सवाल भी समाप्त हो जाएंगे. लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से सक्रियता की कमी नजर आ रही है. लालू और नीतीश की रैली में उपस्थिति दर्ज कराने से कांग्रेस का ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है.

ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को बिहार चुनाव के दूरगामी असर का आभास नहीं है. शायद उन्हें यह पता नहीं है कि बिहार का यह चुनाव, भारत की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव है. नतीजा जो कुछ भी हो, यह भारतीय राजनीति का मील का पत्थर साबित होना वाला है. बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा. और यदि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की तरह ही रहा, तो राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल कांग्रेस के भीतर से ही उठेंगे. साथ ही कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर और बाहर भारतीय जनता पार्टी से मुक़ाबला करने में पहले से ज्यादा कमजोर और असहाय दिखाई देगी.■

manishbph244@gmail.com

लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी में भी बदलाव आया है. अब वह आम कार्यकर्ता की बातों को ध्यान से सुनते हैं. इससे कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवा नेताओं का हौसला बढ़ा है. कांग्रेस के युवा नेता बिहार के महा–गठबंधन में 40 सीटें लेने को राहुल गांधी की जीत बताते हैं. लेकिन इसे वास्तविक जीत में बदलने के लिए राहुल गांधी को आगे भी सजग रहना होगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, उन सीटों पर यदि जद(यू) या आरजेडी के डमी उम्मीदवार खड़े हो गए तो, कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी.

बिहार में चुनाव के दौरान तीखे सामाजिक समीकरण बनते हैं, जो तात्कालिक राजनीतिक विवशताओं के चलते बदलते रहते हैं, तो कुछ एक से अधिक चुनावों में काम करते हैं. बिहार में माय (मुस्लिम–यादव) सबसे पुराना समीकरण है, जो अपनी राजनीतिक प्रकृति में भाजपा विरोधी माना जाता है. यह समीकरण लालू प्रसाद के साथ है और उनकी ताकत का मूल स्रोत भी. 1995 से लेकर अब तक के सारे चुनावों में यह कमोबेश उनकी राजनीति के साथ रहा है. राज्य के मौजूदा राजनीतिक माहौल में यह भाजपा (एनडीए) के लिए बड़ी चुनौती है.

जनगणना के धार्मिक आंकड़े

बिहार चुनाव विशेष बिहार चुनाव

किसका कितना नफा-नुक़सान

सुकांत

जनगणना के धार्मिक आंकड़ों ने बिहार के चुनावी माहौल में नई लहर पैदा कर दी है. हालांकि, दावा किया जा रहा है कि इसका बिहार विधानसभा चुनाव से कोई लेना–देना नहीं है. यह महज एक संयोग है कि बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ पहले इन्हें जारी किया जा रहा है. ये आंकड़े क़रीब पांच साल पहले यानी 2011 की जनगणना में हासिल किए गए थे. चूंकि जनगणना के विविध आंकड़े कई चरणों में जारी होते हैं, लिहाजा इन्हें भी जारी कर दिया गया. यह दावा सहज विश्वास करने योग्य नहीं है. इन आंकड़ों का राजनीतिक उपयोग तय है और फिलहाल यह बिहार में किया जाना है. बिहार की मौजूदा (2011 की जनगणना के हिसाब से) आबादी 10 करोड़ 41 लाख है. कुल आबादी में हिंदू 82.69 प्रतिशत और मुस्लिम 16.87 प्रतिशत हैं. रिपोर्ट के अनुसार, सूबे में इन दस वर्षों (2001–11) में हिंदुओं के मुक़ाबले मुसलमानों की आबादी में बढ़ोत्तरी की रफ्तार अधिक रही और हिंदुओं की तुलना में उनकी आबादी 3.34 प्रतिशत बढ़ी है. पिछली जनगणना (2001) के बाद हिंदुओं की आबादी 24.61 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मुस्लिम आबादी में 27.95 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई. सूबे में ईसाई आबादी में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत सबसे अधिक यानी 143 रहा. वहीं बौद्धों की आबादी में 41.25, जैन समुदाय की आबादी में 17.58 और सिखों की आबादी में 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई.

रिपोर्ट के अनुसार, किशनगंज में मुस्लिम सबसे अधिक हैं. इस ज़िले की कुल जनसंख्या 16.90 लाख है, जिनमें मुस्लिम 11.49 लाख और हिंदू 5.31 लाख हैं. कटिहार की कुल जनसंख्या 30.71 लाख है, जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी 13.65 लाख है. पूर्णिया की जनसंख्या 32.84 लाख है, जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी 12.55 लाख है. अररिया की कुल जनसंख्या 28.11 लाख है, जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी 12.07 लाख है. इसके अलावा पूर्वी चंपारण में 9.90 लाख, दरभंगा में 8.81 लाख, पश्चिमी चंपारण में 8.65 लाख, मधुबनी में 8.18 लाख, मुजफ्फरपुर में 7.45 लाख, सीतामढ़ी में 7.40 लाख और सीवान में 6.06 लाख मुसलमान हैं. जबकि शिवहर, सुपौल, जहानाबाद, अरवल, लखीसराय एवं शेखपुरा में मुस्लिम आबादी लाख से नीचे है. ग़ौरतलब है कि भारत सरकार के पास ये आंकड़े क़रीब डेढ़ साल से तैयार थे. पिछले संसदीय चुनाव के पहले इन्हें जारी होना तय था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसके राजनीतिक निहितार्थ अपने अनुकूल न पाकर ऐसा करने से खुद को रोक लिया. इस साल जनवरी में केंद्र के मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व ने अघोषित कारणों से ऐसा नहीं होने दिया. लगता है, उपयुक्त राजनीतिक मौक़े की तलाश थी और बिहार विधानसभा चुनाव से बेहतर ऐसा अवसर भला क्या होता! धार्मिक समूहों की जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) स्थिति का इस चुनाव में उत्तेजक राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है.

बिहार में चुनाव के दौरान तीखे सामाजिक समीकरण बनते हैं, जो तात्कालिक राजनीतिक विवशताओं के चलते बदलते रहते हैं, तो कुछ एक से अधिक चुनावों में काम करते हैं. बिहार में माय (मुस्लिम–यादव) सबसे पुराना समीकरण है, जो अपनी राजनीतिक प्रकृति में भाजपा विरोधी माना जाता है. यह समीकरण लालू प्रसाद के साथ है और उनकी ताकत का मूल स्रोत भी. 1995 से लेकर अब तक के सारे चुनावों में यह कमोबेश उनकी राजनीति के साथ रहा है. राज्य के मौजूदा राजनीतिक माहौल में यह भाजपा (एनडीए) के लिए बड़ी चुनौती है.

बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 50 से अधिक सीटों पर जीत–हार में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. क़रीब सौ सीटों पर माय उल्लेखनीय ढंग से ताकतवर है. यह राजनीतिक वास्तविकता भाजपा (एनडीए) को कतई रास नहीं आ रही है. हालांकि, अगड़ों का आम समर्थन भाजपा को है, पर उसे माय के समानांतर पिछड़े मतदाताओं की स्पष्ट गोलबंदी चाहिए. गत संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर माय से इतर मतदाताओं की गोलबंदी हुई थी, पर उसमें मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि की बड़ी भूमिका रही थी. इस बार ऐसा नहीं है. निस्संदेह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब भी किसी राजनेता से अधिक है, लेकिन उनके नाम पर पिछड़े सामाजिक समूहों में पिछली बार जैसी गोलबंदी कहीं दिख नहीं रही है. ऐसे में भाजपा को नया हथियार चाहिए. ऐसे में धार्मिक ध्रुवीकरण सबसे आसान और धारदार हथियार हो सकता है, जो जनगणना के धार्मिक आंकड़े उसे सहज उपलब्ध करा रहे हैं. रिपोर्ट बताती है कि पूर्णिया प्रमंडल के चारों ज़िलों (पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार) के साथ–साथ दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान एवं मुजफ्फरपुर में मुस्लिम मतदाताओं का खासा राजनीतिक महत्व रहेगा. भाजपा के चुनावी रणनीतिकार महा–गठबंधन को शिकस्त देने के लिए इस धार्मिक समूह के ख़िलाफ़ आम गोलबंदी की कोशिश करेंगे. सच्चाई यह भी है कि पूर्णिया प्रमंडल भाजपा के लिए सदैव चुनौती भरा रहा है. बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाकर भाजपा वहां अपनी राजनीति कभी परवान चढ़ाती थी, पर 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद उसने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया. अब तो केंद्र में मोदी सरकार के चलते यह मुद्दा उठाना उसके लिए और भी कठिन है.

जनगणना के धार्मिक आंकड़े जारी होने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासनिक कामकाज का अंग बताया है और राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने अब तक कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी. वस्तुत: यह रिपोर्ट राजद प्रमुख की राजनीति को एक साथ कई अवसर देती है. पूर्णिया और सहरसा के साथ–साथ दरभंगा प्रमंडल के विधानसभा क्षेत्रों को लेकर उन्हें नए सिरे से अपनी रणनीति तय करनी होगी. माय को राजनीतिक तौर पर ज़्यादा सार्थक, ज़्यादा धारदार और लाभकारी बनाना होगा. गत संसदीय चुनाव में बिहार ने देखा है कि नरेंद्र मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि के नाम पर किस तरह मंडल के सामाजिक समूहों में भाजपा ने सेंधमारी की. जनगणना के धार्मिक आंकड़े भाजपा को ज़्यादा धारदार और स्थायी हथियार देते हैं. महा–गठबंधन के नेताओं, विशेषकर लालू प्रसाद को इस रणनीति की काट तैयार करनी होगी.

इसी साल जुलाई के पहले हफ्ते में जनगणना के सामाजिक–आर्थिक आंकड़े जारी किए गए थे. उसी के साथ बिहार समेत देश के विभिन्न हिस्सों से जातीय आंकड़े जारी करने की मांग उठने लगी. बिहार में राजद प्रमुख ने इस मांग को लेकर राजभवन तक मार्च किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, धरना दिया, उपवास किया और बिहार बंद का आह्वान भी किया. लालू प्रसाद की इस राजनीतिक सक्रियता के चलते ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अपनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक पृष्ठभूमि की सार्वजनिक तौर पर चर्चा करनी पड़ी. जनगणना के धार्मिक आंकड़े जारी होने से बिहार की चुनावी राजनीति को नया आयाम मिला है, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिलता दिख रहा है. अब देखना यह है कि महा–गठबंधन का नेतृत्व, विशेषकर लालू प्रसाद अपने माय को बचाने के लिए क्या करते हैं? लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती महा–गठबंधन के सामने है, उन्हें मंडल को बचाना है. पिछले संसदीय चुनाव के दौरान उनकी राजनीति धरी की धरी रह गई और मंडलवादी राजनीति के विभिन्न सामाजिक समूह भाजपा की ओर पलायन कर गए. कई दबंग पिछड़ी जातियां उधर चली गईं और अब भी वहीं हैं. अति पिछड़ी जातियों (जिनकी बिहार की आबादी में क़रीब 33 प्रतिशत की हिस्सेदारी है) का भी महत्वपूर्ण हिस्सा भाजपा के साथ चला गया था. लेकिन, इस विधानसभा चुनाव में यह तबका भाजपा के साथ है, ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता. महा–गठबंधन नेतृत्व की चुनावी रणनीति मंडल के सामाजिक समूहों को अपने साथ बांधकर रखने और भाजपा की ओर गए समूहों को वापस लाने की होनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

मिलिए अपने करोड़पति विधायकों से...

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं. पिछले अंक में हमने बताया था कि आपके मौजूदा विधायकों में से आपराधिक छवि के टॉप-20 विधायक कौन हैं? इस बार हम आपको ऐसे विधायकों से मिलवा रहे हैं, जो करोड़पति हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने बिहार विधानसभा 2010 के करोड़पति प्रत्याशियों की रिपोर्ट जारी की थी. इन टॉप-20 करोड़पति विधायकों में से दो ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते समय अपना पैन नंबर नहीं दिया है, जैसे पूर्णिमा यादव और कौशल यादव. इसके अलावा दो अन्य करोड़पति विधायकों मनीष कुमार (धौरैय्या-बांका) और नीता चौधरी (तारापुर-मुंगेर) ने भी संपत्ति के ब्यौरे के साथ अपना पैन नंबर नहीं दिया है. उक्त चारों विधायक जदयू के हैं. बाकी 18 करोड़पति विधायकों ने अपना पैन नंबर ब्यौरे में शामिल किया है. एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, करोड़पति विधायकों की संख्या बिहार के सभी राजनीतिक दलों में अच्छी-खासी है, जिनमें जदयू के 27 (24 फ़ीसद), भाजपा के 12 (13 फ़ीसद), राजद के पांच (23 फ़ीसद) और कांग्रेस के दो विधायक (50 फ़ीसद) शामिल हैं. एडीआर ने जिन टॉप-20 करोड़पति विधायकों को अपनी सूची में शामिल किया है, उनका विवरण निम्नवत है:-

क्रम	विधायक का नाम	विधानसभा क्षेत्र	पार्टी	कुल संपत्ति (रुपये में)
1.	डॉ. फैयाज अहमद	बिस्फी	राजद	15 करोड़
2.	सुरेश शर्मा	मुजफ्फरपुर	भाजपा	22 करोड़
3.	राजू कुमार सिंह	साहेबगंज	जदयू	छह करोड़
4.	सुनील कुमार सिंह	औरंगाबाद	राजद	छह करोड़
5.	गजानंद शाही	बरबीघा	जदयू	पांच करोड़
6.	विजय कुमार सिन्हा	लखीसराय	भाजपा	चार करोड़
7.	वीणा देवी	गाय घाट	भाजपा	चार करोड़
8.	अन्नू शुक्ला	लालगंज	जदयू	तीन करोड़
9.	परवीन अमानुल्लाह	साहेबपुर कमाल	जदयू	दो करोड़
10.	अवधेश कुशवाहा	पिपरा	जदयू	दो करोड़
11.	नरेंद्र कुमार सिंह	मटिहानी	जदयू	दो करोड़
12.	पूर्णिमा यादव	नवादा	जदयू	दो करोड़
13.	कौशल यादव	गोविंदपुर	जदयू	दो करोड़
14.	राजीव रंजन	इस्लामपुर	जदयू	दो करोड़
15.	ललित कुमार यादव	दरभंगा ग्रामीण	राजद	दो करोड़
16.	सुरेंद्र प्रसाद यादव	बेलागंज	राजद	दो करोड़
17.	रेनू देवी	नवी नगर	जदयू	दो करोड़
18.	दिलीप वर्मा	सिकटा	आईएनडी	दो करोड़
19.	सुनील कुमार	बिहार शरीफ	जदयू	दो करोड़
20.	डॉ. मुहम्मद जावेद	किशनगंज	कांग्रेस	एक करोड़

कैमूरांचल

बेटों के भरोसे विरासत बचाने की कवायद

चौथी दुनिया ब्यूरो

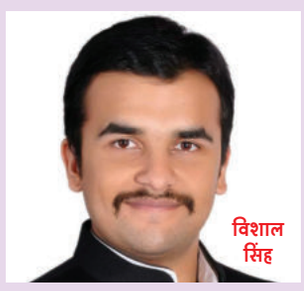

विधानसभा चुनाव की धमक सुनाई देते ही राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र कैमूरांचल के दिग्गजों पर जा टिकी है, जो अपनी राजनीति की दूसरी पारी अपने बेटों के सहारे शुरू कर विरासत बचाने में जुटे हैं. कुछ राजनीतिक दिग्गजों के बेटे बगावत की राह पकड़ कर विरासत हथियाने का खेल भी खेल रहे हैं. इस नज़रिये से कैमूरांचल की कुल 11 विधानसभा सीटों में से रामगढ़, चैनपुर, मोहनियां, काराकाट एवं दिनारा की सीटें अति महत्वपूर्ण हैं. मोहनियां सीट 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद छेदी पासवान ने खाली की थी, तब वहां से वह जदयू के विधायक हुआ करते थे. उपचुनाव में सांसद की मंशा भाजपा के टिकट पर अपने परिवार के किसी सदस्य को लड़ाने की थी, लेकिन ऐन वक्त पर राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए निरंजन राम ने बाजी मार ली और भाजपा नेतृत्व ने निरंजन राम को मैदान में उतार दिया, जिससे छेदी पासवान को मन मसोस कर रह जाना पड़ा. हालांकि, उनके भतीजे चंद्रशेखर पासवान ने घर में ही बगावत करके जदयू का दामन थामा और उन्हें मोहनियां से टिकट भी मिला, लेकिन चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को बड़े अंतर से जीत हासिल हुई. हालांकि, चंद्रशेखर प्रसाद को लगभग 42 हज़ार मत मिले, जो जदयू का एक बेहतर रिकॉर्ड है. इस चुनाव के बाद सांसद पुत्र रवि पासवान ने राजनीति में सक्रियता दिखाई और अपने सांसद पिता के साथ–साथ उनकी तस्वीर भी बैनरों–पोस्टरों पर दिखने लगी. उनका निशाना चेनारी विधानसभा सीट है, जहां प्रदेश रालोसपा के कार्यकारी अध्यक्ष ललन पासवान एनडीए प्रत्याशी के रूप में पहले से ही ताल ठोंक रहे हैं. देखना यह है कि चेनारी विधानसभा सीट पर सांसद की दावेदारी मजबूत पड़ती है या गठबंधन धर्म का पालन होता है. ग़ौरतलब है कि ललन पासवान इस सीट से दो बार विधायक रहे हैं और दो बार काफी कम अंतर से चुनाव हारे हैं. दूसरी महत्वपूर्ण सीट रामगढ़ है, जहां राजद के कद्दावर नेता एवं पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद के विश्वसनीय साथी जगदा बाबू की पकड़ खासी मजबूत बताई जाती है. उनके बेटे सुधाकर सिंह ने घर में बगावत कर पिछली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. लेकिन, जगदा बाबू ने पार्टी धर्म का पालन किया और उन्होंने राजद प्रत्याशी अंबिका यादव को जिताने के लिए एड़ी–चोटी का ज़ोर लगा दिया. अंतत: अंबिका यादव विधायक निर्वाचित हुए. फिर भी सुधाकर सिंह की राजनीतिक सक्रियता जारी रही. इसी बीच भाजपा ने जदयू के ज़िलाध्यक्ष एवं पिछले विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले अशोक सिंह को अपने पाले में शामिल कर लिया. इस बार भाजपा का टिकट पाने के लिए अशोक सिंह और सुधाकर सिंह में कांटे की टक्कर चल रही है. बीच में पूर्व प्रत्याशी एवं नुआंव के प्रखंड प्रमुख अभय सिंह तीसरा कोण बनाने की फिराक में हैं. यहां बगावत की राह पकड़ कर भाजपा से राजनीति शुरू करने वाले सुधाकर सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. तीसरी विधानसभा सीट रोहतास की काराकाट है, जहां से सहकारिता नेता स्वर्गीय तपेश्वर सिंह के पौत्र एवं आरा की पूर्व सांसद मीना सिंह के बेटे विशाल सिंह अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने की कोशिश में हैं. क्षेत्र के लगातार दौरे बता रहे हैं कि विशाल सिंह अपने परिवार से जुड़े पारंपरिक मतदाताओं को एकजुट करने में लगे हैं. वह मतदाताओं को कितना समझा–रिझा पाते हैं, यह अलग बात है. रोहतास की दिनारा विधानसभा सीट भी इस परिवार और तपेश्वर सिंह के सबसे छोटे बेटे रंजीत सिंह के लिए एक चुनौती है, जहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए वह दिल्ली, पटना और दिनारा एक किए हुए हैं. कैमूर की चैनपुर विधानसभा सीट से पिछली बार राजद उम्मीदवार के रूप में तत्कालीन सांसद महाबली सिंह के बेटे धर्मेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इस बार अपनी यह परंपरागत सीट बचाने के लिए महाबली सिंह स्वयं मैदान–ए–जंग में उतरने का मन बना चुके हैं. रोहतास की नोखा विधानसभा सीट पर कई वर्षों तक कब्जा जमाए बैठे पूर्व मंत्री जंगी चौधरी और उनके बेटे आनंद मोहन सिंह के परिवार से भी किसी सदस्य के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट है. हाल में आनंद मोहन सिंह की पार्टी कार्यक्रम में हुई मौत के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ऐसे संकेत भी दिए हैं. यानी कुल मिलाकर कैमूरांचल की 11 में से सात सीटों पर विभिन्न राजनेताओं के परिवारीजन विरासत की जंग लड़ते दिखाई देंगे. ■

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान में भी एनजीओ के दीमक उसी तरह लगने लगे हैं, जैसे अन्य योजनाओं को वे चाट रहे हैं. उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहां स्वच्छता अभियान लागू करने में प्रधानमंत्री की दिलचस्पी भी है, सो ग़ैर सरकारी संस्थाएं उस दिलचस्पी का फ़ायदा उठाने में जुट गई हैं. केंद्र में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी स्वच्छता अभियान पर ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान पंच सितारा होटलों से नहीं, बल्कि गंदी गलियों और कूचों में चलाया जाता है.

स्वच्छता का पंच सितारा प्रपंच

अंधा बांटे रेवड़ी, चीन्ह-चीन्ह के देय... यह कहावत केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश में बखूबी चरितार्थ हो रही है. रेवड़ी बांटने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार निभा रही है और चीन्हा कौन गया है, इसे यह स्टोरी बयां कर रही है...

प्रभात रंजन दीन

सरकार की जो भी योजनाएं सामने आती हैं, वह ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से लागू हों, उसके पहले ही उन्हें लेकर धंधा शुरू हो जाता है. योजनाओं की धंधेबाजी में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है. केंद्र सरकार विदेशों से फर्जी तरीके से फंड हासिल करने वाली ग़ैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) पर ध्यान दे रही है और उन पर पाबंदियां भी लगा रही है, लेकिन उन एनजीओ की ओर किसी का ध्यान नहीं है, जो सरकार से ही फंड वसूल रही हैं और सरकार की योजनाएं बेच-बेचकर खा रही हैं. ज़मीनी स्तर पर काम केवल पंच सितारा होटलों के आलीशान और सुस्वादु सेमिनारों के ज़रिये संपादित हो रहा है. सरकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए दिया जाने वाला भारी-भरकम सरकारी फंड हड़पाय नम: हो रहा है. केंद्र सरकार की स्वास्थ्य को लेकर कोई योजना हो या पर्यावरण संरक्षण की या श्रमिक कल्याण की या फिर महिला एवं बाल कल्याण की, सारी सरकारी योजनाएं ग़ैर सरकारी संस्थाओं की कमाई के गोरखधंधे का ज़रिया बन गई हैं. इस धंधेबाजी में बड़े-बड़े पूंजी घरानों और कई मीडिया घरानों के अपने एनजीओ शामिल हैं. इन ऊंचे घराने वाले एनजीओ के साथ कई बड़े व्यापारिक संस्थान और बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक लिप्त हैं. सरकारी फंड की इस लूट पर अंकुश लगाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसा करके बड़े मीडिया घरानों को नाराज़ नहीं करना चाहतीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में शुरू किए गए स्वच्छता अभियान में भी एनजीओ के दीमक उसी तरह लगने लगे हैं, जैसे अन्य योजनाओं को वे चाट रहे हैं. उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहां स्वच्छता अभियान लागू करने में प्रधानमंत्री की दिलचस्पी भी है, सो ग़ैर सरकारी संस्थाएं उस दिलचस्पी का फ़ायदा उठाने में जुट गई हैं. केंद्र में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी स्वच्छता अभियान पर ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान पंच सितारा होटलों से नहीं, बल्कि गंदी गलियों और कूचों में चलाया जाता है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने ऐसे ही एक पंच सितारा कार्यक्रम में जाकर वहां के स्वच्छ आलीशान माहौल में प्रदेश की गलियों-मोहल्लों की सफाई पर खूब सारी स्वच्छ बातें कीं, अपना भव्य स्वागत कराया और एनजीओ के साथ-साथ लगीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना हित साधने का मार्ग प्रशस्त किया. इसी माहौल में मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश की सफाई का खूब ढिंढोरा पीटा और एनजीओ ने खूब प्रायोजित तालियां पिटवाईं. अखिलेश जिस प्रदेश के फिलहाल मुखिया हैं, उसके दर्जनों ज़िले आज गंदगी से बजबजा रहे हैं और वह जिस राजधानी में वास करते हैं, उसके भी अधिकांश इलाके घनघोर गंदगी वाली मलिन बस्तियों में तब्दील हो चुके हैं. आलीशान कोठी से निकल कर आलीशान सचिवालय जाने और हेलिकॉप्टर पर सवार होकर फुर्र से उड़ जाने को ही मुख्यमंत्री, उनके चाटुकार मंत्रिमंडलीय सदस्य और नौकरशाह स्वच्छता समझ लेते हैं.

गंदगी को जीवन का हिस्सा बना चुके प्रदेश के लोग जब मुख्यमंत्री का भाषण सुनते हैं कि राज्य सरकार स्वच्छता और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी का सपना साकार हो सके, तो अब उन्हें हंसी भी नहीं आती. उन्हें सैकड़ों विशाल वृक्षों के कटे शवों में पर्यावरण संरक्षण और गंदगी से सने राजधानी के मोहल्ले देखकर स्वच्छता अभियान की सच्चाई का एहसास हो जाता है. पिछले दिनों ऐसे ही एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या-क्या कहा, वह देखिए और ज़मीनी असलियत के साथ मुख्यमंत्री के संवाद की असलियत भी परखिए. मुख्यमंत्री बोले, अपनी साफ़-सफाई के साथ-साथ हमें अपने घरों, गांवों, मजरों, शहरों इत्यादि की सफाई पर भी ध्यान देना होगा. हमारे स्वास्थ्य एवं प्रगति के लिए स्वच्छ पर्यावरण अत्यंत आवश्यक है. खुले में शौच की आदत हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है. राज्य सरकार स्वच्छता और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दे रही है. तमाम उपलब्धियों के बावजूद खुले में शौच जाना आज भी एक गंभीर समस्या है. इसके चलते पीलिया आदि घातक रोग फैलते हैं. घरों में शौचालय निर्मित कर उनका प्रयोग करने से इन गंभीर रोगों से हम स्वयं को बचा सकते हैं. बीमारियों से बचने के लिए सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. इसके मद्देनज़र ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण की लागत 10 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 12 हज़ार रुपये कर दी गई है, ताकि कोई दिक्कत न हो. इस कार्य के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,533 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है. ग्रामीण इलाकों में शौचालयों के साथ-साथ स्नानगृहों के निर्माण के लिए भी 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 100 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें वाराणसी जनपद के 50 और कन्नौज एवं इटावा ज़िले के 25-25 गांव शामिल हैं.

मुख्यमंत्री जब शौचालयों के निर्माण के लिए धन आवंटन की राशि का जिक्र कर रहे थे, तब कार्यक्रम के आयोजकों के चेहरे की चमक देखी जा सकती थी. लेकिन, जब मुख्यमंत्री ने स्नानगृहों के निर्माण के लिए महज 16 करोड़ रुपये के आवंटन की बात कही, तो आयोजकों में भुनभुनाहट भी सुनी गई. और, आम लोगों को भी उत्तर प्रदेश सरकार की स्वच्छता के प्रति दिलचस्पी के सत्य का एहसास हुआ. लोगों को यह भी पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्वच्छता प्राथमिकता में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और अपना गृह जनपद इटावा ही शामिल है. इस कार्यक्रम में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, जो अपने पूरे कार्यकाल में शौच-शौच तो खूब कहते रहे, पर शौचालय बनाने के काम में कोई रुचि-तीव्रता नहीं दिखा पाए. कार्यक्रम आयोजित करने वाले एनजीओ और उसके साथ जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को आमंत्रित किया था और उनकी नजाकत का पूरा ध्यान रखा. एक अधिकारी ने कहा भी कि धंधा उत्तर प्रदेश में चलाना है, तो नजाकत का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा.

स्वच्छता अभियान से जुड़ा पूरा कार्यक्रम एनजीओ और उससे जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के मार्केटिंग-अभियान के रूप में ही अभिव्यक्त हुआ. उसमें कहीं से भी प्रदेश के गंदे इलाकों की सफाई की कोई मुकम्मल योजना नहीं दिखी. बड़े-बड़े स्वच्छ महानुभावों के दर्शन ज़रूर हुए. सफाई का रसायन बेचने वाली कंपनी रही हो या टॉयलेट बनाने का धंधा करने वाली कंपनी, इस कार्यक्रम में एनजीओ के साथ मिलकर उन्होंने मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को खूब पटाया और अंगवस्त्र पहना-पहना कर उनसे अंतरंग होने की खूब कोशिश की तथा इसमें वे सफल भी रहीं. इस अंतरंगता का ही नतीजा था कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में कई बार सफाई की दवा बेचने वाली कंपनी के सूत्र-वाक्य की तरह यह दोहराते रहे कि हाथ की सफाई कितनी ज़रूरी है. मुख्यमंत्री जब-जब यह विज्ञापनीय सूत्र-वाक्य दोहराते, वह मुख्यमंत्री कम, उस कंपनी के ब्रांड अंबेसडर अधिक दिखते. उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की, उसमें भी एनजीओ और उसके साथ जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के काम की ढेर सारी प्रशंसा की गई है. सरकार ने एनजीओ और उक्त कंपनी की प्रशंसा करते हुए यह भी लिखा है कि अभियान में उनका किस-किस तरह से सहयोग लिया जाएगा. अब देखिए कि स्वच्छता के नाम पर एनजीओ और बहुराष्ट्रीय कंपनी का साझा धंधा कैसे चलेगा (सरकारी भाषा में)... इनके साझा प्रयास से क्षमता निर्माण और जन-पैरोकारी साधनों द्वारा ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु परिवर्तन वाहकों को तैयार किया जाएगा. खुले में शौच करने से रोकने और जागरूकता लाने के लिए लोगों में व्यवहार परिवर्तन करने की दिशा में काम किया जाएगा.

स्वाभाविक है कि इन सारे कामों में फंड लगेगा. सफाई के नाम पर सफाई की दवा बेचने वाली कंपनी अपने उत्पाद की थोक आपूर्ति का रास्ता खोलेगी. टॉयलेट निर्माण करने के नाम पर भी धंधा चलेगा. सरकार ने तो लिखित तौर पर कहा कि स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए एनजीओ के साथ काम करना है, जिससे उन हिस्सों को चिन्हित किया जा सके, जहां शौचालय का निर्माण होना है और उनका सही रखरखाव सुनिश्चित कराना है. ऐसा कहते हुए सरकार ने स्वच्छता अभियान में शरीक पंचायती राज संस्था के सदस्यों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका और योगदान पर पानी फेर दिया. सरकार ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में जब यह कहा कि स्वच्छता अभियान के इस कार्य में समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों और मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा, तो कार्यक्रम की नज़दीक से समीक्षा करने वालों को प्रभावशाली लोगों और मीडिया का खास परिप्रेक्ष्य भी साफ़-साफ़ समझ में आ गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

सख्त क़ानूनों के बावजूद दुष्कर्मियों के हौसले बुलंद हैं

डॉ वसीम राशिद

16 दिसंबर, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पैरा-मेडिकल छात्रा निर्भया के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना ने देश के हर खास-ओ-आम को हिलाकर रख दिया था. उस घटना के बाद बने नए क़ानून और निर्भया के दोषियों को मिली सजा ने जन-सामान्य को यह भरोसा दिलाया था कि अब कोई शायद ही ऐसा करने की जुर्रत करे. लेकिन अफसोस! छेड़छाड़, बलात्कार व सामूहिक बलात्कार का सिलसिला लगातार जारी है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2014 में पूरे देश में बलात्कार की 37,413 घटनाएं सामने आईं, जिनमें से 2,300 घटनाएं सामूहिक बलात्कार की हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में बलात्कार की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज हुईं यानी 5,076. इनमें से पचास फ़ीसद से ज़्यादा मामलों में नाबालिग लड़कियां शिकार बनीं. राजस्थान दूसरे नंबर पर है, जहां 3,759 मामले दर्ज हुए. उत्तर प्रदेश में 3,467, महाराष्ट्र में 3,438 और दिल्ली में 2,096 मामले दर्ज हुए. नगालैंड एकमात्र ऐसा राज्य रहा, जहां बलात्कार के सिर्फ़ 32 मामले प्रकाश में आए.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के इस बयान कि एक महिला के साथ पांच पुरुष बलात्कार नहीं कर सकते, के बाद जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं, तो पाते हैं कि सामूहिक बलात्कार की कुल 2,300 घटनाओं में से 570 घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं. रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में पुलिस हिरासत के दौरान हुए बलात्कार के मामलों की संख्या 197 है, जिनमें से 17 मामले सामूहिक बलात्कार के हैं. उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में बलात्कार के 189 मामले प्रकाश में आए. ग़ौरतलब है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े पुलिस में दर्ज मामलों पर आधारित होते हैं. भारत जैसे देश में, जहां बदनामी के डर से लड़कियों को मार दिया जाता है, ऑनर किलिंग की घटनाएं आएदिन सामने आती रहती हैं, वहां कितने माता-पिता बलात्कार या सामूहिक बलात्कार की घटनाएं दर्ज कराते होंगे? यह सोचने की बात है.

रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में बलात्कार के प्रयास के 4,200 मामले सामने आए. इसके अलावा छिपकर नग्नावस्था में देखने के 674 और पीछा करने के लगभग 4,600 मामले सामने आए. उत्तर प्रदेश में ऐसे 835 और महाराष्ट्र में 797 मामले दर्ज किए गए. ग़ौरतलब है कि निर्भया कांड के बाद सरकार ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जस्टिस वर्मा की सिफारिश पर पोस्को (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट) जैसा सख्त क़ानून बनाया था. इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न, हमले और पोनोग्राफी से बचाव की व्यवस्था है. इस तरह के मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होती है और दोषी को उम्रक़ैद की सजा हो सकती है. सवाल यह है कि इतने सख्त क़ानून बना देने के बावजूद देश में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आख़िर क्यों? इससे भी ज़्यादा दु:ख की बात यह है कि हमारे विभिन्न राजनेता अपने बचकाना बयानों के ज़रिये बलात्कार पीड़ितों की पीड़ा बढ़ाने से बाज नहीं आते. ■

feedback@chauthiduniya.com

जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें

1. अदालत के संज्ञान लेते ही आरोपी के चुनाव लड़ने पर रोक लगे.
2. दुष्कर्म के आरोपी को शस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून के तहत सुरक्षा न मिले.
3. आरोपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सरकार से पूर्व अनुमति ज़रूरी नहीं.
4. अपराध क़ानून संशोधन विधेयक-2012 में यौन इत्पीड़न (सेक्सुअल असॉल्ट) की जगह पहले से मौजूद दुष्कर्म (रेप) शब्द का प्रयोग किया जाए.
5. सुरक्षा का दायित्व निभाने में नाकामी की वजह से दुष्कर्म की स्थिति में ज़िम्मेदार अधिकारी को सात से 10 साल की सजा दी जाए.

क्या कहता है पोक्सो एक्ट

1. यह क़ानून 18 वर्ष से कम इम्र के बच्चों को हर तरह के यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है.
2. इसके तहत दोषियों को कठोर सजा और सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की जाएगी, जो एक वर्ष के भीतर मामले का निपटारा करेगी.
3. इसमें मामले की रिपोर्टिंग, सुबूतों की रिकॉर्डिंग, जांच एवं सुनवाई जैसी तमाम न्यायिक प्रक्रियाएं बच्चों के अनुकूल बनाई गई हैं. तीस दिनों के भीतर सुबूत जुटाने और रात में बच्चों को थाने में न रखने का प्रावधान भी किया गया है.
4. इसमें बयान लेते वक्त पीड़ित को अनुवादक, विशेषज्ञ एवं व्याख्या करने वाले की सहायता देने और नि:शक्त बच्चों को विशेष शिक्षक या परिचित की मदद देने के साथ-साथ माता-पिता या विश्वस्त अभिभावक के सामने चिकित्सकीय जांच का प्रावधान है.
5. यदि पीड़ित लड़की है, तो इसकी जांच महिला डॉक्टर ही करेगी. बच्चों को गवाही के लिए बार-बार न बुलाने, सुनवाई के दौरान अवकाश देने, असुविधाजनक सवाल न पूछने और बंद कमरे में सुनवाई करने का भी इसमें प्रावधान है.

तस्वीरों में यह सप्ताह

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

1

2

3

4

5

6

1– दिल्ली के जंतर-मंतर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवारीजन एवं समर्थक सरकार से यह मांग करते हुए कि नेताजी से जुड़े दस्तावेज़ों को डि-क्लासीफाइड (गोपनीयता ख़त्म करना) किया जाए. 2– वन रैंक वन पेंशन के लिए धरना दे रहे पूर्व सैनिकों के समर्थन में आए राहुल गांधी. 3– दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्जी एडमिशन रैकेट का विरोध करते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता. 4– महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करती जनता. 5– पाकिस्तानी गोलीबारी और एनएसए वार्ता का विरोध करते शिवसेना कार्यकर्ता. 6– प्याज के बढ़ते दाम पर मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करते यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता.

फूल, आंसू और धोखा

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

मैंने नीरा को धिक्कारते हुए कहा कि यह केस मैंने सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं लिया था, बल्कि इससे मेरे देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी. मैंने नीरा को बहन माना था. वह सीधे मुझसे पैसों की ज़रूरत के लिए बोल सकती थी, जिसे मैं शायद ही नकारता. मैंने उसे बताया कि उसने ऐसा करके अपराध किया है और फेरा क़ानून के तहत इसके लिए उसे सजा मिल सकती है. नीरा रोने लगी. उसने बताया कि केएलएम के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो गया है और मैं चाहूं, तो सीधे केएलएम से अपने पैसों के लिए बात कर सकता हूं. बहरहाल, इतना सब कुछ होने के बाद भी वह असल बात नहीं बता रही थी. मुझे लग रहा था कि वह एक ही समय में केएलएम और मेरे साथ दोहरा खेल खेल रही थी. मैं सही था, क्योंकि इस मुलाकात के बाद अपनी फीस लेने के लिए मुझे एक दशक से भी अधिक समय तक लड़ाई लड़नी थी. उस धोखे के बाद भी मेरे दिल के एक कोने में नीरा के लिए जगह बची हुई थी. हमारा कॉमन दोस्त, जिसने मुझे नीरा से मिलवाया था, ने कुछ और मुलाकातें कराने की कोशिश की. हमने दिल्ली के अंबेसडर होटल में लंच किया, लेकिन असल मुद्दा लटका ही रहा.

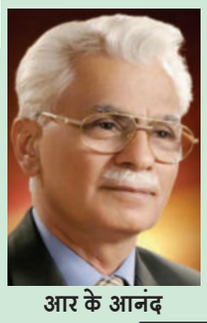

आर के आनंद

स्वीकृति पत्र, जिस पर मैं हस्ताक्षर कर चुका था, मिलने के एक सप्ताह के भीतर मुझे पहला भुगतान मिलना था. तीन महीने बीत गए थे, लेकिन भुगतान का कोई अता-पता नहीं था. नीरा इस बारे में गोलमोल जवाब दे रही थी. वह क्रिसमस या नए साल या नए वित्तीय वर्ष जैसी बहानेबाजी कर रही थी. अब नीरा मेरे घर पर कम ही आ रही थी. फिर उसने अचानक मेरे घर आना बंद कर दिया. वह मेरे फोन उठाती तो थी, लेकिन जवाब में मुझे मिलता था फूलों का महंगा बुके. नीरा ऐसे बुके लगातार मेरे ऑफिस भेजती रही. मेरे फार्म पर लगातार आने की वजह से उसे पता था कि मुझे बागवानी और फूलों का शौक है.

अंत में मैंने सीधे जॉन डेरबीशायर को पत्र लिखा. जो जवाब मुझे मिला, उसके साथ एक फैक्स कॉपी भी थी, जिसकी तिथि नौ जुलाई, 1999 थी. उससे मैं सन्न रह गया. पत्र में कहा गया था कि 23 दिसंबर, 1998 को नीरा राडिया के माध्यम से मेरा सारा भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने मुझसे तत्काल इस ख़बर की पुष्टि करने को कहा. इसी के साथ पत्र की एक कॉपी नीरा को भेजी गई. मुझे नीरा की ओर से एक और बुके मिला. उसके बाद एक फोन आया और उसने मुझसे मिलने के लिए वक्त मांगा. अगले दिन वह मेरे ऑफिस आई और क्षमा मांगते हुए कहा कि उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुझे ख़बर नहीं दी. इसके लिए उसने केएलएम से सीधे अपने नाम से चेक भेजने का अनुरोध किया और चेक मिलते ही उसे अपने विदेशी एकाउंट में डाल दिया.

मैंने नीरा को धिक्कारते हुए कहा कि यह केस मैंने सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं लिया था, बल्कि इससे मेरे देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई थी. मैंने नीरा को बहन माना था. वह सीधे मुझसे पैसों की ज़रूरत के लिए बोल सकती थी, जिसे मैं शायद ही नकारता. मैंने उसे बताया कि उसने ऐसा करके अपराध किया है और फेरा क़ानून के तहत इसके लिए उसे सजा मिल सकती है. नीरा रोने लगी. उसने बताया कि केएलएम के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो गया है और मैं चाहूं, तो सीधे केएलएम से अपने पैसों के लिए बात कर सकता हूं. बहरहाल, इतना सब कुछ होने के बाद भी वह असल बात नहीं बता रही थी. मुझे लग रहा था कि वह एक ही समय में केएलएम और मेरे साथ दोहरा खेल खेल रही थी. मैं सही था, क्योंकि इस मुलाकात के बाद अपनी फीस लेने के लिए मुझे एक दशक से भी अधिक समय तक लड़ाई लड़नी थी.

उस धोखे के बाद भी मेरे दिल के एक कोने में नीरा के लिए जगह बची हुई थी. हमारा कॉमन दोस्त, जिसने मुझे नीरा से मिलवाया था, ने कुछ और मुलाकातें कराने की कोशिश की. हमने दिल्ली के अंबेसडर होटल में लंच किया, लेकिन असल मुद्दा लटका ही रहा. नीरा ने मेरे दोस्त से यह भी कहा कि या तो वह मुझे चुने या फिर नीरा को. लेकिन, मेरा दोस्त कूटनीतिक रास्ता अपनाते हुए मेरे और नीरा के बीच संवाद के विभिन्न माध्यम तलाशता रहा. बाद में एक बहुत ही संवेदनशील और व्यक्तिगत समस्या को लेकर नीरा मेरे पास मदद मांगने आई. तब मैं जेनेवा में था. वहां मुझे नीरा का फोन आया. वह ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी. मामला यह था कि राव धीरज सिंह ने दुर्घटनावश रिवाल्वर से अपनी गर्दन घायल कर ली थी और पुलिस तहकीकात के लिए पहुंची हुई थी. मैंने तत्काल दिल्ली में अपने वकील सहयोगियों से वहां जाकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि पुलिस नीरा से बुरा व्यवहार न करे. उस घटना को मेरी टीम ने संभाला और कोई केस नहीं बना. यह सब बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि मैं जहां दोस्ती को देख रहा था, वहीं नीरा अपनी महत्वाकांक्षा को और ऊंचाई दिए जा रही थी.

पत्र में कहा गया था कि 23 दिसंबर, 1998 को नीरा राडिया के माध्यम से मेरा सारा भुगतान किया जा चुका है. उन्होंने मुझसे तत्काल इस ख़बर की पुष्टि करने को कहा. इसी के साथ पत्र की एक कॉपी नीरा को भेजी गई. मुझे नीरा की ओर से एक और बुके मिला. उसके बाद एक फोन आया और उसने मुझसे मिलने के लिए वक्त मांगा. अगले दिन वह मेरे ऑफिस आई और क्षमा मांगते हुए कहा कि उसे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुझे ख़बर नहीं दी. इसके लिए उसने केएलएम से सीधे अपने नाम से चेक भेजने का अनुरोध किया और चेक मिलते ही उसे अपने विदेशी एकाउंट में डाल दिया.

फीस के लिए मेरी लड़ाई

मैं चाहता, तो नीरा को सजा दिलवा सकता था. मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसा करने की सलाह भी दी, लेकिन मैं एक नज़दीकी दोस्त की धोखेबाजी से आहत था. अब मैं वह कहानी बताऊंगा, जिसमें मुझे अगले एक दशक तक लड़ाई लड़नी पड़ी. यह कहानी उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति बेशर्मी के साथ अपनी हसरत पूरी करने के लिए दूसरे को अपने पैरों से रौंदने में भी नहीं हिचकता. वह पत्र पाने के आधे घंटे के भीतर ही मुझे डेरबीशायर का फोन आया, जिसमें वह जानना चाहते थे कि क्या नीरा ने मुझे वह पैसा दिया है, जो उन्होंने नीरा को चेक के ज़रिये भेजा था. मैंने सीधे कहा कि नहीं, मुझे पैसा नहीं मिला. चूंकि केएलएम के पास मेरे बैंक एकाउंट के सारे डिटेल थे, तो उन्हें सीधे मेरे एकाउंट में पैसा भेजना चाहिए था. मैंने डेरबीशायर को बताया कि नीरा उनकी एजेंट है, मेरी नहीं. और, यह भी कि फेरा क़ानून के तहत पैसा सीधे मेरे एकाउंट में आना चाहिए था. उन लोगों ने मुझसे बात करने से पहले नीरा से बात की थी और नीरा ने उन्हें कुछ ग़लत जानकारी दी थी. वे लोग मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे कि मुझे पैसे नहीं मिले. इस सबके बाद भी मैंने नीरा और केएलएम से संपर्क नहीं तोड़ा. धैर्यपूर्वक मैं उन्हें बताता रहा कि मुझे पैसे मिलने चाहिए. ■

जारी...

(मशहूर वकील आर.के. आनंद क्लोज इंकाउंटर्स विद नीरा राडिया के लेखक हैं.)

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आरक्षण पर नई बहस की कोशिश में संघ और भाजपा

अहमदाबाद और सूरत में लोगों द्वारा अचानक प्रदर्शन करने की घटना ने देश को आश्चर्य में डाल दिया है. एक 22 वर्षीय शख्स अचानक नेता के रूप में इस तरह विशाल भीड़ जुटा सकता है, यह आम आदमी की कल्पना के बाहर था. यह सहज नहीं हो सकता. निश्चित तौर पर ऐसा कोई संगठन था, जो चुपचाप काम कर रहा था और इसका प्रबंधन कर रहा था. वह संगठन कौन है, हम नहीं जानते, लेकिन हम इस समस्या की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं. समस्या नौकरी में कमी की है, शिक्षा के क्षेत्र में सीटों की कमी है. समस्या सुविधा में कमी की है, पिछड़ेपन के आधार पर दावेदारी की है. और, ये बातें 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आईं और 1990 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा इसे लागू किया गया था. इसे लेकर देश में व्यापक आंदोलन हुआ, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि आरक्षण किसी भी स्थिति 50 फ़ीसद से अधिक नहीं होना चाहिए.

समस्या जितनी दिखती है, उससे कहीं बड़ी है. पहली बात तो यह कि आरक्षण जाति आधारित होना चाहिए या ग़रीबी आधारित? तर्क यह था कि दलित एवं पिछड़ी जातियां दशकों अथवा कहें कि सदियों से पिछड़ेपन की शिकार और आम तौर पर ग़रीब रही हैं. इसलिए जाति और ग़रीबी एक–दूसरे के प्रतिरूप हैं. मंडल कमीशन ने यह सिफारिश की कि अगर कुछ निश्चित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें ग़रीब भी आ जाएंगे. यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन यह भी सही है कि ब्राह्मणों एवं राजपूतों की तरह ऊंची जाति के लोग भी ग़रीब हैं. उन्हें इसलिए कोई आरक्षण नहीं मिलता क्योंकि वे उच्च जाति में पैदा हुए हैं. एक अन्य समस्या जाति को परिभाषित करने को लेकर है. एक राज्य में कोई एक जाति अगड़ी हो सकती है, तो दूसरे राज्य में पिछड़ी. उदाहरण के लिए, बिहार में वैश्य समुदाय पिछड़ा माना जाता है, जबकि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में यह बहुत समृद्ध है. बिहार में सुशील कुमार मोदी जैसे नेता पिछड़े माने जाते हैं. इन जटिलताओं को आसानी से हल नहीं किया जा सकता. राजस्थान में जाट प्रमुख जाति है. वे पिछड़ी जाति में शामिल होना चाहते हैं और इसके लिए मांग करते हैं. उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पूरी तरह से जाटों का वर्चस्व है और मानते हैं कि यदि वे पिछड़ा वर्ग में शामिल होते हैं, तो उन्हें और अधिक लाभ मिलेगा.

एक आम बौद्धिक क्षमता वाला आदमी यह समझ सकता है कि गुजरात में जो हुआ, वह पटेलों द्वारा खुद के आरक्षण से आगे की बात है. उन्हें आरक्षण नहीं मिल सकता और इस बात को वे भी समझते हैं. वे शायद आरक्षण पर इस बहस को जन्म देना चाहते हैं कि अन्य सभी जातियों के लिए भी आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए. उद्देश्य तो यही प्रतीत होता है. उन्होंने आज आंदोलन शुरू किया है और अगले चुनाव तक शायद यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए कि आरक्षण नहीं होना चाहिए. यह इस आंदोलन का प्रारंभिक ख़तरा है. यह क़ानून व्यवस्था की समस्या नहीं है. पुलिस ने हार्दिक पटेल को गिरफ्तार करके बेवकूफी की. आंदोलन से निपटने का यह कोई तरीका नहीं है. इसी तरह दिल्ली पुलिस मूर्खतापूर्ण तरीके से सेना के पूर्व लोगों के साथ पेश आई, वह तरीका भी सही नहीं था. क्या पुलिस देश को संभाल सकती है? पाकिस्तान बहुत सही कर रहा है, जहां लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है, प्रधानमंत्री की आवाज़ का कोई मतलब नहीं है, वहां सिर्फ़ सेना है, जो असल शासन कर रही है. हम यहां वैसा नहीं कर सकते. हमारे यहां बातचीत और संवाद ही असल चीज है. बेशक, अभी यह कहना कठिन है कि पटेल चाहते क्या हैं, लेकिन हमें बड़े मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर देना चाहिए. हम आरक्षण की इस समस्या से कैसे निपटने जा रहे हैं? हमें ग़रीबी से निपटना है. व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वह ग़रीब है, उसके पास भोजन नहीं है, तो उसे पैसा देना ही होगा. इस सरकार ने जिस मनरेगा की आलोचना की, वह बहुत अच्छा काम कर रही है. इसकी वजह से ग़रीबों के हाथ में थोड़ा–बहुत पैसा आया है. निश्चित तौर पर इसमें भ्रष्टाचार है, दुरुपयोग है, लेकिन यह भी सही है कि कल तक जिन ग़रीबों के पास कोई काम नहीं था, आज उन्हें काम मिल रहा है और इसके ज़रिये उनके हाथ में पैसा आ रहा है. केंद्रीय मुद्दा जाति नहीं, ग़रीबी है. ग़रीबी हटाने के लिए पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए. अनुसूचित जातियों को दस साल के लिए संविधान में दस फ़ीसद आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद इसे हटाने का साहस किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिखाया. मैं समझ सकता हूं कि अनुसूचित जातियों को सैकड़ों सालों तक मैला ढोने और इसी तरह के अन्य काम करने की वजह से काफी नुक़सान उठाना पड़ा. लेकिन, अन्य पिछड़ी जातियों के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें ज़मीन मिली?

मैं समझता हूं कि इस गुजरात आंदोलन को एक संकेत के तौर पर लेना चाहिए और जाति पर गंभीरता से काम शुरू होना चाहिए. यह काम केंद्र सरकार या नीति आयोग को दिया जाना चाहिए या इसके लिए एक विशेष समिति बनानी चाहिए. एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस तरह की सम्स्या सभी जगह नहीं है. उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु को लें. वहां मंडल आयोग के बहुत पहले से 60 फ़ीसद आरक्षण था. वहां के आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका जा रहे हैं और वे ब्राह्मण या सवर्ण नहीं, बल्कि पिछड़ी जातियों से आते हैं. अगर हम स्टीरियो टाइप ढंग से यह सोचें कि ब्राह्मण का काम सिर्फ़ पूजा और कर्मकांड है, तो यह ग़लत होगा. कभी यह बात सही थी, लेकिन आज तो आपको उन्हें अवसर देने ही होंगे. आज का युवा यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके दादा एक ब्राह्मण थे, इसलिए कोई भी उसे काम नहीं देगा.

मेरे अनुसार यह बहुत ही ख़तरनाक बात है कि पटेल समुदाय, जो वास्तव में गुजरात की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके पास ज़मीन है, वह आज आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहा है. वे सड़कों पर कैसे आ सकते हैं? लोग उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर आ जाएंगे. लेकिन, उनका सड़कों पर आना यह संकेत करता है कि भाजपा या संघ में कुछ चल रहा है. भाजपा या संघ आरक्षण वाली बहस को शुरू करना चाहते हैं और इसलिए वे इस तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं.

हम नहीं जानते, लेकिन समय बताएगा कि सच क्या है. अफवाह है कि संघ परिवार दिसंबर में, जब अमित शाह का कार्यकाल ख़त्म होगा, तब नितिन गडकरी को भाजपा अध्यक्ष बनाएगा और अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे. ऐसा सब सुनने में आ रहा है. यह भी सुनने में आ रहा है कि अमित शाह आनंदी बेन पटेल से खुश नहीं हैं और इसलिए गुप्त रूप से इस आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहे हैं. यह सब राजनीति में चलता रहता है और सच इतनी आसानी से बाहर नहीं आता. लेकिन, जहां तक देश का सवाल है, तो यदि सवर्ण भी आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू करते हैं, तब हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल स्थिति होगी. यह समस्या नियंत्रण से बाहर चली जाए, उससे पहले इसका समाधान निकालना होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

> मैं समझता हूं कि इस गुजरात आंदोलन को एक संकेत के तौर पर लेना चाहिए और जाति पर गंभीरता से काम शुरू होना चाहिए. यह काम केंद्र सरकार या नीति आयोग को दिया जाना चाहिए या इसके लिए एक विशेष समिति बनानी चाहिए. एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस तरह की सम्स्या सभी जगह नहीं है. उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु को लें. वहां मंडल आयोग के बहुत पहले से 60 फ़ीसद आरक्षण था. वहां के आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका जा रहे हैं और वे ब्राह्मण या सवर्ण नहीं, बल्कि पिछड़ी जातियों से आते हैं. अगर हम स्टीरियो टाइप ढंग से यह सोचें कि ब्राह्मण का काम सिर्फ़ पूजा और कर्मकांड है, तो यह ग़लत होगा. कभी यह बात सही थी, लेकिन आज तो आपको उन्हें अवसर देने ही होंगे.

जब एक स्त्री डाकू बदला लेने पहुंचती है-3

मान सिंह जैसा बनना चाहते थे लालाराम-श्रीराम

बेहमई और आसपास के अन्य गांव राजपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं. यह विधानसभा क्षेत्र शायद मध्य उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां घोर जातीय नारों के आधार पर चुनाव होते हैं और उम्मीदवार की जीत भी जातियों के इकट्ठे होने–न होने पर निर्भर होती है. इस बार भी इस इलाके से अर्जक संघ के राम स्वरूप वर्मा विधायक हैं. अर्जक संघ घोषित रूप से पिछड़ों का दल है और उसके नेता राम स्वरूप वर्मा ही उसके जन्मदाता हैं. वह इस क्षेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए हैं. जनता पार्टी की हवा में चुने गए राकेश चतुर्वेदी के पहले तीन चुनावों में वह ही विजयी उम्मीदवार थे. वह 1967 में राज्य में बनी सम्मिलित सरकार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं. वह व्यक्तिगत रूप से वर्ण–संघर्ष के पक्षधर और मौजूदा ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे के विरुद्ध हैं. उनका अर्जक संघ उनके इन विचारों को व्यवहारिक रूप देने का ही एक माध्यम है, जिसके ज़रिये समय–समय पर ब्राह्मणवादी संस्कृति पर सीधी चोट करने की कार्रवाइयां होती रहती हैं. इस इलाके में कुर्मियों व ब्राह्मणों की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन आर्थिक संपन्नता कुर्मियों में अधिक है और यहां के ब्राह्मणों के मुक़ाबले वे शिक्षित भी ज़्यादा हैं. इसने उनमें सामाजिक सम्मान पाने की जो भूख पैदा कर दी है, उसे राम स्वरूप वर्मा टुकड़ों–टुकड़ों में तुष्ट करते रहे हैं. अर्जक संघ द्वारा किया जाने वाला नाटक शम्बूक वध भी, जिसमें ब्राह्मणों के मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा शम्बूक नाम के एक शूद्र तपस्वी की हत्या कराके राम राज्य की परिकल्पना का मज़ाक उड़ाया जाता है, उसी पुष्टिकरण की एक कड़ी है. कोई ढाई वर्ष पहले, जब राम स्वरूप वर्मा अपने प्रभाव में कुछ कमी महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने इस इलाके में अर्जक संघ के लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से रामचरित मानस की प्रति जलाए जाने की घोषणा कर दी थी. इसने उनके अनुयायियों को एक तुष्टि ज़रूर प्रदान की, लेकिन इससे क्षेत्र में जातीय द्वेष की आग और गाढ़ी हो गई.

यह जातीय द्वेष का तीखापन इस क्षेत्र के हर वर्ग व जाति के व्यक्ति में देखा जा सकता है. इसने सीधे–सीधे यहां के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है, सवर्ण और पिछड़ा. सवर्णों की अगुवाई ब्राह्मणों के हाथों में है और ठाकुर उनके साथ हैं. जबकि पिछड़ों की डोर कुर्मियों के पास है और बाकी जातियां उनके पीछे हैं. घोर जातीय आधार पर यह विभाजन यहां के सामान्य सामाजिक जीवन में भी दिखता है. कुर्मी ब्राह्मणों के बीच नहीं बैठते और ब्राह्मण कुर्मियों के बीच नहीं, क्योंकि दोनों को अकेला पड़ने पर अपमानित किए जाने का ख़तरा रहता है. यहां तक कि क्षेत्र की अन्य पिछड़ी जातियों के मज़दूर भी यह जातीयता निभाते हैं और वे किसी पंडित या ठाकुर के यहां मज़दूरी करने के बजाय कुर्मी के यहां काम करना अधिक पसंद करते हैं. यही सवर्णों में भी है. इस तरह कहा जा सकता है कि यहां पर आदमी नहीं, बल्कि ब्राह्मण–ठाकुर बसते हैं या फिर कुर्मी–यादव.

दस्यु गिरोहों में भी इस जातीय सोच की शिनाख्त की जा सकती है. बताते हैं कि लालाराम–श्रीराम द्वारा विक्रम को मारे जाने के पीछे भी यही सोच थी. उससे पहले विक्रम ने खड़गोई गांव के बृज वल्लभ सिंह को, जो लालाराम–श्रीराम का मौसेरा भाई था, मरवा दिया. उसकी मौत से आहत होकर उसकी बहन तभी उनके पास आई और बोली कि तुम लोग या तो उसकी मौत का बदला लो या फिर बीहड़ छोड़ दो. तुम्हारे बीहड़ में रहने से हमें क्या फ़ायदा? इसका लालाराम–श्रीराम पर बड़ा असर पड़ा. वस्तुत: जबसे गिरोह पर विक्रम मल्लाह का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, वे उससे मन ही मन जलने लगे थे. इस घटना ने उन्हें उसका दुश्मन ही बना दिया. विक्रम की मौत के बाद भी लालाराम–श्रीराम ने अपनी जाति के लोगों के अहं की पुष्टि के लिए मल्लाहों व अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को सताने का जो घिनौना सिलसिला शुरू किया, उसने इलाके में सक्रिय अन्य प्रतिद्वंद्वी डाकू गिरोहों को भी नहीं बख्शा. इस दौरान अपनी जाति को छोड़कर अन्य जातियों के लोगों को ही निशाना बनाने की वारदातें सामने आईं. लालाराम–श्रीराम के बारे में बताया जाता है कि उन्हें मान सिंह की तरह का लोकप्रिय डाकू सरदार बनने का चस्का लग गया. वे इलाके में लोगों की पंचायतें करने लगे. 14 फरवरी को बेहमई के पड़ोसी गांव दमनपुर के बीहड़ में उनकी एक पंचायत आयोजित थी, जिसमें दमनपुर के एक नाई की बारह बीघा ज़मीन गांव के एक ठाकुर द्वारा हड़पे जाने का मामला तय होना था. फूलन को शायद इसी पंचायत की ख़बर लगी होगी.

जारी...

feedback@chauthiduniya.com

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

> सवर्णों की अगुवाई ब्राह्मणों के हाथों में है और ठाकुर उनके साथ हैं. जबकि पिछड़ों की डोर कुर्मियों के पास है और बाकी जातियां उनके पीछे हैं. घोर जातीय आधार पर यह विभाजन यहां के सामान्य सामाजिक जीवन में भी दिखता है. कुर्मी ब्राह्मणों के बीच नहीं बैठते और ब्राह्मण कुर्मियों के बीच नहीं, क्योंकि दोनों को अकेला पड़ने पर अपमानित किए जाने का ख़तरा रहता है. यहां तक कि क्षेत्र की अन्य पिछड़ी जातियों के मज़दूर भी यह जातीयता निभाते हैं और वे किसी पंडित या ठाकुर के यहां मज़दूरी करने के बजाय कुर्मी के यहां काम करना अधिक पसंद करते हैं. यही सवर्णों में भी है. इस तरह कहा जा सकता है कि यहां पर आदमी नहीं, बल्कि ब्राह्मण-ठाकुर बसते हैं या फिर कुर्मी-यादव.दस्यु गिरोहों में भी इस जातीय सोच की शिनाख्त की जा सकती है. बताते हैं कि लालाराम–श्रीराम द्वारा विक्रम को मारे जाने के पीछे भी यही सोच थी.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सार्थक राजनीतिक संवाद की ज़रूरत

> गुजरात में 22 वर्ष का युवक पटेलों का नया मुखर प्रवक्ता बन चुका है. जब समाज में विचार समाप्त होता है और न्यायपूर्ण अवसरों की संभावना समाप्त हो जाती है, तब स्वत: समाज के भीतर से कोई व्यक्ति नेता बन जाता है. ऐसे उदाहरण हमारे देश में कई हैं और उनमें नया नाम हार्दिक पटेल का है. हार्दिक पटेल संपन्न पटेल समुदाय के लिए नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं. दूसरे शब्दों में, वे व्यवस्था के अंदर अपना दखल चाहते हैं. अर्थव्यवस्था का बड़ा नियंत्रण उनके हाथ में है, पर वे कार्यपालिका में भी अपनी जगह चाहते हैं.

तीस वर्षों के भीतर भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है. पहले नेता विचारों के आधार पर बनते थे. विचार थे, जो तय करते थे कि कैसा समाज बनाना है और परिभाषाएं भी कुछ साफ़ थीं. पूंजीपति, समाजवादी, साम्यवादी या फिर सर्वोदय. सब अपनी–अपनी बात लोगों के सामने रखते थे, लोगों को समझाने की कोशिश करते थे. इस सारी प्रक्रिया में वे लोग पैदा होते थे, जो वैचारिक रूप से सशक्त होते थे और समाज का नेतृत्व करना चाहते थे, जिनमें से कुछ को जनता स्वीकार करती थी, कुछ को अस्वीकार कर देती थी. पर जो भी राजनीति में आगे बढ़ता था, उसके साथ किसी एक विचारधारा का आधार होता था. अब ऐसा नहीं है. अब विचार नेता पैदा नहीं करते, बल्कि समस्याएं नेता पैदा करती हैं. जब समस्याएं नेता पैदा करती हैं, तो उस नेता का विचारधारा से कोई मतलब नहीं होता और उसका पूरे समाज से कोई मतलब नहीं होता. हमारे समाज में बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, जिनकी संख्या नगण्य है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास आवाज़ उठाने की भी ताकत नहीं है. ऐसे लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, संसाधन बहुत कम हैं, बहुत थोड़े हैं, वे दरअसल 50 प्रतिशत से ज़्यादा हैं. और, 50 प्रतिशत में वे लोग हैं, जिनके पास बहुत कुछ है. फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है.

गुजरात में जो हो रहा है, वह समस्या के कारण हो रहा है. समस्या है अवसरों के समाप्त होने की, समस्या है जिन्हें अवसर मिल चुके हैं, वे और अवसर चाहते हैं. हार्दिक पटेल इसी समस्या और सोच की पैदाइश हैं. आम तौर पर गुजरात में पटेल समाज एक संपन्न समाज माना जाता है. आर्थिक रूप से वहां भी विपन्न हैं, जैसे बाकी समाजों में हैं, लेकिन वे सामाजिक रूप से विपन्न नहीं हैं. उनके पास कुछ न हो, लेकिन समाज में उनकी इज्जत, उनकी पूछ बहुत सारे दलितों एवं पिछड़ों से ज़्यादा है. गुजरात में इसे हम अध्ययन के तौर पर देख सकते हैं. पटेल समुदाय अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के ज़रिये आगे बढ़ना चाहता है.

इस सबके बीच विकास का संतुलित ढांचा आ जाता है. संतुलित विकास हुआ होता, तब ये समस्याएं नहीं पैदा होतीं. लेकिन, असंतुलित विकास और असीमित अवसरों के शोषण ने देश में किसी भी एक वर्ग को खुश नहीं रखा है. जिनके पास है, वे अपने साथ के दूसरे लोगों को जगह नहीं देना चाहते. वे न केवल वहां जमे रहना चाहते हैं, बल्कि अपने से ग़रीब या आर्थिक रूप से कमज़ोर अपने ही समाज के लोगों को आगे आने से रोकना चाहते हैं. इसके पीछे पिछले 60–65 वर्षों का अन्यायपूर्ण ढांचा है, जिसने देश में हर तबके को निराश किया है. खुश सिर्फ़ वे हैं, जो भ्रष्ट हैं, बाहुबली हैं और लूट के नए–नए तरीके तलाशने में माहिर हैं.

इसलिए आज जब समाज में कोई अपराधी या बाहुबली चुनाव जीतता है, तो उसके पीछे यही मनोविज्ञान है कि उस जाति के लोग उसे अपना आदर्श मानकर राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं. उन्हें यह लगता है कि वैचारिक रूप से राजनीति करने वाले असफल हो चुके हैं. उनसे कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए उनको समर्थन देने का कोई मतलब नहीं है. और, हर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि इस प्रकार के लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है.

गुजरात में 22 वर्ष का युवक पटेलों का नया मुखर प्रवक्ता बन चुका है. जब समाज में विचार समाप्त होता है और न्यायपूर्ण अवसरों की संभावना समाप्त हो जाती है, तब स्वत: समाज के भीतर से कोई व्यक्ति नेता बन जाता है. ऐसे उदाहरण हमारे देश में कई हैं और उनमें नया नाम हार्दिक पटेल का है. हार्दिक पटेल संपन्न पटेल समुदाय के लिए नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं. दूसरे शब्दों में, वे व्यवस्था के अंदर अपना दखल चाहते हैं. अर्थव्यवस्था का बड़ा नियंत्रण उनके हाथ में है, पर वे कार्यपालिका में भी अपनी जगह चाहते हैं. यह सवाल खड़ा होने के पीछे सिर्फ़ एक कारण है कि लोग निराश हो चुके हैं. लोगों को लगता है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से कुछ पा नहीं सकते.

हमारे इस अविवेकी समाज से पैदा हुई सरकारें अब शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं को सुनती नहीं हैं. जब तक हिंसा न हो, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती. उन्हें यह पता नहीं रहता कि उनकी योजनाओं या उनके वादों या उनके क्रियाकलापों की वजह से किस वर्ग में असंतोष पैदा हो रहा है. अच्छी सरकार वह होती है, जो असंतोष पैदा होने से पहले या असंतोष पैदा होने के समय उसके निराकरण का उपाय सोचे. लेकिन, हमारे देश की सरकारें असंतोष को तब तक बढ़ने देती हैं, जब तक वह क़ानून व्यवस्था की समस्या न बन जाए और मुख्य समस्या उसके भीतर विलुप्त न हो जाए.

इसलिए जब नक्सलवादी किसी प्रदेश में ज़िलाधिकारी को अगवा कर लेते हैं, तो सरकारें उनकी बातें सुनती हैं. जब कहीं कोई समुदाय रेल आवागमन अवरुद्ध कर देता है, तब उसकी बातें सुनती हैं. लेकिन, विडंबना यह है कि उस समय जो वादे करती हैं, उन्हें भी पूरा नहीं करतीं. सरकारों का एक उद्देश्य रह गया है कि अभी आने वाली समस्या को टालो, जब समस्या दोबारा खड़ी होगी, तब देखा जाएगा.

हार्दिक पटेल ने होशियारी के साथ अपने लिए राजनीतिक ज़मीन भी तलाशी है. उन्होंने नीतीश कुमार को अपना साथी बताया है, चंद्रबाबू नायडू को भी अपना साथी बताया है. समस्याओं के हल के रूप में आरक्षण मांगने वाले लोगों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे नेताओं ने भी समस्याओं का हल आरक्षण ही बताया है, कोई दूसरा उपाय किसी ने बताया ही नहीं. पिछले वर्षों में समाज के भीतर असहिष्णुता आक्रामकता, अपराध बढ़े हैं. इनके पीछे उन संगठनों का भी हाथ है, जिनके ऊपर समाज में अच्छे विचार फैलाने की ज़िम्मेदारी है, चाहे वे धार्मिक संगठन हों या स्वयंसेवी संगठन. वे लोगों के बीच परिवर्तन की दशा और दिशा, परिवर्तन का चरित्र बताते ही नहीं हैं. दरअसल, वे अपने चरित्र को परिवर्तन का चरित्र मानते हुए लोगों के बीच काम करते हैं, जिससे पूरा देश अराजकता के मुहाने पर खड़ा हो गया है.

सवाल न भाजपा का है, न कांग्रेस का, बल्कि सवाल देश का है. इसलिए देश की बुनियादी समस्याओं को लेकर एक बार फिर राजनीतिक तौर पर बहस होनी चाहिए. इसकी ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है. लेकिन, अगर यह अफवाह फैले कि नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह या फिर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे आंदोलनों के गर्भ से संपूर्ण आरक्षण व्यवस्था के ऊपर बहस कराना चाहते हैं और आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं और उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन रहें, तो बहुत सारे लोग हैं, जो इस बात को सत्य मान लेंगे. देश समस्याओं की वजह से अराजकता के मुहाने पर खड़ा है. ज्वालामुखी के फटने का इंतजार नहीं करना चाहिए. देश की बुनियादी समस्याओं पर राजनीतिक सहमति बनानी चाहिए और उन्हें हल करने के तरीकों के बारे में बहस करनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि राजनेता हमारी समस्या समझते हैं, हमारी समस्या से चिंतित हैं और उसका हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं.

यही लोकतंत्र है. यहां पर हम अपनी समस्याओं के हल के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं. यदि वे प्रतिनिधि उन समस्याओं को स्वीकार करने से इंकार कर दें, तो परेशानी पैदा होती है. मुझे लगता है कि देश में एक सार्थक राजनीतिक संवाद की ज़रूरत है. वरना सारे देश में गुजरात जैसे आंदोलन फूटेंगे, जो विचार आधारित नहीं होंगे, बल्कि समस्या आधारित होंगे और जिनका रिश्ता समाज के परिवर्तन से नहीं होगा, लेकिन जिनका रिश्ता उस समाज के वर्चस्व की लड़ाई में बदल जाएगा. समस्या विकराल है, समस्या का हल भी विकराल होना चाहिए और जिसकी शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ़ राष्ट्रीय बहस से हो सकती है.■

editor@chauthiduniya.com

कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया

मेघनाद देसाई

उफ़ा (रूस) में जब भारत एवं पाकिस्तान के निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत चल रही थी, तो उसी समय यह तय हो गया था कि नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ जाएगा और आतंकवादी गतिविधियों में भी तेज़ी आ जाएगी. दोनों देशों के बीच विवाद के लंबे इतिहास में जब भी शांति बहाली संभव लगने लगती है, तो ऐसी शक्तियां आड़े आ जाती हैं, जिनकी वजह से शांति प्रक्रिया रुक जाती है. दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) स्तर की प्रस्तावित बैठक (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया) एक उच्चस्तरीय बैठक थी. पिछले कई वर्षों से इस तरह की वार्ताएं होती रही हैं. ऐसी वार्ताओं में पाकिस्तान कश्मीर को अपना मुख्य मुद्दा मानता है, जो फ़िलहाल भारत के लिए मुद्दा नहीं है. भारत चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मसला सुलझाए. भारत का कोई भी प्रधानमंत्री कश्मीर मसले पर भारत के हितों से समझौता नहीं कर सकता. उसी तरह किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इतना अधिकार नहीं है कि वह वांछित आतंकवादियों को भारत के हवाले कर दे. परवेज़ मुशर्रफ ऐसे में एक अपवाद थे, क्योंकि वह एक सैन्य तानाशाह थे. अपनी किताब–दी पाकिस्तान पैराडॉक्स: इंस्टेबिलिटी एंड रिजिलीएंस में क्रिस्टोफे जेफ़रलो ने यह दिखाया है कि कैसे सेना वहां के शासक वर्ग के साथ मिलकर देश चलाती है. दोनों वर्गों की संस्कृति साझी है, दोनों के बीच रिश्तेदारियां हैं और दोनों के सोचने का तरीका एक है.

वर्ष 1971 के बाद लोकतंत्र की तीसरी वापसी पर इसे मज़बूती मिली है. इमरान खान के प्रदर्शन सेना को उकसाने के लिए किए जा रहे थे, ताकि वह सत्ता पर क़ब्ज़ा कर ले, लेकिन इसमें उन्हें नाकामी हाथ लगी. नवाज़ शरीफ को नेशनल असेंबली का पूरा समर्थन हासिल है, लेकिन इसके बावजूद देश में सत्ता के दो केंद्र बने हुए हैं. अफ़ग़ानिस्तान, परमाणु हथियार और कश्मीर से जुड़े मामले सेना के हाथ में हैं, बाक़ी मामले नवाज़ शरीफ देखते हैं. सेना देश में आतंकवाद के मसले से परेशान है. अभी हाल में आतंकवादियों ने पंजाब के गृह मंत्री की हत्या कर दी थी. लेकिन, यदि आतंकवादी सीमा पार करके भारत जाते हैं, तो इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है. इन सबके बावजूद पाकिस्तान की सिविल सोसायटी बदल रही है. वर्ष 1998 के पाकिस्तान दौरे के दौरान मैं जिस घर में गया, मुझसे यही कहा गया कि आप लोग कश्मीर छोड़ क्यों नहीं देते? अभी हाल में जब कश्मीर पर लिखी अपनी किताब पर व्याख्यान देने के लिए मैंने 10 दिन लाहौर और इस्लामाबाद में गुज़ारे थे, तो वहां लोगों में नरेंद्र मोदी के बारे में जानने की जिज्ञासा थी. उन्होंने भारत के सेक्युलर मीडिया को पढ़ रखा था, जिससे उन्हें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी एक आग उगलने और युद्धोत्तेजक बातें करने वाले व्यक्ति होंगे. वे अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज़ शरीफ को बुलाकर दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया और शांति के दूसरे प्रस्तावों का क्या अर्थ है?

जहां तक मैं समझाता हूं कि उन्हें लेकर संघ के कुछ उजड्ड तत्व भी हैरान हैं. यहां तक कि कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है कि सीमा पर होने वाले उल्लंघन को भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है. बेशक, कांग्रेस यह भूल गई होगी कि मनमोहन सिंह ने शांति की नीति अपनाने के लिए कितनी कोशिश की और उनकी पार्टी ने उनका कैसे साथ दिया. शर्म अल–शेख याद कीजिए. उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. भारत–पाकिस्तान दोस्ती के लिए सभी भारतीय नेताओं में सबसे अधिक प्रयास उन्होंने ही किए थे. वह नरेंद्र मोदी के हीरो हैं. राजनीति विरोधाभासों से पूर्ण है. अक्सर देखा गया है कि चरमपंथी (हार्ड लाइनर) समझे जाने वाले नेताओं ने स्थायी शांति स्थापित की है. वे यह परवाह नहीं करते कि उनके नर्म रुख पर उनकी आलोचना हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपतियों रिचर्ड निक्सन एवं रोनाल्ड रीगन ने क्रमशः चीन और गोर्वाचोव के साथ ऐसा ही किया था. अगले हफ्ते न सही, अगले साल न सही, लेकिन ऐसा संभव है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ स्थायी शांति बनाने में कामयाब हो जाएं. वह अपने संकल्पों में अटल हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

> वर्ष 1998 के पाकिस्तान दौरे के दौरान मैं जिस घर में गया, मुझसे यही कहा गया कि आप लोग कश्मीर छोड़ क्यों नहीं देते? अभी हाल में जब कश्मीर पर लिखी अपनी किताब पर व्याख्यान देने के लिए मैंने 10 दिन लाहौर और इस्लामाबाद में गुज़ारे थे, तो वहां लोगों में नरेंद्र मोदी के बारे में जानने की जिज्ञासा थी. उन्होंने भारत के सेक्युलर मीडिया को पढ़ रखा था, जिससे उन्हें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी एक आग उगलने और युद्धोत्तेजक बातें करने वाले व्यक्ति होंगे. वे अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज़ शरीफ को बुलाकर दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया और शांति के दूसरे प्रस्तावों का क्या अर्थ है?

इसका वृक्ष ऊंचा होता है तथा छाल धूसर एवं लम्बाई में फटी होती है. इसकी लकड़ी बहुत मजबूत, सुन्दर तथा धारीदार होती है. इसके पत्ते 15 सेमी लम्बे, नुकीले, कंगूरेदार, छूने में कड़े तथा मोटे मालूम होते हैं. इसके पत्र शीतकाल में झड़ जाते हैं और इसमें माघ से चैत्र माह तक नवीन पत्र निकल आते हैं. इसके पुष्प चैत्र या बैसाख माह में लगते हैं. ये श्वेत रंग के छोटे, शाखाओं के अग्र–भाग पर गुच्छों में लगे होते हैं. एक ही गुच्छों में पुंकेसर और स्त्रीकेसरयुक्त दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं. लगभग 30–40 वर्ष बाद अखरोट के पेड़ों पर फल लगते हैं.

रोगनाशक होता है अखरोट

अखरोट के कई प्रकार होते हैं.

1. जंगली अखरोट 30–40 मीटर तक ऊंचे, अपने आप उगने वाले तथा इसके फल का छिलका मोटा होता है.

2. कृषिजन्य अखरोट 15–25 मीटर तक ऊंचा होता है और इसके फल का छिलका पतला होता है. इसे कागजी अखरोट कहते हैं. इसकी मींगी श्वेत तथा स्वादिष्ट होती है. यह प्राय: पर्वतीय प्रदेशों अर्थात हिमालय में कश्मीर से मणिपुर तक मिलता है.

बाह्य स्वरूप

इसका वृक्ष ऊंचा होता है. इसकी छाल धूसर एवं लम्बाई में फटी होती है. इसके पत्ते 15 सेमी लम्बे, नुकीले, कंगूरेदार, छूने में कड़े तथा मोटे मालूम होते हैं. इसके पत्र शीतकाल में झड़ जाते हैं और इसमें मेघ से चैत्र माह तक नवीन पत्र निकल आते हैं. इसके पुष्प चैत्र या बैसाख माह में लगते हैं. ये श्वेत रंग के छोटे. शाखाओं के अग्र–भाग पर गुच्छों में लगे होते हैं. एक ही गुच्छों में पुंकेसर और स्त्रीकेसरयुक्त दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं. लगभग 30–40 वर्ष बाद अखरोट के पेड़ों पर फल लगते हैं. इसका पुष्पकाल एवं फलकाल फरवरी से अगस्त तक होता है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

–अखरोट वात–शामक, कफ–पित्तवर्धक, मेध्य, दीपन, स्नेहन, अनुलोमक, कफ–निसारक, बलकारक, वृष्य एवं बृंहण होता है.

–अखरोट तैल मधुर, शीत, गुरु, वातपित्तशामक, कफकारक, केशों के लिए हितकर, अभिष्यंदी तथा रक्तदोष–शामक होता है.

–अखरोट जीवाणुनाशक, रक्तस्रावरोधक, तंत्रिका–अवसादक, विषाणुरोधी होता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

नेत्र रोग

1. नेत्र–ज्योतिवर्धनार्थ–दो अखरोट और तीन हरड़ की गुठली को जलाकर उनकी भस्म के साथ 4 नग काली मिर्च को पीसकर अंजन करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है.

मुख रोग

1. दन्त–विकार–अखरोट के छिलकों को जलाकर प्राप्त भस्म में थोड़ा सेंधानमक मिलाकर मंजन करने से दांत मजबूत होते हैं.

2. दंतरोग–अखरोट छाल को मुंह में रखकर चबाने से दांत के रोग तथा मुख की बामारियों में लाभ होता है.

3. तालुदाह–पेड़ की छाल का कल्क बनाकर लेप करने से तालुदाह में लाभ होता है.

4. दंतमूलगत रक्तस्राव–अखरोट छाल, तुम्बरू छाल, बकुल छाल तथा लता कस्तुरी बीज चूर्ण को समान मात्रा में लेकर चूर्ण कर लें. उस चूर्ण को दंतमूल में लेप कर, 10–15 मिनट रखकर, गुनगुने जल का कुल्ला करने से दांत वाले रक्तस्राव का स्तम्भन होता है.

कण्ठ रोग

1. गण्डमाला–5 ग्राम अखरोट छाल तथा पत्र को 200 मिली पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर 10–20 मिली की मात्रा में सेवन करने से तथा उसकी क्वाथ से ग्रंथियों का प्रक्षालन करने से गले की गांठों तथा घेंघा का श्मन होता है.

2. कण्ठप्रदाह–अखरोट की गिरी (5–10 ग्राम) का सेवन कण्ठप्रदाह में लाभकारी होता है.

वक्ष रोग

1. क्षतक्षीण–जीवक, काकोली, क्षीरकाकोली तथा अखरोट आदि द्रव्यों से बनाए अमृतप्राश घृत को 5 ग्राम की मात्रा में अग्निबल का विचार कर, प्रात: सायं सेवन करने से क्षतक्षीय में लाभ होता है.

2. अखरोट गिरी को आग में हल्का भूनकर चबाने से कास में लाभ होता है.

3. छिलके सहित अखरोट की भस्म बनाकर 500 मिग्रा की मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा सा अकरकरा रस व मधु मिलाकर प्रात: सायं सेवन करने से कास में लाभ होता है.

उदर रोग

1. अतिसार–5–10 ग्राम अखरोट पत्र एवं त्वक का काढ़ा बनाकर, 1/4 भाग शेष रहने पर, छानकर सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है.

2. 20–40 मिली अखरोट तेल को 250 मिली या अवाश्यकतानुसार दूध के साथ प्रात:काल पीने से कोष्ठ का स्नेहगन तथा मल का निर्हरण होता है.

3. विसूचिका– हैजा में जब कंपकपी तथा शरीर में ऐंठन हो तो अखरोट तेल की मालिश करने से लाभ होता है.

4. विबन्ध–अखरोट फल के 10 से 20 ग्राम छिलकों को 400 मिली जल में पकाकर, काढ़ा बनाकर , सुबह–शाम पिलाने से कब्ज में लाभ होता है.

5. प्रवाहिका–10–20 ग्राम अखरोट गिरी के सेवन से उदरशूल तथा प्रवाहिका में लाभ होता है.

6. कृमि–अखरोट फल तैल की वस्ति देने से उदरकृमियों का नि:सरण होता है.

7. 20–40 ग्राम मिली अखरोट त्वक क्वाथ अथवा पत्र क्वाथ को पीने से आंत्रकृमियों का निर्हरण होता है.

8. फल के 10 से 20 ग्राम छिलकों को 1 लीटर पानी में पकाकर अष्टमांश शेष काढ़ा बनाकर सुबह–शाम से भी अतिसार में लाभ हो जाता है.

गुदा रोग

1. अर्श–अखरोट तैल पिचु को गुदा में धारण करने से बवासीर के कारण उत्पन्न वेदना (दर्द) का शमन होता है.

2. रक्तार्श–2–3 ग्राम अखरोट फल छाल की भस्म को प्रात मट्ठे के साथ तथा सायंकाल जल के साथ सेवन करने से रक्त का बहना रुक जाता है.

वृक्कवस्ति रोग

1. प्रमेह– 50 ग्राम अखरोट गिरी, 40 ग्राम छुहारे और 10 ग्राम बिनौले की मींगी को एक साथ कूटकर थोड़े से घी में भूनकर, इसकी आधी मात्रा में मिश्री मिलाकर रखें, इसमें से 5 ग्राम नित्य प्रात: सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है. (चिकित्सकीय परामर्शानुसार सेवन करें).

प्रजनन संस्थान रोग

1. स्तन्यजननार्थ–100 ग्राम गेहूं की सूजी तथा 10 ग्राम अखरोट के पत्ते को पीसकर, दोनों को मिलाकर गाय के घी में पूरी बनाकर सात दिन तक खाने से स्तन्य (स्त्री दुग्ध) की वृद्धि होती है.

2. मासिकविकार–20–30 ग्राम अखरोट को त्वाक (छिलका) सहित कूटकर काढ़ा बनाएं. काढ़े में दो चम्मच शहद मिलाकर 3–4 बार पिलाने से मासिक धर्म की रुकावट में लाभ होता है. इससे मासिक के समय होने वाले दर्द में लाभ होता है.

त्वचा रोग

1. दाद– प्रात:काल बिना मंजन किए हुए अखरोट की 5 से 10 ग्राम गिरी को मुंह में चबाकर दाद पर लगाने से कुछ ही दिनों में दाद में लाभ होता है.

2. व्रण– अखरोट की छाल के काढ़े से घावों को धोने से लाभ होता है व इससे घाव जल्दी भर जाता है.

3. नारू–अखरोट की छाल को जल के साथ महीन पीसकर आग पर गर्म कर नहरूवा की सूजन पर लेप करने से तथा उस पर पट्टी बांध कर खूब सेंक देने से 10–15 दिन में नारू में लाभ होता है.

4. अखरोट की छाल को पानी में पीसकर और गर्म कर नारू के घाव पर लगाएं.

5. दद्रु–5 से 10 ग्राम अखरोट बीज कल्क का लेप करने से दद्रु का शमन होता है.

6. दुष्टव्रण–10 ग्राम अखरोट बीज के सूक्ष्म कल्क को पिघले मोम या तैल के साथ मिलाकर लेप करने से शीघ्र घाव, विसर्प, खुजली आदि में लाभ होता है.

7. क्षुद्र कुष्ठ–अखरोट त्वक एवं पत्र को पीसकर लगाने से घाव, विसर्प, खुजली आदि में लाभ होता है.

मानस रोग

1. मस्तिष्क दुर्बलता–अखरोट की गिरी को 25 से 50 ग्राम तक की मात्रा में नित्य खाने से दिमाग शीघ्र ही सबल हो जाता है.

2. अर्दित–अखरोट के तेल की मालिश कर, वात हर औषधियों के काढ़े से बफरा (स्वेदन करने) देने से अर्दित में लाभ होता है.

3. अपस्मार–अखरोट गिरी को निर्गुण्डी के रस में पीसकर अंजन करने से और 4–6 बूंद प्रतिदिन प्रात:काल खाली पेट नाक में डालने से मिर्गी में लाभ होता है.

सर्व–शरीर रोग

1. वात रोग– अखरोट की 10 से 20 ग्राम ताजी गिरी को पीसकर वेदना–स्थान पर लेप करें, कपड़ा लपेट कर उस स्थान पर सेंक देने से शीघ्र पीड़ा मिट जाती है. गठिया पर इसकी गिरी को नियमपूर्वक सेवन करने से लाभ होता है.

2. शोथ–250 मिली गोमूत्र में 10 मिली अखरोट तैल मिलाकर पिलाने से सर्वांगशोथ (सारे शरीर पर आने वाली सूजन) में लाभ होता है.

3. वात–जन्य सूजन–अखरोट की 10 से 20 ग्राम गिरी को कांजी में पीसकर लेप करने से वातज शोथ में लाभ होता है.

4. बलवर्धनार्थ–10 ग्राम अखरोट गिरी को 10 ग्राम मुनक्का के साथ नित्य प्रात: खिलाना चाहिए. इससे शारीरिक व मानसिक बल की प्राप्ति होती है व पेट भी ठीक रहता है, यदि न पचे तो इसकी मात्रा कम कर दें.

विष चिकित्सा

1. अहिफेन विष–20 से 30 ग्राम तक अखरोट की गिरी खाने से अफीम का विष और भिलावे के उपद्रव शांत हो जाते हैं.

प्रयोज्यांग– फल तैल, बीज, छाल, पत्र, फल गिरी, फल के छिलके तथा भस्म.

मात्रा–गिरी 10–20 ग्राम त्वक क्वाथ 20–40 ग्राम, चिकित्सक के परामर्शानुसार.■

आचार्य बालकृष्ण

टीचर या डॉक्टर समय से न आएं तो क्या करें

सरकारी अस्पताल या स्कूल जनता के पैसे से चलते हैं. यानी, जनता के कर से ही इन संस्थानों के शिक्षकों या डॉक्टरों को वेतन मिलता है या अन्य खर्चे चलते हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि सरकारी अस्पतालों या स्कूलों में जनता को बेहतर सुविधा मिले. लेकिन, हालात ठीक इसके उलट हैं. सरकारी अस्पतालों या स्कूलों को लेकर यह आम शिकायत रहती है कि यहां पर स्तरीय सुविधा नहीं मिलती. शिक्षक या डॉक्टर सही समय पर नहीं आते. सवाल है कि इसका उपाय क्या है? इसका एक सरल उपाय यह है कि आप सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन देकर यह जान सकते हैं कि आपके इलाके के स्कूल या अस्पताल में कितने डॉक्टर या शिक्षक तैनात हैं. उनकी हाजिरी का समय वगैरह का पता कर सकते हैं. इस संबंध में नीचे एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं.

सेवा में
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय

मैं अपने गांव/कस्बे/शहर में स्थित ..... स्कूल/अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता/चाहती हूं:

1. उपरोक्त संस्थान में कुल कितने कर्मचारी हैं. उन सभी कर्मचारियों की एक सूची प्रदान करें, जिसमें उनके बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई गई हो:

नाम
पद
कार्य भार/ज़िम्मेदारी का विवरण
वर्तमान कार्यालय में कब से कार्यरत हैं
प्रतिदिन ड्यूटी पर आने व जाने का समय

2. उपरोक्त सभी कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की पिछले छह महीने की प्रति मुझे उपलब्ध कराएं.

3. अगर कोई कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचता है या बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो विभाग में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है. कृपया इस संबंध में नियमों/दिशा–निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं.

4. पिछले छह महीने में उपरोक्त में से कितने कर्मचारियों के खिलाफ देर से आने या अनुपस्थित रहने के मामले में उपरोक्त व्यवस्था के तहत क्या कार्रवाई हुई है, उसका पूरा विवरण व उस संबंध में पारित किए गए आदेशों/निर्देशों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

5. कृपया उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा पिछले छह महीने में लिए कुल अवकाशों (साप्ताहिक अवकाश व अन्य कार्यालय अवकाश दिवसों को छोड़कर) का विवरण उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपया अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्डधारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोकसूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई–मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है–

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश पिन–201301
ई–मेल: rti@chauthiduniya.com

कश्मीर ऊफ़ा घोषणा में अगर शामिल नहीं किया गया तो यह किसकी ग़लती है? सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस समय इससे भी बड़ा मुद्दा आतंकवाद है. इसलिए इसे ही प्राथमिकता देकर बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरी मीटिंग को कश्मीर समस्या तक ले जाना चाहिए था. यह जगजाहिर है कि जब भी दोनों देशों के राजनयिकों के बीच मुलाकात होनेवाली होती है, पहले से ही विभिन्न मुद्दों पर एजेंडा तैयार होता है. एक–एक शब्द को सोच–समझकर तैयार किया जाता है. वार्ता में शामिल होने वाले लोगों का चयन भी बहुत सोच–समझकर किया जाता है.

भारत-पाक वार्ता रद्द

आख़िर इसके लिए ज़िम्मेवार कौन है

भारत और पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की वार्ता पर पूरे विश्व की नजरें थीं, लेकिन पाकिस्तान ने वार्ता के ऐन पूर्व अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अज़ीज़ को भारत भेजने से इंकार कर भारत के भरोसे को शर्मिंदा कर दिया. पाकिस्तान न आतंकवाद पर बात करना चाहता है, न हुर्रियत नेताओं से मिलने की जिद छोड़ता है. हिमाकत देखिए कि जब भारत द्वारा उसके इस कदम का विरोध किया जाता है, तो वह परमाणु बम की धमकी भी दे देता है. सवाल यह उठता है कि भारत-पाकिस्तान के बीच होनेवाली यह वार्ता क्या भारत सरकार की विदेश नीति की असफलता थी या पाकिस्तान की चिरपरिचित धोखेबाजी?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आख़िरकार भारत–पाक राष्ट्रीय सुरक्षा स्तर की वार्ता स्थगित हो ही गई. इधर बात रुकी नहीं कि दोनों देशों के बीच आरोप–प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया. जब भी भारत–पाक बातचीत की उम्मीद बंधती है, दोनों देशों की जनता एक नई उम्मीद के साथ अच्छे संबंधों की प्रतीक्षा करते हैं. लेकिन पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन और भारत में तबाही मचाने वाले दुश्मनों को जिस तरह से पाकिस्तान शरण देता रहा है, उससे उत्पन्न समस्या को हम सिर्फ बातचीत के रास्ते ही सुलझा सकते हैं, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान बातचीत से भी ऐन वक्त पर पीछे हट जा रहा है. यही कारण है कि भारत की कोई भी कोशिश आज तक बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सकी.

पाकिस्तान का शुरू से ही यह दुर्भाग्य रहा है कि इस देश को आज तक राजनीतिक स्थिरता नहीं हासिल हो पाई. पूरा देश आतंकवादियों का पनाहगाह बन चुका है. दूसरे शब्दों में पाकिस्तान को आतंक की नर्सरी कहना गलत नहीं होगा. आए दिन पाकिस्तान में जगह–जगह धमाके होते रहते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते रहे हैं. कारण कि इस देश के नेताओं ने आतंकवाद को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया. इसलिए पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश भारत के लिए भी सिरदर्द बनता रहा. यही कारण है कि भारत भी पाक प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होता गया. अब सवाल यह है कि आख़िर यह राजनयिक वार्ता आरोप–प्रत्यारोप और कटुता पर आकर कैसे ख़त्म हो गई? आखिर क्यों पाकिस्तान खुद वार्ता से पीछे हटता है और भारत को परमाणु बम की धमकी देता है? राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि इस मुलाक़ात का बाक़ायदा एजेंडा तो तैयार हुआ, लेकिन इस पर पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब नहीं आया. भारत ने जो एजेंडा पाकिस्तान को भेजा, अगर इस एजेंडे पर पाकिस्तान ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया था तो फिर इस वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए और क्या बेहतर रास्ता अपनाया गया? जब ऊफ़ा में बातचीत दोबारा शुरू करने के निर्णय पर मुहर लग गई थी तो दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों को क्या यह याद

नहीं था कि इससे पूर्व वार्ता किस बात पर ख़त्म हुई थी या यह बातचीत का सिलसिला किस बात पर अटक गया था. जब दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऊफा में बातचीत करने का संकल्प लिया था तो रणनीति क्या होगी, किन–किन मुद्दों पर बातचीत होगी, कौन–कौन सी समस्याएं प्राथमिकता के साथ उठाई जाएंगी? क्या यह सब उस समय तय नहीं किया गया था और अगर यह सवाल ही महत्वपूर्ण नहीं बनाया गया तो फिर यह राजनयिक स्तर पर सबसे बड़ी हार है.

कश्मीर ऊफ़ा घोषणा में अगर शामिल नहीं किया गया तो यह किसकी ग़लती है? सारी दुनिया जानती है कि कश्मीर दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस समय इससे भी बड़ा मुद्दा आतंकवाद है. इसलिए इसे ही प्राथमिकता देकर बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरी मीटिंग को कश्मीर समस्या तक ले जाना चाहिए था. यह जगजाहिर है कि जब भी दोनों देशों के राजनयिकों के बीच मुलाकात होनेवाली होती है, पहले से ही विभिन्न मुद्दों पर एजेंडा तैयार होता है. एक–एक शब्द को सोच–समझकर तैयार किया जाता है. वार्ता में शामिल होने वाले लोगों का चयन भी बहुत सोच–समझकर किया जाता है.

इस संदर्भ में एक और बात आम भारतीयों के ज़हन में आती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नवाज़ शरीफ़ दोनों ही टेलीफोनिक संपर्क में रहते हैं. दोनों ईद, होली, दीवाली और क्रिकेट मैच की जीत पर एक–दूसरे को मुबारकबाद देते हैं. जब दोनों को ही नज़र आ रहा था कि मुलाक़ात ख़तरे में पड़ सकती है तो फोन पर बातचीत क्यों नहीं की गई. एजेंडे पर दोनों की ही सहमति नहीं थी तो फिर बातचीत को कुछ समय के लिए रद्द किये जाने की बात करनी चाहिए थी. पाकिस्तान ने जिस प्रकार अंतिम निर्णय ले लिया कि बातचीत स्थगित की जा रही है और सरताज अज़ीज़ ने परमाणु शक्ति होने की धमकी तक दे डाली. सरताज अज़ीज़ गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए यह भी कहते रहे कि अब पाकिस्तान वार्ता के लिए पहल नहीं करेगा. सरताज अज़ीज़ यह भूल गये हैं कि दोनों देशों में स्थिरता रहे और दोनों अच्छे पड़ोसियों की तरह बर्ताव करें, इसकी पहल हमेशा भारत की ओर से ही हुई है. अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर बार स्वयं ही संबंध बेहतर बनाने पर पहल की है. अगर वर्तमान सरकार संबंध बेहतर बनाने में गंभीर न होती तो नरेन्द्र मोदी अपनी ताजपोशी में नवाज़ शरीफ़ को आमंत्रित न करते. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का औचित्य इस संदर्भ में स्पष्ट था, इन्होंने इस बार की बातचीत को आतंकवाद पर केन्द्रित किया था. हालांकि भारत पाकिस्तान के साथ अन्य विवादित मुद्दों पर भी बात करना चाहता था, जिसे शांति की दिशा में काबिलेतारीफ कहा जा सकता है. पिछले 2 महीनों के दौरान 100 से अधिक घुसपैठ की घटनाएं हो चुकी हैं. जिंदा आतंकवादी नवेद पकड़ा गया है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता. आतंकवादी खुद स्वीकार रहा है कि वह पाकिस्तान का नागरिक है, लेकिन पाकिस्तान की थोथी दलील देखिए कि वह अपने नागरिक को ही पाकिस्तानी होने से इंकार कर रहा है. एनएसए स्तरीय इस वार्ता के स्थगित होने के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों और सीमा रक्षकों के बीच अगली निर्धारित मुलाक़ातें भी खटाई में पड़ गई हैं. दोनों देशों के सेना मिलिट्री ऑपरेशन के प्रमुखों के बीच 6 सितंबर को मुलाक़ात का प्रस्ताव दिया गया था. इसके अलावा भारतीय सीमा सुरक्षा बलों और पाकिस्तानी रेंजर्स के अधिकारियों को भी इन्हीं दिनों में मुलाक़ातें करनी थीं. अब यह सब शायद ही हो पाए. पाकिस्तान ने आखिरी समय में जिस तरह से एनएसए स्तर की वार्ता को स्थगित कर दिया, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई थी कि पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज पर भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भारी पड़ेंगे. इस बात की जानकारी हमें पाकिस्तानी सूत्रों से ही मिलती है. दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच प्रमुख समस्या आतंकवाद की है, लेकिन पाकिस्तान इसे कोई समस्या मानता ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार आतंकवाद पर वार्ता के लिए अडिग थी और इस मुद्दे पर जिस तरह से पाकिस्तान अपना रवैया दिखा रहा था, उससे खुद

फोटो–प्रभात पाण्डेय

पाकिस्तान को ही लगने लगा था कि वह आतंकवाद के मुद्दे पर घिर सकता है. पाकिस्तान की एक और जिद्द भारत को नागवार गुजरी और वह थी हुर्रियत नेताओं से मिलने की जिद्द. इन सारे बिंदुओं पर पाकिस्तान ने भारत के समझ खुद को घिरता हुआ पाया. इसलिए उसने वार्ता रद्द करना ही उचित समझा. सारे बिंदुओं पर भारत वार्ता के लिए तैयार बैठा था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के भरोसे को शर्मिंदा किया. कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, उसके साथ बहुत सोच–समझकर कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय या घरेलू मंचों पर भारत की किरकिरी न हो.■

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

दानवी पिशाच अल्बर्ट फिश

इंसानों को मारकर खाने की खबरों पर भले ही आप यकीन नहीं करें, लेकिन अभी भी देश और दुनिया के सामने ऐसे कुछ मामले आते रहते हैं, जिनको पढ़ने के बाद लगता है कि नरभक्षी इंसान अभी भी इस दुनिया में हैं. इसी तरह की घटना में एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही माता–पिता की हत्या कर दी और उनके शव के टुकड़े पकाने व भूनने के बाद उन टुकड़ो को खाया और जो बच गया उसे लंच बॉक्स में भर कर फ्रीज में रख दिया.

दरअसल, इंसानी मांस का सेवन दुनिया में सबसे घृणित कार्य है. ऐसी घटनाएं किसी भी सामान्य इंसान का हृदय विचलित कर देती हैं. इसी तरह के एक क्रूर नरभक्षी इंसान अल्बर्ट फिश के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसे बच्चों का उत्पीड़न करने में विशेष सुख मिलता था. बच्चों के साथ बलात्कार करना और उनका मांस खाना इसकी आदत में शुमार था. अल्बर्ट फिश 1870 में वाशिंगटन डीसी में पैदा हुआ. उसे ग्रे मैन, वेयरवोल्फ ऑफ वेस्टेरिया और ब्रुकलिन वैम्पायर के नाम से जाना जाता था. उस पर तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों के साथ अत्याचार करने का इल्जाम लगा था. इसके बावजूद उसने सिर्फ तीन कत्ल करने की बात कबूली. अल्बर्ट के मानसिक बीमारी का एक लंबा इतिहास रहा है. उसके माता–पिता ने उसे कम उम्र में ही छोड़ दिया और वह

एक अनाथालय में पला–बढ़ा. अल्बर्ट फिश सबसे पहले चर्चा में आया 25 मई 1928 में, जब उसने एक अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा. अल्बर्ट अंशकालिक काम की तलाश में 18 वर्षीय एडवर्ड बड से मिला तो उसने उसे नौकरी देने का आश्वासन दिया. अल्बर्ट फिश को अपना शिकार मिल गया था. इस बीच फिश की नजर उसकी छोटी बहन ग्रेसी बड पर गई, जो की मात्र 10 वर्ष की थी. अल्बर्ट अपने सौम्य और विनम्र व्यवहार से एडवर्ड बड के परिवार वालों का दिल जीत लिया. एक दिन शाम को उसने ग्रेसी को अपनी भतीजी की जन्मदिन पार्टी में ले जाने के लिए उसके मां–बाप से अनुमति मांगी.

एक उम्रदराज व्यक्ति पर बिना किसी शक के उन्होंने इजाजत दे दी. उस दिन के बाद से ग्रेसी कभी घर नहीं लौटी. उसके साथ क्या हुआ, यह भी कोई नहीं जान सका. कुछ दिनों के बाद ग्रेसी के मां–बाप को एक गुमनाम सा पत्र मिला, जिसे पढ़ने के बाद किसी भी सामान्य इंसान की रूह कांप जाए. दरअसल, वह पत्र अल्बर्ट ने ही लिखा था, जिसमें उसने ग्रेसी के साथ किए गए हैवानियत का चित्रण किया था. पत्र पढ़ने के बाद पुलिस ने अल्बर्ट के खिलाफ जांच शुरू की. पत्र के आधार पर पुलिस ने अल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया. 16 जनवरी, 1936 को अदालत ने अल्बर्ट की हैवानियत के लिए उसे मौत की सजा दी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त खबरें

गंगा की सफाई करेगा जर्मनी

गंगा से भारत के लोगों का आत्मिक रिश्ता है. भारतीयों के लिए इस मामले में एक खुशी की बात यह है कि जर्मनी ने निर्मल गंगा अभियान का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है. जर्मनी ने राइन नदी को साफ करने में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी को उत्तराखंड में गंगा नदी के एक हिस्से के पुनर्जीवन में प्रयोग करने की पेशकश की है. राइन नदी को यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक माना जाता है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जर्मनी की इस पेशकश के बारे में बताया. सुषमा ने कहा कि उनके जर्मन समकक्ष फैंक वाल्टर स्टेनमेयर ने उनके साथ दो घंटे तक चली बैठक के दौरान उत्तराखंड में गंगा की सफाई करने का प्रस्ताव किया. सुषमा ने अपने जर्मन समकक्ष के साथ बातचीत के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सम्पूर्ण आयामों की समीक्षा की. सुषमा ने कहा कि जर्मन विदेश मंत्री ने मुझे बताया कि आप गंगा को मां कहते हैं. हमने राइन नदी को साफ किया है. राइन पिता के समान हैं और गंगा मां हैं.■

यूसुफ रजा गिलानी गिरफ्तार हो सकते हैं

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी हुआ है. पाकिस्तान की एंटी–करप्शन कोर्ट ने करोड़ों रुपए के स्कैम के मामले में यह अरेस्ट का ऑर्डर दिया है. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता गिलानी के अलावा उनकी ही पार्टी के मखदूम अमीन फाहिम के खिलाफ भी गैरजमानती वॉरंट जारी हुआ है. कोर्ट ने यह ऑर्डर फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी (एफआईए) की ओर से पेश की गई चार्जशीट के बाद दिया है. एफआईए की ओर से पेश चार्जशीट में गिलानी और फाहिम पर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (टीडीएपी) में करोड़ों रुपए के स्कैम से संबंधित 12 केस का जिक्र है. एफआईए ने पीपीपी के इन दोनों पीपीपी नेताओं के अलावा टीडीएपी के कुछ पूर्व और मौजूदा सीनियर अफसरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है. इन सभी पर फेक कंपनियों की मदद से पैसों के लेनदेन का आरोप है. बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने गिलानी और फाहिम के खिलाफ कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी किया था.■

पहली बार सामने आया आईएस आतंकी जिहादी जॉन का चेहरा

कंप्यूटर प्रोग्रामर से आतंकवाद की दुनिया में कदम रखने वाला खूंखार आतंकी जिहादी जॉन एक वीडियो में यह धमकी देते दिखाई दिया है कि वह ब्रिटेन लौटकर लोगों के सिर कलम करेगा. इस वीडियो में पहली बार वह बिना नकाब के नजर आया है. यह वीडियो लंदन के डेली मेल को मिला और इस वीडियो में खूखार आतंकी जिहादी जॉन काला टोप पहने हुए था. इस वीडियो में जिहादी जॉन कह रहा है कि वो इस्लामिक स्टेट के खलीफ़ा के संग ब्रिटेन लौटेगा और लोगों के सिर कलम करना जारी रखेगा. जिहादी जॉन एक ब्रिटिश नागरिक है और उसका नाम मोहम्मह एमवाज़ी है. फेस मैपिंग के एक्सपर्ट के मुताबिक, वीडियो में नज़र आ रहा शख्स और एमवाज़ी के चेहरे में कई समानताएं हैं. आतंकवाद के मामले में नाम आने के बाद से जिहादी जॉन छिपा हुआ है. वीडियो में जिहादी जॉन कहता है, मैं मोहम्मद इमवजी हूं. मैं खलिफा के साथ जल्द ब्रिटेन जाऊंगा. हम काफिरों को मारेंगे. मैं सिर कलम करूंगा. इससे पहले भी जिहादी जॉन इस तरह के वीडियो और ऑडियो जारी करके पश्चिमी देशों और उनके अरब साझेदारों को धमकी दे चुका है. इतना ही नहीं, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को भी निशाना बनाने की धमकी दी थी.■

बाबा उन तेलियों के व्यवहार से तनिक भी खिन्न हुए बिना निर्विकार भाव से मस्जिद आए और जल को तेल में परिवर्तित कर उससे उन्होंने मस्जिद में दीप जलाए. तेलियों ने छिपकर यह सब देखा और बाबा के इस चमत्कार को देखकर उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ. जब वह अपने इस बुरे कृत्य से दुखी होकर भविष्य में उसे न दोहराने का संकल्प लेकर क्षमा मांगने बाबा के पास आए, तो बाबा ने उनको क्षमा करते हुए सत्य बोलने और पारस्परिक विभेद मिटा कर एक-दूसरे की सहायता करने के लिए कहा. इसके बाद वे तेली मस्जिद में नियमित रूप से तेल देते रहे और अपनी संकीर्णता से बाहर निकल आए.

साईं वंदना

बाबा ने शिरडी क्यों छोड़ा

बहुत से भक्त केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा को निरंतर घेरे रहते थे. बाबा अपनी दयालुता के कारण जो कुछ भी उनके पास होता था, सब कुछ लोगों में बांट दिया करते थे, रुपया, पैसा, खाना आदि. धीरे-धीरे ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, जो कि बाबा की दयालुता का लाभ उठाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे. बहुतों की दृष्टि बाबा को प्राप्त होने वाली दक्षिणा एवं खाद्य पदार्थों पर होती थी. यहां तक कि बाबा के खाने के लिए जो भोजन आता था, वह भी लोग चाहते थे कि उनमें प्रसाद के रूप में बंट जाए.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

बाबा बार-बार कहते थे कि तेली की दीवार तोड़ दो, इसका अर्थ क्या है?

श्री साईं सच्चरित्र में लिखा गया है कि शिरडी में तेली रहते थे, जो मस्जिद में दीप जलाने के लिए बाबा को भिक्षा में तेल देते थे. एक बार उन्होंने अपने पास तेल होते हुए भी बाबा को तेल देने से मना कर दिया. बाबा उन तेलियों के व्यवहार से तनिक भी खिन्न हुए बिना निर्विकार भाव से मस्जिद आए और जल को तेल में परिवर्तित कर उससे उन्होंने मस्जिद में दीप जलाए. तेलियों ने छिपकर यह सब देखा और बाबा के इस चमत्कार को देखकर उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ. जब वह अपने इस बुरे कृत्य से दुखी होकर भविष्य में उसे न दोहराने का संकल्प लेकर क्षमा मांगने बाबा के पास आए, तो बाबा ने उनको क्षमा करते हुए सत्य बोलने और पारस्परिक विभेद मिटा कर एक-दूसरे की सहायता करने के लिए कहा. इसके बाद वे तेली मस्जिद में नियमित रूप से तेल देते रहे और अपनी संकीर्णता से बाहर निकल आए. मूलत: तेली की दीवार शब्दों का बाबा ने एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है. जो एक धार को दो बनाती है, वह है दीवार. जो दीवार लोगों को अलग कर देती है, वह लोभ, हिंसा और अहंकार से बनी हुई है. बाबा ने उन सबका संवरण करके उन्हें हटाने के लिए कहा ताकि लोगों की आत्मा पर पड़े हुए उनके कई जन्मों के संस्कारों की मैली दीवार हट सके और इस प्रकार चलते-चलते जब उनके सारे परदे हट जाएंगे और कोई परदा नहीं रहेगा तो व्यक्ति अपने में सबको और सबको अपने में देखेगा. कोई भी दीवार जो कि बाधक बनती है, नहीं रहेगी और वह अखंड सत्ता का अनुभव करेगा, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं.

स्वार्थी लोगों के कारण बाबा का मन उखड़ना

श्री साईं सच्चरित्र कहता है कि बाबा ने शिरडी छोड़कर अन्यत्र चले जाने के लिए कहा था पर तात्या आदि उन्हें वापस ले आए थे. बाबा का ऐसा करने के पीछे कारण क्या था.

श्री साईं सच्चरित्र में बाबा के शिरडी छोड़कर अन्यत्र जाने के बारे में जिक्र आया है. तत्कालीन कुछ भक्तों के अनुभवों में भी इसका उल्लेख हुआ है. शिरडी में रहते हुए जब बाबा की ख्याति दूर-दूर तक फैली, तो उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी. उनमें आध्यात्मिक लाभ की कामना से आने वाले भक्तों की तुलना में ऐसे भक्तों की संख्या अधिक थी, जो सदैव केवल व्यक्तिगत समस्याओं एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिए बाबा से फायदा उठाना चाहते थे. वे चाहते थे कि अपनी चमत्कारिक शक्तियों से बाबा उन्हें उनके रोगों एवं समस्याओं से मुक्त कर दें. उन्हें यह परवाह नहीं थी कि उनके वह मांग उचित है या अनुचित? वह चाहते थे कि बुरा कार्य करने पर भी बाबा से उन्हें संरक्षण मिलता रहे.

बहुत से भक्त केवल भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा को निरंतर घेरे रहते थे. बाबा अपनी दयालुता के कारण जो कुछ भी उनके पास होता था, सब कुछ लोगों में बांट दिया करते थे, रुपया, पैसा, खाना आदि. धीरे-धीरे ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, जो कि बाबा की दयालुता का लाभ उठाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे. बहुतों की दृष्टि कि बाबा को प्राप्त होने वाली दक्षिणा एवं खाद्य पदार्थों पर होती थी. यहां तक कि बाबा के खाने के लिए जो भोजन आता था, वह भी लोग चाहते थे कि उनमें प्रसाद के रूप में बंट जाए. बहुत से लोग तो अपने तो अपने बच्चों को ही द्वारकामाई भेज देते थे और बाबा अपनी अतिशय दयालुता के कारण अपना पूरा भोजन बांट देते थे और खुद भूखे रह जाते थे.

दिनों-दिन बाबा की ख्याति फैलने के कारण बाहर से आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ती गई और उसके साथ बाबा को प्राप्त होने वाली दक्षिणा की राशि भी बढ़ती गई. चूंकि बाबा सब कुछ बांट देते थे, यह जानकर कुछ धूर्त लोग भी स्वार्थ-साधन के लिए वहां जमा होने लगे और इसके लिए लोग अनुचित तरीके भी अपनाने लगे.

लेकिन बाबा जिस महत् उद्देश्य को लेकर आए थे, उस पर अपवाद-स्वरूप (म्हालसापति एवं श्री काका साहेब दीक्षित आदि जैसे)कुछ भक्तों को छोड़कर अन्य का इस पर ध्यान नहीं था कि बाबा अपना (सरकार) का जो खजाना लोगों में बांटना चाहते थे, लोग उसे छोड़कर दूसरी चीजों की मांग कर रहे थे. लोगों की तुच्छ भौतिक मांगो के सदंर्भ में बाबा ने कहा भी था. भाउ ये हमारा काम ना. जैसा कि श्री साईं सच्चरित्र में भी है कि लोग अपनी इच्छित वस्तुएं ही मांगते हैं. वह चाहते हैं कि उन्हें वह सब कुछ मिले जो वह चाहते हैं और वह नहीं, जो कि आध्यात्मिक निधि के रूप में बाबा उन्हें देना चाहते हैं.■

जारी

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

धर्म

पाताल भुवनेश्वर

जहां कलयुग के ख़त्म होने का रहस्य छिपा है

पाताल भुवनेश्वर में ही पाण्डवों ने तपस्या की और कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इसे पुन: खोजा. इस गुफा में प्रवेश का एक पतला रास्ता है, जो कि करीब 100 फीट नीचे जाता है. नीचे एक दूसरे से जुड़ी कई गुफाएं हैं जिन पर पानी रिसने के कारण विभिन्न आकृतियां बन गई हैं, जिनकी तुलना वहां के पुजारी अनेकों देवी-देवताओं से करते हैं. पाताल भुवनेश्वर गुफा का प्रवेश द्वारा बहुत पतला है, सीढियों द्वारा लोहे की जंजीर के सहारे धीर-धीरे सरक कर नीचे उतरना पड़ता है और केवल एक व्यक्ति एक बार में नीचे उतर सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक केन्द्र है. यहां देवदार के घने जगलों के बीच अनेक भूमिगत गुफाओं का संग्रह है, जिसमें से एक बड़ी गुफा के अंदर देवों के देव महादेव विराजमान हैं, जो पाताल भुवनेश्वर के नाम से विख्यात है. पाताल भुवनेश्वर का मंदिर अल्मोड़ा से 160 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी वादियों के बीच सीमान्त कस्बे गंगोलीहाट में बसा है. स्कंद पुराण ग्रन्थ में वर्णित पाताल भुवनेश्वर की गुफा में पत्थरों से बना शिल्प तमाम रहस्यों को खुद में समेटे हुए है. माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर में ही पाण्डवों ने तपस्या की और कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इसे पुन: खोजा. इस गुफा में प्रवेश का एक पतला रास्ता है, जो कि करीब 100

फीट नीचे जाता है और नीचे एक दूसरे से जुड़ी कई गुफाएं हैं जिन पर पानी रिसने के कारण विभिन्न आकृतियां बन गई हैं, जिनकी तुलना वहां के पुजारी अनेकों देवी-देवताओं से करते हैं. पाताल भुवनेश्वर गुफा का प्रवेश द्वारा बहुत पतला है, सीढ़ियों द्वारा लोहे की जंजीर के सहारे धीर-धीरे सरक कर नीचे उतरना पड़ता है और केवल एक व्यक्ति एक बार में नीचे उतर सकता है. गुफा में उतरते ही एक बड़े कमरे में लोग अपने आप को तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं की प्रतीकात्मक शिलाओं, प्रतिमाओं व बहते हुए पानी के मध्य में पाते हैं. आगे बढ़ने पर एक छोटा सा हवन कुंड दिखाई देता है. कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने इसी कुण्ड में सभी नागों को जला डाला, लेकिन तक्षक नाम का नाग बच निकला, जिसने बदला लेते हुए परिक्षित को मौत के घाट उतार दिया. हवन कुण्ड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी मिलती है. हवन कुण्ड के आगे गुफा में आप अपने आप को शेष नाग के ऊपर पर खड़ा पाएंगे और सिर के उपर शेष नाग का फन देखेंगे. आप को वास्तव में एहसास हो जायेगा कि कुदरत द्वारा तराशे गए पत्थरों में नाग फन फैलाए हैं. यहां पर भगवान शिव के द्वारा कटा हुआ भगवान गणेश के सिर जैसी आकृति मिलती है. उसके ऊपर चट्टानों से बना कमल का फूल है, जिससे पानी टपकते हुए मूर्ति पर पड़ता है. भगवान शिव की लीला स्थली होने के कारण उनकी विशाल जटाएं इन पत्थरों पर नजर आती है और साथ में शिव की तपस्या का कमण्डल, खाल सब नजर आती है. ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां साथ-साथ स्थापित हैं. पर्यटक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब छत के ऊपर एक ही छेद से क्रमवार पहले ब्रह्मा फिर विष्णु फिर महेश की इन मूर्तियों पर पानी टपकता रहता है और फिर यही क्रम दोबारा से शुरु हो जाता है. एक स्थान पर यहां चार खण्ड है, जो चार युगों अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग को दर्शाते हैं. इनमें पहले तीन आकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता. जबकि कलयुग का पिंड लंबाई में अधिक है और उसके ठीक ऊपर गुफा से एक पिंड नीचे की ओर लटक रहा है और इनके मध्य की दूरी पुजारी के कथानुसार सात करोड़ वर्षों में एक इंच बढ़ती है और पुजारी का कथन सत्य माने तो दोनों पिंडों के मिल जाने पर कलियुग समाप्त हो जाएगा. 19 वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित तांबे से मढ़ा शिवलिंग भी यहीं स्थित है. माना जाता है कि गुफा के आखिरी छोर पर पाण्डवों ने शिवजी के साथ चौपड़ खेला था. आश्चर्य की बात है कि जमीन के इतने अन्दर होने के बावजूद यहां घुटन नहीं होती बल्कि शांति मिलती है. ऐसे न जाने कितनी रहस्य और रोमांच से भरी चीजें पाताल भुवनेश्वर अपने में समेटे हुए है, जिसकी वजह से सैलानियों के बीच उसकी एक अलग पहचान है. कुछ लोग यहां श्रद्धा से, कुछ रोमांच के अनुभव के लिए और कुछ शान्ति की तलाश में यहां आते हैं. आप कभी भी पाताल भुवनेश्वर जा सकते हैं. पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए कई रास्ते हैं. यहां पहुंचने के लिए ट्रेन से काठगोदाम या टनकपुर होते हुए सड़क के रास्ते निजी वाहन के जरिए जा सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

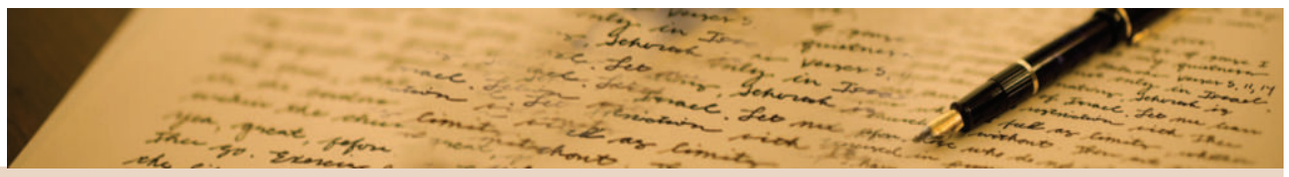

राजनीति में भ्रष्टाचार

यूपीए शासन काल में भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनमत को अपने पक्ष में करके बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन अब वही भ्रष्टाचार के आरोप मोदी सरकार पर लग रहे हैं, जिसे कांग्रेस मुद्दा बनाकर भाजपा के ऊपर हमला कर रही है. व्यापमं घोटाला प्रान्तीय स्तर से उठकर देशव्यापी हो गया है. कोई ऐसा राज्य नहीं है, जहां की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगा हो. भाजपा का व्यापमं मामले में कोई निर्णय न लेना, उसको यूपीए सरकार से पीछे कर देता है. मनमोहन सिंह सरकार में जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन मंत्रियों का इस्तीफा हुआ. लेकिन एनडीए सरकार में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मध्यप्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों पर ललित मोदी की मदद का आरोप है और वह अभी भी अपने पद पर कायम हैं. भ्रष्टाचार आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता के भीतर से ही पनप कर विषवृक्ष बना है, जो आज पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है.

-सत्य प्रकाश शिक्षक, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

अपराधियों का महिमामंडन उचित नहीं

यह किस तरह की राजनीति है कि मुंबई बम कांड की साजिश रचने वाले याकूब मेमन को फांसी न दी जाए, उसकी पैरवी के लिए दर्जनों वकील, नेता, पत्रकार व फिल्मी हीरो एक अभियान शुरू कर देते हैं. सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को सुनवाई करनी पड़ती है. शुक्र है कि नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अगर इस कुर्सी राजद, सपा, बसपा, जेडीयू या कांग्रेस का कोई नेता आसीन होता, तो याकूब को फांसी कदापि न होती. हद तो तब हो गई जब महाराष्ट्र समाजवदी पार्टी के उपाध्यक्ष फारुक घोसी ने अपने राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह यादव से याकूब की बीबी राहीन को राज्यसभा भेजने की मांग की. गौरतलब है कि 21 हत्याओं की दोषी फूलन देवी को नेता जी सांसद बना चुके हैं.

-राजकिशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

न्यायिक सुधार से ही लगेगी भ्रष्टाचार पर लगाम

व्यापमं घोटाले ने सिद्ध कर दिया है कि शासन तंत्र का प्रत्येक अंग भ्रष्टाचार में डूबा है. अगर सीबीआई बगैर किसी दबाव के व्यापमं मामले की निष्पक्ष जांच करती है, तो निश्चित तौर पर यह देश के सबसे बड़े घोटालों में शामिल हो जाएगा. व्यापमं घोटाले में चपरासी से लेकर बड़े-छोटे सरकारी कर्मचारी तक और नेता से लेकर मंत्री तक ने आम आवाम के धन को लूटा है. इसमें प्रदेश ही नहीं देश के अन्य प्रांतों के डॉक्टर, अधिकारी, शिक्षा माफिया आदि शामिल हैं. इससे साफ होता है कि लाखों लोगों को केवल कागज पर ही शिक्षा प्राप्त होती है. ऐसे में महात्वाकांक्षा के चलते ये घाटोले स्वाभाविक सी बात लगती है. इसे रोकने के लिए कौशल आधारित शिक्षा को तरजीह देनी होगी. धांधलियों में लिप्त सारे लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए. दोषी अभ्यर्थियों को अन्य परीक्षा से तो वंचित किया ही जाए, सरकारी सुविधायों और सामाजिक सुरक्षा के दायरे से भी बाहर कर देना चाहिए. व्यापमं घोटाले ने देश की छवि पर गहरा दाग लगाया है. खून पर खून का सिलसिला इस घोटाले के पीछे खड़े लोगों का कद बताता है. इसके पूरे सच को देश की जनता जानना चाहती है.

-अशोक निर्मोही, *दरभंगा, बिहार.*

ललित मोदी मामले पर इतना हल्ला क्यों

आईपीएल घोटाला के आरोपी ललित मोदी की मदद करके विदेश मंत्री सुषमा स्वाराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विवादों में ऐसी घिरी कि मानों राजनीति में भूचाल सा आ गया हो. विपक्ष सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग कर रहा था और हो सकता है विपक्ष इस मांग आगे भी कायम रखे. सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को पत्नी के इलाज के लिए पुर्तगाल भेजने में मदद की थी. जब उनसे इस पर सफाई मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की थी, क्योंकि उनकी पत्नी को कैंसर था. उन्होंने कहा कि मैंने केवल इतना कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा के दस्तावेज देती है, तो इससे हमारे दोनों देशों के रिश्ते खराब नहीं होंगे. विदेश मंत्री ने आगे कहा कि ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज जारी करने का फैसला ब्रिटेन के नियमों के तहत था. वसुंधरा राजे पर आरोप है कि उन्होंने ललित मोदी की आव्रजन अर्जी पर सहयोग किया था. ललित मोदी ने 2008 में उनके बेटे दुष्यंत की कंपनी में लगभग 11.63 करोड़ रुपये का निवेश किया था. ललित मोदी पर आईपीएल घोटाले और मैच फिक्सिंग का आरोप है, लेकिन उन पर यह आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं. सवाल उठता है कि अगर एक व्यक्ति पर आरोप है, तो उसके परिवार को आरोपी की दृष्टि से देखना उचित है? मानवीय आधार पर और कानून के अंदर रहकर किसी की मदद करना क्या गलत है? इस मुद्दे को मिर्च मसाला लगाकर संसद के कार्य को ठप कर देना कहां तक सही है?

-निधि अग्रवाल, *द्वारका, दिल्ली.*

यह कैसा देश प्रेम

जब तोप मुकाबिल हो-यह देशप्रेम नहीं, देशद्रोह है (24 अगस्त-30 अगस्त 2015) पढ़ा. संतोष भारतीय से मैं सहमत हूं कि सेना में जो सिपाही गए और जो आज मांग कर रहे हैं कि वन रैंक-वन पेंशन होनी चाहिए, हमारा अधिकार है, तो उनसे सवाल यह है कि क्या उन्हें किसी ने आमंत्रण भेजा था कि आप सेना में आइए और अपनी जान जोखिम में डालिए? अगर सेना के लिए वन पेंशन वन रैंक लागू होता है, तो देश पर करोड़ों रुपये का बोझ पड़ेगा और फिर अर्द्धसैनिक बल, पुलिस, सीआरपीएफ एवं आईएएस भी यही मांग उठाएंगे. अभी एक या दो वर्ष में सातवां पे कमीशन लागू होगा, फिर उसके बाद देश पर करोड़ों का बोझ पड़ेगा. इसलिए पहले देश हित हो, उसके बाद अपना हित.■

-मंगल यादव, *बक्सर, बिहार.*

अनंत विजय

साहित्य के मंच पर सियासत

बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है. सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है . सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोहरे चल रहे हैं . शह और मात का खेल जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरों ने चुनावी फिज़ा को संगीन बना दिया है. इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बेहद अहम है, लालू के लिए तो अस्तित्व को बचाने की लड़ाई ही है. लेकिन इन सबसे इतर भी एक वजह है जिसके कारण ये चुनाव चर्चित हो रहा है. विधानसभा की इस सियासी बाजी में इस बार साहित्यक और सांस्कृतिक संस्थाओं को भी मोहरा बनाया जा रहा है. जिन संस्थाओं पर भाषा और संस्कृति के विकास की जिम्मेदारी है, वो अपने मंच का इस्तेमाल राजनीति चमकाने के लिए करने की इजाजत दे रहे हैं. ताजा मामला है दिल्ली का. दिल्ली की मैथिली भोजपुरी अकादमी ने दिल्ली में एक आयोजन किया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाषा से जुड़े साहित्यकारों, कलाकारों और अहम शख्सियतों का सम्मान करना था. इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था. यहां तक तो सब कुछ ठीक था. कोई भी अकादमी किसी भी राजनेता को साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए या सम्मान समारोह का गवाह बनने के लिए बुला सकती है. लेकिन क्या किसी भी राजनीतिक दल के नेता या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इस मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करने की इजाजत दी जा सकती है. दिल्ली की मैथिली भोजपुरी अकादमी के उद्देश्यों में राजनीतिक कार्यक्रमों के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है. ये राजनीतिक कार्यक्रम था भी नहीं. ये कार्यक्रम तो उस सरोगेट विज्ञापन की तरह था जो हमारे यहां टेलीविजन पर चलते या अखबारों में छपते हैं. शराब के विज्ञापन पर रोक है तो फिर शराब के नाम से ही पानी की बोतल बना लो और फिर उसके विज्ञापन से जनता को बताओ कि अमुक नाम से शराब भी है. इसी तरह से दिल्ली की मैथिली भोजपुरी अकादमी ने भी एक सरोगेट साहित्यक कार्यक्रम आयोजित किया था. इस कार्यक्रम में मंच पर जेडीयू और आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री बैठे थे. हाथ में हाथ डालकर ऊपर उठाकर नेताओं ने फोटो भी खिंचवाए और साथ होने का संदेश भी जनता को दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने मैथिली–भोजपुरी अकादमी के मंच से पूरी तरह से राजनीतिक भाषण दिया. नीतीश और केजरीवाल दोनों ने मैथिली भोजपुरी अकादमी के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जोरदार हमला बोला. बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयानों को खारिज किया बल्कि अपने तर्कों को सामने रखने के लिए लंबा वक्त भी लिया. नीतीश कुमार को मालूम था कि कार्यक्रम दिल्ली में है और केजरीवाल की मंच पर मौजूदगी सुर्खियां बनेंगी लिहाजा उन्होंने उस अवसर का बेहतरीन इस्तेमाल किया. दिल्ली के मुख्यमंत्री और मैथिली–भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी इस मंच से भारतीय जनता पार्टी, नरेन्द्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग आदि की आलोचना की. साहित्यक सम्मान नेपथ्य में चला गया. सारी चर्चा मोदी बनाम नीतीश–केजरीवाल पर आकर टिक गई. नीतीश और केजरीवाल की दोस्ती पर भी चर्चा शुरू हो गई. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल्ली की अन्य भाषाई अकादमियों के कर्मचारियों को भी काम पर लगाया गया था. ज़ाहिर है कि दिल्ली सरकार इस कार्यक्रम को बेहतर करना चाहती थी. कार्यक्रम में राजनेताओं को भी न्योता दिया गया था. उन राजनेताओं को भी जिनका मैथिली–भोजपुरी से कोई लेना–देना नहीं था. आयोजकों की मंशा साफ थी. इस कार्यक्रम को राजनीतिक रखना और दिल्ली और बिहार के मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मंच देना. उसमें मैथिली पंजाबी अकादमी सफल रही.

दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार ने मैथिली भोजपुरी अकादमी का गठन किया था तब उसका लक्ष्य था–मैथिली और भोजपुरी भाषओं व साहित्य–संस्कृति

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने मैथिली–भोजपुरी अकादमी के मंच से पूरी तरह से राजनीतिक भाषण दिया. नीतीश और केजरीवाल दोनों ने मैथिली भोजपुरी अकादमी के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जोरदार हमला बोला. बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयानों को खारिज किया बल्कि अपने तर्कों को सामने रखने के लिए लंबा वक्त भी लिया. नीतीश कुमार को मालूम था कि कार्यक्रम दिल्ली में है और केजरीवाल की मंच पर मौजूदगी सुर्खियां बनेंगी लिहाजा उन्होंने उस अवसर का बेहतरीन इस्तेमाल किया.

का उन्नयन व पल्लवन. इसके अलावा इस अकादमी के कार्य और उद्देश्यों की एक बड़ी लंबी फेहरिश्त बेवसाइट पर मौजूद है लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि इसके मंच से राजनीति होगी. नई बनी कमेटी ने इन दोनों भाषाओं के उन्नयन और पल्लवन के लिए क्या काम किया, ये तो अभी ज्ञात नहीं हो सका है क्योंकि सरकार की बेवसाइट अपडेट नहीं है. हां, इतना अवश्य हुआ कि केजरीवाल– नीतीश को एक साथ मंच पर लाकर अकादमी ने अपने अध्यक्ष का काम कर दिया. मैथिली–भोजपुरी अकादमी के मंच के इस दुरुपयोग पर मुझे हरिशंकर परसाई का एक लेख – हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं – का स्मरण हो आया है. अपने उस लेख में परसाईं जी ने कई चुटीले वाक्य लिखे हैं जो आज भी वर्षों बाद मौजूं हैं. मेरे नाम, काम, धाम सब बदल गए हैं. मैं राजनीति में शिफ्ट हो गया हूं. उसी लेख में हरिशंकर परसाई ने आगे लिखा है –पार्टी का नाम जनमंगल कांग्रेस होगा. नाम में जन या जनता या लोक रखने का आधुनिक राजनीति में फैशन चल पड़ा है. इसलिए हमने भी जन शब्द रख लिया. जनता से प्रार्थना है कि वो इसे गंभीरता से ना लें, इसे वर्तमान राजनीति का एक मजाक समझें. जनता कच्चा माल है. इससे पक्का माल विधायक–मंत्री आदि बनते हैं. पक्का माल बनाने के लिए कच्चे माल को मिटाना ही पड़ता है. हम जनता को विश्वास दिलाते हैं उसे मिटाकर हम ऊंची क्वालिटी की सरकार बनाएंगे. हमारा न्यूनतम कार्यक्रम सरकार में रहना है. तो क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली की मैथिली–भोजपुरी अकादमी राजनीति में शिफ्ट हो गई है. क्या वो पक्का माल बनाने के काम में लग गई है. क्या वो साहित्य संस्कृति के विकास के कामों को मिटाकर ऊंची क्वालिटी की सरकार बनाने में लग गई है? क्या उनका न्यूनतम कार्यक्रम सरकार बनवाना हो गया है? अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो ये बेहद चिंता की बात है. कम से कम मैथिली और भोजपुरी भाषा–भाषियों के लिए. पहले भी इन अकादमियों का राजनीति के लिए इस्तेमाल होता रहा है लेकिन इस तरह से खुले आम, अकादमी के मंच से राजनीतिक भाषण पहली बार हुआ है. दरअसल दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद इन भाषाई अकादमियों में उपाध्यक्षों की नियुक्तियां हुईं. सरकार ने अपने मनमाफिक लेखकों और पत्रकारों को इन पदों पर बैठाया. यह सरकार का विशेषाधिकार है कि वो अपने मनमुताबिक लोगों का चयन करें लेकिन इन पदों पर बैठे लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो भाषा और साहित्य के विकास के लिए कोई ठोस रूपरेखा बनाएं और उसको क्रियान्वित करें .

अब अगर हम दिल्ली के अलावा पूरे देश की भाषाई अकादमियों पर विचार करें तो लगभग सारी अकादमियां सरकारी कार्यक्रमों को ही बढ़ावा देती हैं. इन अकादमियों पर होनेवाला खर्च करदाताओं के खून पसीने की कमाई से अर्जित किए गए पैसों की बर्बादी है . इनका उद्देश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है, आदर्शवाद की तमाम बातें भी होती हैं लेकिन जब कार्यक्रमों को करने का वक्त आता है तो फिर राजनीतिक आकाओं की ओर देखा जाने लगता है. कभी मंत्री तो कभी मुख्यमंत्री की इच्छा पर कार्यक्रम तय किए जाते हैं, बहुधा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार हो उस पार्टी के विरोधियों को ना बुलाया जाए. इस चक्कर में कई बार कार्यक्रमों में भारी भरकम खर्च होने के बावजूद उससे भाषा और साहित्य को कुछ हासिल नहीं होता है. इन अकादमियों का गठन भाषा और साहित्य को बढ़ाना देने के लिए किया गया था लेकिन कालांतर में हुआ यह कि भाषा और साहित्य की बजाए ये अपने अपने सूबे के मुख्यमंत्रियों की छवि के विकास के लिए काम करने लगीं. नतीजा क्या हुआ कि ये अकादमियां राज्य सरकार के सूचना विभाग का एक्सटेंशन बन गईं और इसके सचिव वगैरह उस विभाग के अफसरों की तरह काम करने लगे. इन अकादमियों को चलाने के लिए कभी कभार अच्छे लेखकों का भी चयन हो जाता है लेकिन उन अच्छे लेखकों के सामने सरकारी बाबुओं से निपटने की बड़ी चुनौती होती है. सुविधाएं भी कम होती हैं. उपाध्यक्षों के लिए मात्र चार हजार रुपए महीने के मानदेय का प्रावधान है जो कि मेरी समझ से इस पद पर बैठनेवाले का अपमान है . या तो इसको अवैतनिक कर देना चाहिए या फिर सम्मानजनक राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए. वर्ना वही होगा कि अकादमी के कार्यक्रमों को राजनीतक मंच बनाकर उसके कर्ताधर्ता अपना रसूख बढ़ाने में लग जाएंगे, और यह एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत है जो न इन अकादमियों को खत्म कर दे सकती हैं.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

> केजरीवाल–नीतीश को एक साथ मंच पर लाकर अकादमी ने अपने अध्यक्ष का काम कर दिया. मैथिली–भोजपुरी अकादमी के मंच के इस दुरुपयोग पर मुझे हरिशंकर परसाई का एक लेख – हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं – का स्मरण हो आया है. अपने उस लेख में परसाईं जी ने कई चुटीले वाक्य लिखे हैं जो आज भी वर्षों बाद मौजूं हैं. मेरे नाम, काम, धाम सब बदल गए हैं.

साहित्यकार

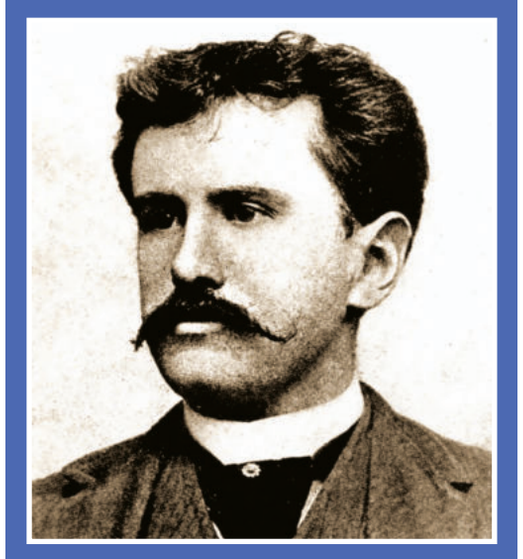

ओ हेनरी

ओ. हेनरी या विलियम सिडनी पोर्टर प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक थे. उनका जन्म11 सितंबर, 1862 के दिन ग्रीन्सबरो, उत्तर केरोलाइना में हुआ और मृत्यु 5 जून, 1910 को न्यू यॉर्क में. सोलह वर्ष की उम्र में उन्होने स्कूल छोड़ दिया, पर उनकी पढ़ने–लिखने की आतुरता नहीं छूटी. वह कहा करते थे कि सत्य की सच्ची अनुभूति केवल कथासाहित्य में ही हो सकती है. अपने निजी अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंच कर, ओ. हेनरी ने विद्वानों के इस विश्वास को फ़िर से स्थापित कर दिया कि ऐतिहासिक तथ्य की अपेक्षा, कल्पना ही सौन्दर्य का अधिक प्रभावशाली आविष्कार करती है. आज ओ. हेनरी की कहानियां, उनके युग के प्रतीक के रूप में ही पढ़ी जाती हैं. जिस प्रकार ब्रेट हार्ट की कथाएं, पश्चिमी सीमाप्रदेश के खान के मजदूरों, जुआरियों और ठेकेदारों को पुनर्जीवित कर देती हैं, उसी प्रकार ओ हेनरी की कहानियां सन् 1900 के आस–पास की दुनिया खड़ी कर देती हैं. अपनी कृतियों में जब उन्होंने घुड़सवारों का मजाक उड़ाया, तब स्पेन की लड़ाई के घुड़सवारों की याद जाती थी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक–समीक्षा

भारतीय भाषाओं में दलित चिंतन

अमृत शर्मा

हिंदी साहित्य में पिछले दो–तीन दशकों में अगर कोई सफल आंदोलन चला है तो वह दलित आंदोलन है. दलित लेखकों, चिंतकों और विमर्शकारों ने दलितों की सनातन समस्याओं पर गंभीरता से कलम चलाई है और सामाजिक न्याय का पुरजोर बिगुल फूंका है. अस्सी के दशक के बाद एक तरफ जहां भारतीय राजनीति में दलित और पिछड़े वर्ग का तेजी से राजनीतिक उभार हुआ, वहीं साहित्य में दलित और पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी मुखर हुई, जिससे राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी को लेकर दलितों की आवाज मुखर हुई. दलितों की आवाज को मुसलसल उठाते रहने वालों में से ही एक हैं बजरंग बिहारी तिवारी, जिन्होंने हाल ही में 'भारतीय दलित साहित्य: आंदोलन और चिंतन' शीर्षक से किताब लिखकर इस कड़ी में एक और अध्याय जोड़ा है. बजरंग बिहारी तिवारी लंबे समय से कथादेश पत्रिका में इसी विषय में नियमित कॉलम लिखते रहे हैं. साथ ही वे अन्य पत्र–पत्रिकाओं में भी दलित और पिछड़े समुदाय से जुड़े सवालों को उठाते रहे हैं.

बजरंग बिहारी तिवारी की यह किताब 'भारतीय दलित साहित्य:आंदोलन और चिंतन' हाल ही में शब्दारंभ प्रकाशन से छपकर आई है. यह किताब हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं के दलित लेखकों और चिंतकों के साक्षात्कार पर आधारित है. किताब में जिन चिंतकों को शामिल किया गया है उनमें– मराठी से शरण कुमार लिम्बाले, यशवन्त मनोहर, डॉ. गंगाधर पानतावणे, प्रो. सुखदेव थोरात, गुजराती से नीरव पटेल, कन्नड़ से डॉ. मोगल्ली गणेश और एल. हनुमन्तैय्या, तमिल से प्रो. के. ए. गुणशेखरन, बांग्ला से मनोरंजन व्यापारी, उर्दू से सरदार अनवर, हिंदी जगत से ओमप्रकाश वाल्मीकि, मलखान सिंह, कंवल भारती, प्रो. तुलसीराम, अशोक भारती और सुखनंदन हैं. मराठी साहित्यकार कॉमरेड शरद पाटिल के इंटरव्यू पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेख परिशिष्ट के रूप में दिया गया है. यह इंटरव्यू पिछले वर्ष उनके देहावसान से ठीक पहले का है जो प्रकाशित नहीं हो सका था. यह काफी विचारोत्तेजक है.

साक्षात्कारों का यह संग्रह दलित साहित्य का एक प्रतिनिधि संग्रह जैसा है जिसमें अलग–अलग भाषा–भाषी भारतीय समाजों में दलित चिंतन की विस्तृत झलक मिलती है, जिसमें आप दलित आंदोलन और साहित्य पर अखिल भारतीय बहसों से परिचित हो सकते हैं. मशहूर दलित लेखिका अनीता भारती के शब्दों में यह किताब 'दलित साहित्य की लाइब्रेरी' है जो दलित साहित्य के अध्येताओं के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी. दलितों का राजनीतिक और संघर्ष किन–किन पड़ावों से गुजरा है और उसे कहां तक ले जाने का प्रयत्न करना है, इससे जुड़े तमाम सवालों पर इस किताब में चिंतकों अपने–अपने तरीके से प्रकाश डाला है. हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में दलित विमर्श की क्या स्थिति है? दलितों की मुक्ति का रास्ता क्या हो सकता है? समाज में समता की लड़ाई में कौन सी बाधाएं हैं? दलित समाज का संघर्ष अब तक कहां पहुंचा है? दलित आंदोलन की दिशा और दशा कैसी है? दलित राजनीति बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को किस हद तक साकार करने में कामयाब रही है? मार्क्सवाद दलितों की मुक्ति में कितना सहायक हो सकता है? मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद में क्या मतभेद रहे? मार्क्सवाद और गांधीवाद दलितों के संघर्ष में कितने हद तक सहायक हो सके, नहीं हुए तो क्यों? दलित साहित्य किसे कहा जाए? सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ एक संघर्ष की अभिव्यक्ति को दलित साहित्य क्यों कहा जाना चाहिए? गैर दलितों द्वारा रचा गया साहित्य दलित साहित्य है कि नहीं? बाजारवादी–पूंजीवादी व्यवस्था में दलितों की क्या स्थिति होगी? दलित आंदोलन और चिंतन में महिलाओं के सवाल कितनी जगह बना सके हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको दलित चिंतकों की जुबानी इस किताब में मिलेंगे.

किताब–भारतीय दलित साहित्य आंदोलन और चिंतन
लेखक–बजरंग बिहारी तिवारी
प्रकाशन–शब्दारंभ

संग्रह की खास बात यह है कि इसमें भूमिका के सिवा बजरंग जी ने खुद अपने विचार कहीं नहीं रखे हैं. उन्होंने दलित समुदाय के संघर्ष के क्रम में उठने वाले तमाम सवालों को सिलसिलेवार ढंग से दलित चिंतकों के समक्ष रखे हैं और उसपर उनकी प्रतिक्रियाओं अथवा जवाबों को जस का तस पेश किया है. भूमिका में वे लिखते हैं– 'चिंतन आंदोलन को दिशा देते हैं तो आंदोलन चिंतन को गति व स्वरूप प्रदान करते हैं. फिर इनकी पारस्परिकता में भारतीयता का नया अध्याय रचा जाता है. दलित चिंतन और आंदोलन ने इसी तरह नई भारतीयता का निर्माण किया है. बुद्ध और अंबेडकर से शुरू करके वे समूचे दलित आंदोलन की विकास प्रक्रिया बताते हुए रेखांकित करते हैं कि 'दलित चिंतन, आंदोलन और लेखन को समझने की प्रक्रिया में यह किताब तैयार हुई है. दलित जागृति को समझने के लिए अखिल भारतीय परिपेक्ष्य सामने रखना आवश्यक है. अभी तक ऐसा कोई उल्लेखनीय अध्ययन, ऐसी कोई किताब मेरे देखने में नहीं आई. समूचे भारतीय दलित आंदोलन पर किताब लिखना कठिन है. तब इस अपेक्षा की पूर्ति साक्षात्कारों से हो सकती थी. इस मकसद से मैंने देश के अलग–अलग भाषा क्षेत्रों से अलग–अलग समय पर दलित आंदोलन और साहित्य के अधिकारी विद्वानों से बातचीत की.'

इस सिलसिले में तमाम मुद्दे, जिनपर आम तौर पर दलित विद्वानों में ही मतभेद देखने को मिलते हैं, उन पर तमाम दिग्गजों की बेबाक राय एक मंच पर सामने आई. इस संग्रह की मदद से तमाम सवालों पर एक राय कायम करने में यकीनन मदद मिलेगी. उम्मीद है कि एक संघर्षशील समाज के लिए, उसके अध्येताओं के लिए बजरंग बिहारी तिवारी की यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीर घाटी

जहां दूध की नदियां बहती थीं,
जहां गौरी शंकर रमते थे,
जहां फूलों में मादकता थी,
आज वहां पर बंटवारे की जाने
क्यों तैयारी है
आज हमारे कश्मीर की घाटी
क्यों बेचारी है
जिसके खातिर लाल बहादुर
सैनिक वीर शहीद हुये
जिस धरती पर गए मुखर्जी
कितने वीर शहीद हुए
आज उसी धरती पर खून
की नदियां बहती हैं
उग्रवाद की काली रातें
सूरज को भी छलती हैं
पूजा नमाज रोते हैं
ये कैसी बमबारी है
आज हमारे काश्मीर की
घाटी क्यों बेचारी है

आज हमारे कुछ साथी भड़के हैं.
रोज नए तामसे करते हैं.
चंद सिक्कों की खातिर
भारत माता को छलते हैं.
पर आग लगाने वाले देखों
तेरे भी घर जलते हैं.
मैं आह्वान करता हूं
अपने वीर जवानों से.
देश भक्त और सच्चे लोगों
अपने सभी किसानों से.
आओ शस्त्र उठाकर आओ
खेतों से खलिहानों से.
कूद पड़ो नापाक इरादों पर
निज तीर कमानों से.
इसे बचाने की हम
सब की पूरी जिम्मेदारी है.
आज हमारे कश्मीर की
घाटी क्यों बेचारी है.

रोहित पांडेय पेशे पत्रकार हैं. बीते लगभग चार वर्षों से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं.

कुन्नूर की यात्रा पर आये किसी भी पर्यटक को कुन्नूर–ऊटी की रेल सवारी को नहीं छोड़ना चाहिए. यह रेलगाड़ी नीलगिरी पहाड़ी रेल सेवा के तहत चलती है. दार्जिलिंग पहाड़ी रेलसेवा के साथ–साथ नीलगिरी पहाड़ी रेल सेवा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है. यह विश्व के कुछ उन खास स्थानों में से है, जहां पर रेल सेवा में रैक और पिनियन तन्त्र का प्रयोग किया जाता है. रास्ते में पड़ने वाले शानदार प्राकृतिक दृश्य यात्रियों को मन्त्रमुग्ध कर देते हैं. अगर आप कुन्नूर जायें तो सिम्स पार्क, डॉल्फिन नोज़, दुर्ग फोर्ट, लैम्ब्स रॉक, हिडेन वैली, कटारी फॉल्स और सेन्ट जॉर्ज चर्च स्थानों को देखना न भूलें.

मुकाम

टूरिज्म में बनाएं करियर

ट्रैवल प्रोफेशनल्स की डिमांड दुनिया में तेजी से बढ़ रही है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. टूरिज्म जैसे क्षेत्रों के उभरने से भी भारत को सैलानियों को आकर्षित करने में मदद मिल रही है. यही नहीं, अब तो इंडियन भी खूब सैर–सपाटा कर रहे हैं. ऐसे में टूरिज्म इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर भी क्रिएट हो रहे हैं. इस इंडस्ट्री में अच्छा करने के लिए दमदार कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है. साथ ही, देश–दुनिया की जानकारी भी ब्राइट फ्यूचर के लिए जरूरी है. इन चीजों के अलावा जिनकी जरूरत पड़ती है, वे हैं कस्टम सर्विस स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिसिजन मेकिंग स्किल्स. इस इंडस्ट्री में इतने प्रकार के काम हैं कि व्यक्ति कहीं न कहीं खप ही जाता है, लेकिन बढ़िया पैसा कमाने के लिए बढ़िया डिग्री भी जरूरी होती है. टूरिज्म प्रोफेशनल्स की बढ़ती डिमांड के कारण ही आज देश के तमाम जानेमाने इंस्टीट्यूट्स में टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री या इस सब्जेक्ट में डिप्लोमा के कोर्स उपलब्ध हैं. इस फील्ड में जो कोर्सेज प्रचलन में हैं, उनकी अवधि एक साल से लेकर दो साल तक की है. कुछ कोर्स एक साल से कम अवधि के भी हैं. मास्टर कोर्स दो साल का होता है. बाकी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स एक साल या इससे कम अवधि के होते हैं. टूरिज्म से रिलेटेड कोर्स 12वीं के बाद से ही उपलब्ध हैं. मास्टर्स के लिए आपका ग्रैजुएट होना जरूरी होता है. देश के कई चुनिंदा मैनेजमेंट स्कूल्स में भी टूरिज्म की पढ़ाई होती हैं, लेकिन वहां एडमिशन पाने के लिए आपको कैट–मैट के साथ–साथ ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी फेश करना पड़ता है.

कहां से करें पढ़ाई–इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट–नई दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म–श्रीनगर, उत्तराखंड, बीएचयू–वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर, केरल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल स्टडीज, हिमाचल यूनिवर्सिटी–शिमला, भारतीय विद्या भवन–नई दिल्ली सहित ये कुछ विश्वविद्यालय हैं, जहां टूरिज्म की पढ़ाई की जा सकती है. ■

फैशन दुनिया

भारत–पाकिस्तान सीमा विवाद भले ही राजनेताओं के बीच फंसा रहे, लेकिन यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दोनों ही देशों की संस्कृति एक है. इसी के मद्देनजर भारतीय फैशन डिजाइनर्स द्वारा निर्मित परिधानों का भारतीय मॉडल्स द्वारा नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में प्रदर्शन किया गया.

खाना पीना

सबको भाये बिहारी खुरमा

कहते हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू. जी हां, बिहार की राजनीति के साथ–साथ बिहार की मिठाइयां भी बहुत मशहूर हैं. बिहार की मिठाइयां इतनी आकर्षक और स्वादिष्ट होती हैं कि उन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. बिहार का आरा शहर अनेक मामलों में विश्व विख्यात है. आरा से जगजीवन बाबू, रामसुभग सिंह जैसी महान हस्तियां जुड़ी रही हैं. आरा जिला के उदवंतनगर गांव में बनती है बेल्ग्रामी मिठाई, जिसे लोग खुरमा के नाम से जानते हैं. खुरमा बिहार की सबसे मशहूर मिठाई है. खुरमा मिठाई को पसंद करने वाले लोग इसे दिल्ली, मुम्बई , बेंग्लुरु और मद्रास ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी ले जाते हैं. खुरमा को मिठाई के तौर पर ही नहीं, बल्कि प्रसाद के रूप में पूजा और त्योहारों में भी चढ़ाया और खाया जाता है.

खुरमा मिठाई बनाने की विधि:

सामग्री :

आटा : 2 कप

मैदा : 1 कप

घी : 4 चम्मच

चीनी : 2 कप

बनाने की विधि : मैदा और आटे में घी मिलाकर गूंद ले. उसके बाद 1 इंच की मोटाई लेकर उसे चौरस आकृति में काटें. खुरमा को गरम तेल में धीमी आंच पर तब तक तलें, जब तक सुनहरे रंग नहीं आ जाता. एक कड़ाई लें. उसमें चीनी और पानी आवश्यकतानुसार तब तक उबालें, जब तक चाशनी तैयार न हो जाये. तैयार की गई चाशनी में खुरमा को डूबोकर निकाल लें. आपकी मिठाई परोसे जाने के लिए तैयार है. जमकर मजे लें ■

सैर–सपाटा

खूबसूरत वादियों का शहर कुन्नूर

ऊटी हिल स्टेशन के नजदीक बसा एक छोटा शहर कुन्नूर है, जहां आने के बाद आप इसकी वादियों में खो जाएंगे और इस शहर के वातावरण से आपको तुरंत प्यार हो जाएगा. कुन्नूर इतनी शांत जगह है कि यात्रियों की चहल–पहल और शोरगुल के बावजूद इस स्थान की शांति भंग नहीं होती. इसीलिये इसे कभी न सोने वाली घाटी के नाम से नवाज़ा गया है. कुन्नूर की यात्रा पर आये किसी भी पर्यटक को कुन्नूर–ऊटी की रेल सवारी को नहीं छोड़ना चाहिए. यह रेलगाड़ी नीलगिरी पहाड़ी रेल सेवा के तहत चलती है. दार्जिलिंग पहाड़ी रेलसेवा के साथ–साथ नीलगिरी पहाड़ी रेल सेवा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है. ये विश्व के कुछ उन खास स्थानों में से है, जहां पर रेल सेवा में रैक और पिनियन तन्त्र का प्रयोग किया जाता है. रास्ते में पड़ने वाले शानदार प्राकृतिक दृश्य यात्रियों को मन्त्रमुग्ध कर देते हैं. अगर आप कुन्नूर जायें तो सिम्स पार्क, डॉल्फिन नोज़, दुर्ग फोर्ट, लैम्ब्स रॉक, हिडेन वैली, कटारी फॉल्स और सेन्ट जॉर्ज चर्च स्थानों को देखना न भूलें, क्योंकि यही कुन्नूर के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं. कुन्नूर की अर्थव्यवस्था यहां के फलते–फूलते चाय उद्योग पर निर्भर करती है. यहां के अधिकांश लोग चाय के उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री पर निर्भर हैं. घर की बनी चॉकलेट कुन्नूर की विशेषता है. आपको घर में बनी चॉकलेट लगभग हर घर में खाने को मिल जाएगी, जिसका स्वाद लाजवाब होता है. कुन्नूर बागवानी और फूल उद्योग के लिये भी प्रसिद्ध है. ऑर्किड और फूल वाले पौधों की कई दुर्लभ प्रजातियां यहां पर उगाई और बेची जाती हैं.हिल स्टेशन होने के कारण कुन्नूर अपने मौसम के लिये जाना जाता है.

कब जाएं

तापमान के लिहाज से देखें तो यहां का मौसम सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाता है, जबकि यहां की गर्मियां सुहावनी होती हैं.

कैसे पहुंचें

कुन्नूर पहुंचना बहुत आसान है. कोयम्बटूर से आप बस पकड़ कर गांधीपुरम पहुंचें. फिर वहां से कुन्नूर के लिये सीधी बस आपको मिल जाएगी. कोयम्बटूर से कुन्नूर की यात्रा में साढ़े तीन घंटे का समय लगता है. शानदार दृश्यों, घूमने–फिरने के पर्याप्त विकल्पों, चॉकलेट, बागानों और सुहवाने मौसम के साथ कुन्नूर छुट्टी बिताने वालों के साथ–साथ हनीमून पर आने वाले नवविवाहित जोड़ों का पसंदीदा स्थान है. ■

आईफोन यूज़र्स के लिए व्हॉट्सएप का वेब वर्जन

आईफोन यूजर्स के लिए आखिरकार अब व्हॉट्सएप का वेब वर्जन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है. अब आईफोन यूजर्स भी अपने पीसी या लैपटॉप पर व्हॉट्सएप चला सकेंगे. ये फीचर अभी सभी आईफोन यूजर्स तक नहीं पहुंचा है, लेकिन व्हॉट्सएप ने इसे रोलआउट करना शुरू कर दिया है. आईओएस यूजर्स डेस्कटॉप पर व्हॉट्सएप चलाने के

लिए अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में व्हॉट्सएपडॉटकॉम खोलना होगा. इसके बाद एक क्यूआर कोड स्कैन कर, जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखेगा, उसे मोबाइल व्हॉट्सएप से स्कैन करना होगा. इसके लिए आपके पास व्हॉट्सएप एप्लिकेशन का अपडेटेड वर्जन होना जरूरी है. मोबाइल में व्हॉट्सएप के मेन्यू में जाकर व्हॉट्सएप वेब ऑप्शन में आप इस कोड को स्कैन कर आसानी से डेस्कटॉप पर व्हॉट्सएप यूज कर पाएंगे. अगर आप अपने डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम के अलावा कोई दूसरा ब्राउजर यूज नहीं करते तो आप व्हॉट्सएप वेब का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ■

बाज़ार में नया

सोलर स्पोर्ट्स कार

ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियर जल्द ही एक शोर–रहित सोलर–इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का मॉडल पेश करने वाले हैं. यह हाइब्रिड–इलेक्ट्रिक कार है. यह कार मर्सिडीज़ बैंज एस–क्लास कूपे जितनी लंबी होगी. इसमें दो लोगों के बैठने की जगह होगी और कुछ सामान रखने की भी. इस कार की छत पर 75 वर्गमीटर के सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल लगे होंगे. इसके अलावा कार में लिथियम आयन बैटरी भी लगी होगी. इमोरटस नामक इस कार का कॉन्सेप्ट ईवीएक्स वेंचर्स ने मेलबर्न की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स और ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियरों और सोलर कार रेसरों के साथ तैयार किया है. कंपनी का दावा है कि यह स्पोर्ट्स कार संभालने में भी सहज होगी और प्रदर्शन के हिसाब से भी शानदार. कार को शून्य से 62 मील प्रति घंटे की रफ़्तार तक पहुंचने में 7 सेकंड से कम वक्त लगेगा. कार की अधिकतम गति 90 मील प्रति घंटा से ज़्यादा होगी. जिस दिन सूर्य की रोशनी ठीक–ठाक होगी, उस दिन कार 50 मील प्रति घंटा की रफ़्तार से चलेगी. उस समय ये रीचार्ज करने से पहले 340 मील तक की दूरी तय कर सकेगी. हालांकि यदि केवल सोलर पावर से ये कार चलाई जाए तो ये कार 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अनलिमिटेड यानी कितना भी फ़ासला तय कर पाएगी. ■

सबसे सस्ता 4जी स्मार्टफोन लेनोवो ए2010

लेनोवो ने भारतीय बाजार में अब तक का सबसे सस्ता 4जी स्मार्टफोन लेनोवो ए2010 लॉन्च किया है. यह भारत का पहला और सबसे किफायती 4 जी एलटीई डूअल–सिम स्मार्टफोन है. कंपनी ने इसकी कीमत 4,990 रुपए रखी है. फोन की बिक्री 3 सितंबर को पहली बार फ्लिपकार्ट पर की गई. लेनोवो ए2010 में 4.5 इंच रेज्युलूशन वाला डिसप्ले दिया गया है. यह एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप ओएस पर आधारित है. फोन 64 बिट 1 गीगाहर्ट्ज क्वॉड–कोर मीडियाटेक प्रोसेसर 1 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ है. एक्सटर्नल मेमोरी के लिए 32 जीबी तक माइक्रोएसडी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्सल रियर और 2 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा उपलब्ध होगा. कनेक्टिविटी के लिए डुअल सिम सपोर्ट, 4जी एलटीई, वाईफाई और ब्लूटूथ है. लेनोवो ए2010 की बैटरी 2,000 एमएएच की है. भले ही यह सुनने में कम लगता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि यह 4जी नेटवर्क पर 8.5 घंटे का टॉक टाइम देने में सक्षम है. फोन के लान्च पर लेनोवो इंडिया स्मार्टफोन के डायरेक्टर सुधीन माथुर ने कहा कि हम लेनोवो के द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं और आधुनिक तकनीक के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को कम बजट में आधुनिक तकनीक से लैस डिवाइस मिल सके और लेनोवो ए–2010 इसकी ओर हमारा पहला कदम है. इस फोन को मध्यवर्ग के युवा भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो लगातार किफायती दाम पर हाइ क्वालिटी उत्पादों की तलाश में रहते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

कुमार संगकारा का संन्यास

क्रिकेट के एक युग का अंत

डेढ़ दशक लंबे टेस्ट करियर में संगाकारा ने कई बेहतरीन पारियां खेलीं. टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा दोहरे शतक के सर डॉन ब्रैडमैन के 12 दोहरे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से महज एक कदम से चूक गए. क्रिकेट में विकेटकीपर की भूमिका को एक नया आयाम एडम गिलक्रिस्ट ने दिया था. एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज टीम की काया पलट कर सकता है, इस विचार को संगाकार और आगे ले गए. उनकी कमी श्रीलंकाई क्रिकेट को लंबे समय़ तक खलेगी.

नवीन चौहान

श्रीलंकाई क्रिकेट के राजकुमार, कुमार संगकारा अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते नहीं दिखाई देंगे. उनके संन्यास लेने के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया है. कोलंबो के पी सारा ओवल मैदान में भारत के खिलाफ श्रृंखला का दूसरा टेस्ट उनके क्रिकेट करियर का अंतिम टेस्ट था. इस मैदान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह एशिया का एकमात्र मैदान है जहां सर डॉन ब्रैडमैन खेले थे. हालांकि इस चैंपियन बल्लेबाज को हार के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा. ऐसा ही कुछ 2015 विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में भी हुआ था. वह संगकारा के एकदिवसीय क्रिकेट का आखिरी मैच था. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में उनकी विदाई सबसे धमाकेदार रही. उन्होंने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ खेले गए टी–20 विश्वकप के फाइनल में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाकर टी–20 करियर का समापन किया था. उनके संन्यास के बाद श्रीलंकाई टीम की जिम्मेदारी पूरी तरह नई पीढ़ी के हाथों में आ गई है. जुलाई, 2000 में संगाकारा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में पदार्पण किया था.जिस भारत के खिलाफ संगकारा ने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला उसी भारत के खिलाफ संगकारा ने अपना पहला टेस्ट शतक साल 2001 में गॉल में लगाया था.

37 वर्षीय संगकारा एक शानदार खिलाड़ी हैं इस बात से सभी वाकिफ हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से टेस्ट मैचों में उनके बल्ले का जादू दिखाई नहीं पड़ रहा था, उन्हें स्पिन गेंदबाजों को खेलने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी. भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उन्होंने दो टेस्ट खेले. चारों पारियों में उनका विकेट आर अश्विन ने लिया. करियर के आख़िरी पड़ाव में फ़ॉर्म ने भी संगकारा का साथ छोड़ दिया था. पिछले 9 टेस्ट मैचों में उनके जैसा उम्दा बल्लेबाज रनों के लिए तरसता रहा. इस दौरान उन्होंने 22.44 के औसत से केवल 202 रन बनाये. वह अपनी अंतिम पारी में केवल 18 रन बना सके.

डेढ़ दशक लंबे टेस्ट करियर में संगाकारा ने कई बेहतरीन पारियां खेलीं. टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा दोहरे शतक के सर डॉन ब्रैडमैन के 12 दोहरे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से वह महज एक कदम से चूक गए. क्रिकेट में विकेटकीपर की भूमिका को एक नया आयाम एडम गिलक्रिस्ट ने दिया था. एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज टीम की काया पलट कर सकता है, इस विचार को संगाकार और आगे ले गए.उनकी कमी श्रीलंकाई क्रिकेट को लंबे समय़ तक खलेगी.

आज वह श्रीलंका ही नहीं विश्व के सर्वकालिक महान खिलड़ियों में से एक हैं. वह सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस जैसे खिलाड़ियों के समकक्ष खड़े दिखाई देते हैं. संगकारा ने उस दौर में क्रिकेट खेली जब दुनिया भर में बेहतरीन क्रिकेटरों की एक बड़ी फौज खड़ी थी. बावजूद इसके संगकारा ने न केवल अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि सनथ जयासूर्या, मुथैया मुरलीधरन और महेला जयवर्धने जैसे खिलाड़ियों के साथ मिलकर श्रीलंकाई क्रिकेट को एक नई ऊंचाईयों पर ले गये. उनके टीम में रहते श्रीलंका दो बार एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकप के फाइनल में(2007,2011), तीन बार टी–20 विश्वकप के फाइनल में(2009,2012,2014) और साल 2002 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची. इन सभी में संगकारा टीम में थे. लगातार दो बार टीम को एकदिवसीय विश्वकप के फाइनल तक ले जाने के बावजूद वह उसे दोबारा विश्वविजेता नहीं बना सके, शायद यह मलाल संगकारा को जीवन भर रहेगा, लेकिन 2014 टी–20 विश्वकप की जीत इस दर्द में थोड़ी राहत जरूर देगी.

कुमार संगकारा का टेस्ट मैचों में बैटिंग औसत कम से कम सौ टेस्ट मैच खेलने वाले बल्लेबाजों की सूची में सबसे ऊपर है. उन्होंने यह उपलब्धि क्रिकेट के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, जैक कैलिस, रिकी पॉन्टिंग जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़कर हासिल की है. संगकारा ने अपने टेस्ट करियर में 57.40 की औसत से 12,400 रन बनाये. ऐसे तो संगकारा एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने एक विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए 150 टेस्ट पारियों में 67.39 की औसत से रन बनाये जो कि सर डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे ज्यादा है.

सचिन तेंदुलकर ने संगकारा को विदाई देते हुए कहा है कि संगकारा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जब पूरी टीम संघर्ष कर रही होती है तो भी वह आसानी से रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं. शायद इसी वजह से विपक्षी टीमें उनसे डरती थीं और इज्जत करती थीं. वे विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं. शायद इसीलिए बतौर कप्तान राहुल द्रविड़ भी संगकारा के खेल में तकनीकि गल्तियां ढूंढने में असमर्थ रहे. जेंटलमेंस गेम में संगकारा को एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ–साथ एक अच्छे इंसान के रूप में भी जाना जाता है. संगकारा का विवादों से दूर–दूर तक कोई नाता नहीं रहा न ही सफलता कभी उनके सिर चढ़कर बोली. वह एक समर्पित खिलाड़ी थे और खेल भावना के अनुरूप मैदान में अपने बल्ले को जादू से हर किसी को मंत्र–मुग्ध कर देते थे. वह मैदान के बाहर भी समाज सेवा के कार्यों में लगातार लगे रहे.

जिस अंदाज में विश्वकप–2015 में उनकी लगातार चार शतकीय पारियों के विश्व रिकॉर्ड के साथ विदाई हुई थी. टेस्ट में वैसा नहीं हो सका, लेकिन एक बात तो संगकारा के बारे में निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि फॉर्म इज टेम्परेरी एंड क्लास इज पर्मानेंट. संगकार के क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद श्रीलंकाई टीम में उपजे शून्य को भर पाना आसान नहीं होगा. भारत के खिलाफ दोनों ही टेस्ट मैचों में संगकारा के बल्ले का जादू नहीं चला इसी वजह से दोनों ही टेस्ट मैचों में श्रीलंकाई टीम संघर्ष करती दिखी. भले ही खुदकिस्मती से वह पहला टेस्ट जीतने में कामयाब हो गई लेकिन दूसरे टेस्ट में उनकी कलई खुल गई. उनकी कमी केवल श्रीलंका को ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट को भी खलेगी.■

navinonline2003@gmail.com

- संगकारा ने टेस्ट क्रिकेट में 150 रनों से ज्यादा की 19 पारियां खेली हैं. यह एक विश्व रिकॉर्ड है.
- कप्तान के रूप में संगकारा का बल्लेबाजी औसत केवल सर डॉन ब्रैडमैन से कम है.
- 150 रनों की लगातार चार पारियां खेलने का रिकॉर्ड संगकारा के नाम दर्ज है.
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल रनों के मामले में संगकारा(28016) केवल सचिन तेंदुलकर(34357) से पीछे हैं.
- कुमार संगकारा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 8000,9000,11000,12000 रनों तक पहुंचने वाले खिलाड़ी हैं.
- संगकारा और जयवर्धने के नाम टेस्ट क्रिकेट की सबसे लंबी साझेदारी (624) का रिकॉर्ड दर्ज है. जो उन्होंने साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलंबो में बनाया था.
- गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट के पीछे शिकार करने के मामले में तीसरे स्थान(678) पर हैं जबकि दक्षिण अफ्रीकी विकेट कीपर मार्क बाउचर (998)पहले और एडम गिलक्रिस्ट (905) दूसरे नंबर पर हैं.
- संगकारा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक जमाने वालों की सूची में 11 दोहरे शतक के साथ दूसरे स्थान पर हैं सबसे ज्यादा दोहरे शतक सर डॉन ब्रेडमैन(12) के नाम दर्ज हैं.

संगकारा को ब्रिटेन में उच्चायुक्त पद की पेशकश

संगकारा के विदाई समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्रीसेना उपस्थित थे. उन्होंने संगकारा को स्मृति चिन्ह प्रदान करके के बाद अपने संबोधन में उन्हें ब्रिटेन में उच्चायुक्त पद की पेशकश कर दी. हालांकि संगकारा ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग खुशी नज़र आई. राष्ट्रपति ने कहा कि संगकारा हमारे देश के चर्चित चेहरे हैं और मुझे उन्हें ब्रिटेन में उच्चायुक्त के पद का प्रस्ताव देते हुए बेहद खुशी हो रही है. संगकारा ने कहा कि मेरे पास अभी प्रस्ताव आया है मैं इसे लेकर अचंभित हूं. मैं राष्ट्रपति के प्रस्ताव का सम्मान करता हूं, मुझे इस बारे में उनसे और बात करनी होगी क्योंकि इस विषय में मुझे किसी तरह का अनुभव नहीं है.

कुमार संगकारा : आंकड़ों के आईने में

टेस्ट करियर

मैच	पारी	नाबाद	रन	सर्वाधिक	औसत	शतक	अर्धशतक
134	233	17	12400	319	57.40	38	52

टॉप पांच पारियां

319 बनाम बांग्लादेश, चिटगांव,2014
287 बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलंबो(एससीसी), 2006
270 बनाम जिंबाब्वे, बुलवायो,2004
232 बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलंबो(एससीसी), 2004
230 बनाम पाकिस्तान, लाहौर, 2002

मणिपुर का पारंपरिक खेल यूबी-लाकपी

यूबी का अर्थ होता है नारियल और लाकपी का मतलब होता है छीनना. इसलिये इस खेल का नाम यूबी–लाकपी पड़ा.

मणिपुर का पारंपरिक खेल यूबी–लाकपी, जिसे मणिपुरी रग्बी भी कहां जाता है. यह खेल मणिपुर की सांस्कृतिक अभिन्न हिस्सा है. माना जाता है कि इस खेल की शुरूआत समुद्र मथंन के समय हुई थी. जब देवता और राक्षस अमृत कलश को छीनने के लिए भगवान धनवंतरी के पीछे भाग रहे थे. तभी से मणिपुर में यूबी लाकपी का खेल खेला जाता है. मणिपुरी भाषा में यूबी का अर्थ होता है नारियल और लाकपी का मतलब होता है छीनना. इसलिये इस खेल का नाम यूबी–लाकपी पड़ा. इस खेल में दो टीमें होती हैं. दोनों ही टीमों में 7–7 खिलाड़ी होते हैं. खेल शुरू करने से पहले खिलाड़ी अपने शरीर पर सरसों का तेल फिसलन बनाने के लिए लगाते हैं. इसके बाद एक नारियल जो कि मुख्य अतिथि (जो कि वहां का राजा होता है) के सामने रखा होता है. जिसे एक खिलाड़ी अपने हाथों के बीच पकड़कर भागता है. दूसरी टीम के खिलाड़ी उससे नारियल छीनने का प्रयास करते हैं. यह खेल एक सूखे चौकोर मैदान में खेला जाता है जो कि 5 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा होता है. खेल के निर्धारित समय में जो टीम विपक्षी टीम के गोल पोस्ट तक नारियल को ज्यादा बार ले जाने में सफल होती है. वह टीम विजेता बनती है. जिस नारियल से यह खेल खेला जाता है, खेल समाप्त होने के बाद उसे मुख्य अतिथि को भेंट स्वरूप दे दिया जाता है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कबड्डी

यू मुंबा ने जीता प्रो-कबड्डी लीग का खिताब

यू–मुंबा ने बेंगलुरु बुल्स को 36–30 के अंतर से हराकर स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी सीजन–2 का ख़िताब जीत लिया. पिछले सीजन के फाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स से मात खाने वाली यू–मुंबा इस बार नहीं चूकी. पहले हाफ में शानदार डिफेंस और दूसरे हाफ के ऑलराउंड खेल की बदौलत यू–मुंबा ने मैच जीता. बॉलीवुड और क्रिकेट सितारों की मौजूदगी में मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में यू–मुंबा ने शुरुआत से अपना दबदबा बनाए रखा. फाइनल मुक़ाबले में यू–मुंबा ने टॉस जीतकर बुल्स को पहले रेड करने के लिए कहा. जीत की प्रबल दावेदार के रूप में खेलने उतरी मुंबई की टीम ने प्रतिद्वंदी टीम को हराने के लिए जबरदस्त मशक्कत की. मेजबान टीम कहीं से भी कम नहीं थी. दोनों टीम का हर एक खिलाड़ी जीत के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगा रहा थी. मेजबान टीम ने जीत के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन अंत में वह सफल नहीं हो सके. लगातार रोमांचक होते खेल को लेकर दर्शकों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा था. दोनों टीमों के खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ाने के लिए दर्शक टीम के नाम से लगातार नारेबाजी कर रहे थे. एक के बाद आगे बढ़ते राउंड के साथ जैसे दर्शकों में कौतुहल और भी बढ़ता जा रहा था. जैसे–जैसे खेल अंत के करीब पहुंचा, यू–मुंबा की जीत की उम्मीद ज्यादा बढ़ने लगी. आखिर में जीत के साथ यू–मुंबा की टीम को एक करोड़ रुपये की शीर्ष इनामी राशि मिली. वहीं बेंगलुरु बुल्स को उपविजेता के रूप में 50 लाख के पुरस्कार से संतोष करना पड़ा.■

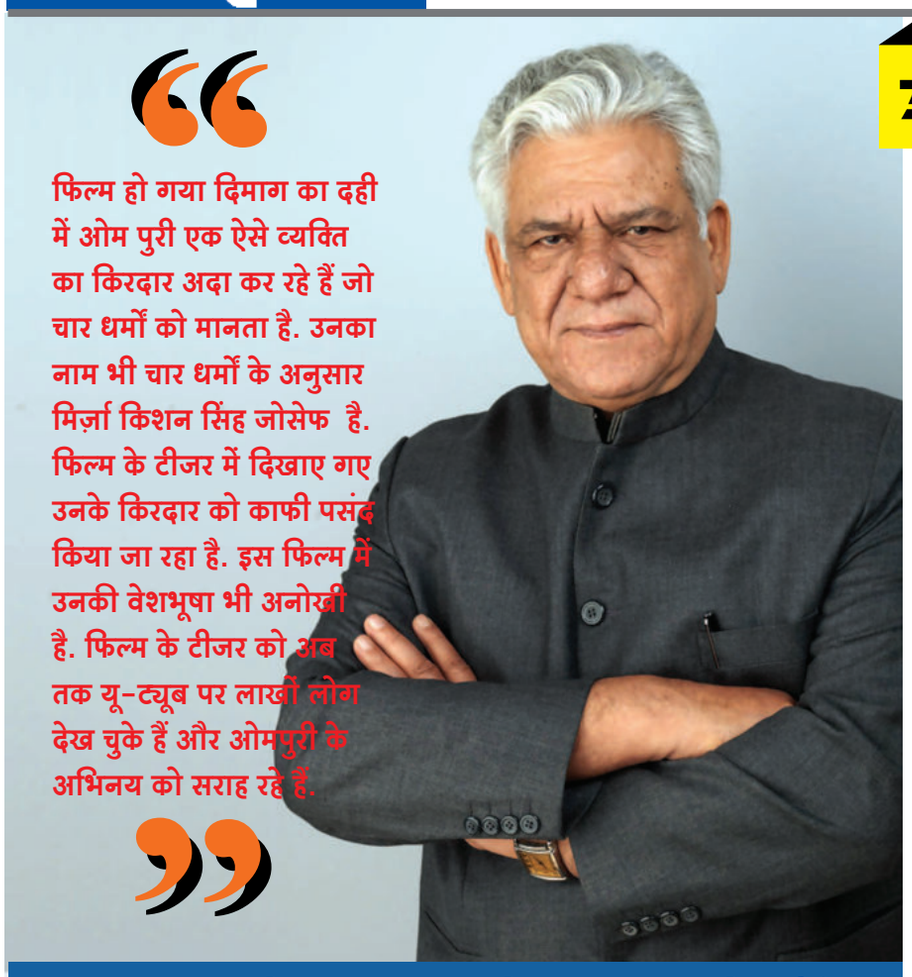

फिल्म हो गया दिमाग का दही में ओम पुरी एक ऐसे व्यक्ति का किरदार अदा कर रहे हैं जो चार धर्मों को मानता है. उनका नाम भी चार धर्मों के अनुसार मिर्ज़ा किशन सिंह जोसेफ है. फिल्म के टीजर में दिखाए गए उनके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म में उनकी वेशभूषा भी अनोखी है. फिल्म के टीजर को अब तक यू-ट्यूब पर लाखों लोग देख चुके हैं और ओमपुरी के अभिनय को सराह रहे हैं.

आपसे मिलने आ रहे हैं मिर्ज़ा किशन सिंह जोसेफ

चौथी दुनिया ब्यूरो

अगर दिलीप कुमार आज सक्रिय होते तो कैसे होते? शायद ओमपुरी जैसे, उनके चेहरे के भाव, बोलने का ढंग, शब्दों पर जोर यह सब दिलीप कुमार की याद दिलाते हैं. खास है कि वे दिलीप साहब से अलग ओमपुरी हैं. अपने चरित्र की छाप छोड़ने वाले वे आज के अकेले अभिनेता हैं.उनकी 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म दिमाग का दही इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. उनका बोला संवाद **कब ले जायेंगे**, डायलॉग डिलीवरी का अनोखा उदाहरण है. सिर्फ चेहरे की शिकनों से दृश्य में जान डाल देने का कारनामा आज सिर्फ ओमपुरी ही कर सकते हैं.

फिल्म ***होगया दिमाग का दही*** में ओम पुरी एक ऐसे व्यक्ति का किरदार अदा कर रहे हैं जो चार धर्मों को मानता है उनका नाम भी चार धर्मों के अनुसार मिर्ज़ा किशन सिंह जोसेफ है. फिल्म के टीजर में दिखाए गए उनके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म में उनकी वेशभूषा भी अनोखी है. फिल्म के टीजर को अबतक यू-ट्यूब में लाखों लोग देख चुके हैं और ओमपुरी के अभिनय को सराह रहे हैं. ओमपुरी खुद भी फिल्म ***होगया दिमाग का दही*** को लेकर काफी उत्साहित हैं. ओमपुरी का कहना है कि 16 अक्टूबर को फिल्म के रिलीज होने पर जब दर्शक मिर्ज़ा किशन सिंह जोसेफ से रूबरू होंगे, तो हंस हंस कर उनके दिमाग का दही हो जायेगा. अपने इस अनोखे किरदार के बारे में वह बताते हैं कि उन्हें ***मिर्जा किशन सिंह जोसेफ*** का किरदार अदा करते हुए काफी मजा आया. ओमपुरी पहली बार किसी फिल्म में एक अनोखे गेट अप में नज़र आयेंगे. उन्होंने खुद भी अपने इस गेटअप की तारीफ की है. ओमपुरी फिल्म की शूटिंग के दौरान ***मिर्ज़ा किशन सिंह जोसेफ*** के किरदार में इस तरह रच बस गये थे कि उन्होंने शूटिंग के दौरान सभी शॉट एक ही टेक में पूरे कर लिए थे. इस वजह से फिल्म में उनके कैरेक्टर में जान आ गई है. वह बताते हैं कि फिल्म का डायलॉग कब ले जायेंगे मुझे अभी भी रात में जगा देता है.

इस रोल के बारे में ओमपुरी कहते हैं कि उन्होंने इतना इंटेस रोल पहले कभी नहीं किया, वह शूटिंग के दौरान अपने सह कलाकारों से लगातार यह कहते रहते थे कि ***होगया दिमाग का दही*** एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म बनने जा रही है, इसलिए कोई भी इसे हल्के में न ले. इस वजह से सभी कलाकारों ने फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है. ओमपुरी आज एक्टिंग की जीवित पाठशाला हैं. उनका हंसना, गुस्सा होना, चलना और बोलना एक्टिंग सीखने वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ पाठ है. इन सबको एक साथ देखना हो तो ***होगया दिमाग़ का दही*** फिल्म में 16 अक्टूबर को देखा जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

जन्मदिन हरदिल अजीज आशा भोसले

08 सितंबर को आशा भोसले 82 साल की हो जाएंगी, लेकिन आज भी उनकी आवाज़ का जादू फीका नहीं पड़ा है. जब कभी हिन्दी फिल्मों के ग्लैमरस गीतों की आती है तो सबसे पहले दिमाग में चुलबुली, नटखट और जिंदादिल गायिका आशा भोसले का नाम सबसे पहले जहन में आता है. ऐसे तो उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए हर तरह के गाने गाये. लेकिन कैबरे गीतों के लिए उन्हें विशेष रुप से याद किया जाता है. स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की छोटी बहन होने के बावजूद आशा भोसले ने अपनी कड़ी मेहनत और गायिकी की बदौलत फिल्म जगत में अपना अलग मुकाम बनाया. आशा भोसले ने साल 1943 में अपने करियर की शुरुआत की और पिछले सात दशकों से लोगों के दिल पर राज करती आ रही हैं. हर वर्ग के लोग उनके गीतों के प्रशंसक हैं. **मेरा कुछ सामान..** से लेकर **कमबख्त इश्क..** जैसे बहुत से गीत हैं जो हर किसी को मदहोश कर देते हैं. आशा भोसले उन तमाम कलाकारों में से हैं, जिन्होनें आर डी बरमन, ओ पी नैय्यर, गुलज़ार और शंकर-जयकिशन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया और नये दौर के महान संगीत निर्देशक एक आर रहमान के साथ भी उसी गर्मजोशी के साथ काम कर रही हैं. आशा भोसले ने न केवल कैबरे गात गाये या फिर लाइव म्यूजिक को अपना सहारा बनाया बल्कि फिल्म उमराव जान में शां ीय शैली के गीतों को भी अपनी आवाज भी दी. आशा भोसले के गाये गानों में ***इन आंखो की मस्ती के..***, ***झुमका गिरा रे..***, **परदे में रहने दो..**, **दम मारो दम..**, **पिया तू अब तो आजा..**, मेरा कुछ समान तुम्हारे पास है ऐसे न जाने कितने गाने अपने ज़माने में हिट हुए बल्कि आज भी लोगों के दिल और जुबां पर बसते हैं. जब आशा ताई के सुर और पंचम दा के संगीत का मिलन हुआ, तब आशा शादी शुदा थीं और तीन बच्चो की मां थीं. आर डी बरमन आशा से 6 साल छोटे थे लेकिन इन सब के बावजूद इन दोनों को जो चीज एक दूसरे के करीब लाई वह थी संगीत.

आशा भोसले और आर डी बर्मन की पहली मुलाकात तब हुई जब आर डी महज़ 13 साल के थे और आशा 19 साल की. आर डी बर्मन के पिता सचिन देब बर्मन ने दोनों की मुलाकात कराई. उस मुलाक़ात में पिता के आदेश पर पंचम ने आशा के पैर छुए थे. आशा भोसले ने 16 वर्ष की उम्र में अपने से 15 साल बड़े गणपत रॉव भोसले से भागकर शादी की थी. तीन बच्चे होने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं और दोनों 1960 में अलग हो गए. इस रिश्ते के टूटने का असर कभी उनके संगीत पर नहीं पड़ा और वो लगातार मशहूर होती गईं. वह आसमान की बुलंदियों को छूने लगीं. वहीं दूसरी ओर पंचम दा आशा की गायकी के दीवाने होते जा रहे थे. वह अपनी हर फिल्म में आशा से ही गाने गवाते और इसी दौरान इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. इसके बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गये.

ऐसे तो आशा भोसले को कई पुरस्कारों से नवाज़ा गया है लेकिन साल 1981 में फिल्म उमराव जान के गीत दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिये और वर्ष 1986 में फिल्म इजाजत के गीत **मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है..**के लिये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा गया. साल 2005 में उन्हें उनके एलबम आज जाने की जिद न करो के लिये एम टीवी ईमेज बेस्ट फीमेल पॉप ऐक्ट जैसे पुरस्कार से भी नवाज़ा गया.■

पाकिस्तानी मीडिया में हो गया दिमाग का दही की चर्चा

www.jang.com.pk
باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED پاکستان کا سب سے بڑا روزنامہ
THE DAILY JANG KARACHI
روزنامہ جنگ کراچی
میر خلیل الرحمٰن
جلد 79 | بدھ 10 ذیقعدہ 1436ھ 26 اگست 2015ء | نمبر 235

نامور اداکار قادر خان دس برس بعد فلم ''ہوگیا دماغ کا دہی'' میں جلوہ گر ہونگے

کراچی (رپورٹ جاوید رشید) بھارتی فلم انڈسٹری کے نامور اداکار قادر خان عرصہ دس برس بعد سنتوش بھارتی کی فلم ''ہوگیا دماغ کا دہی'' میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ فلم بھارتی سینما گھروں میں 16اکتوبر 2015 کو نمائش کے لئے پیش کی جائے گی۔ فلم میں قادر خان، اوم پوری، سنجے مشرا، رزاق خان، ایتا نانجیا، اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ فلم میں گانے روئی چوپڑا نے لکھے ہیں فلم کو بھارتی سنسر بورڈ کی کلیئرنس حاصل ہوگئی ہے۔

फिल्म हो गया दिमाग का दही के चर्चे सरहद पार पाकिस्तान में भी हो रहे हैं. जाने माने पत्रकार संतोष भारतीय द्वारा निर्मित और फौजिया अर्शी द्वारा निर्देशित इस कॉमेडी फिल्म पर पाकिस्तान के नामचीन उर्दू अखबार रोजनामा जंग ने कादर खान की एक दशक बाद फिल्मों में वापसी पर एक लेख प्रकाशित किया है. गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन की कई सुपरहिट फिल्मों के डॉयलाग क़ादर खान ने लिखे हैं इस वजह से भी वह पाकिस्तान में लोकप्रिय हैं. अमिताभ बच्चन पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय हैं, हाल ही में बिग बी ने भी कादर खान की फिल्मों में वापसी का स्वागत ट्वीट करके किया था. अखबार आगे लिखता है कि फिल्म भारत में सिनेमाघरों में 16 अक्टूबर को रिलीज होगी.■

बॉलीवुड का नया कपल जैकलीन-अर्जुन

मलेशिया में हुए आईफा अवार्ड्स समारोह के दौरान जैकलीन फर्नांडीज और अर्जुन कपूर एक-दूसरे के साथ समय बिताते हुए नजर आए थे. इसके बाद यह कयास लगाने शुरू हो गए थे कि इनके बीच कुछ करीबी रिश्ता है. इसके अलावा जैकलीन अर्जुन के बर्थ-डे पर भी नज़र आईं थीं. जहां वह अर्जुन की बहन के साथ बॉन्डिंग करती दिखीं थीं. जैकलिन से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सब बकवास है, मुझे ऐसी बातों पर हंसी आती है. मैं और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त हैं और केवल दोस्त ही हैं. इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं. जैकलीन ने कहा, मैं सिर्फ यह सब सुनती हूं और हंसती हूं. मैं आजकल अखबार नहीं पढ़ती हूं, मेरे आसपास के लोग मुझे मेरे बारे में जानकारी देते रहते हैं. लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मेरे और अर्जुन के बीच अफेयर है और सलमान खान से मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं. लेकिन यह सब बकवास है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको खुद ही बताऊंगी.■

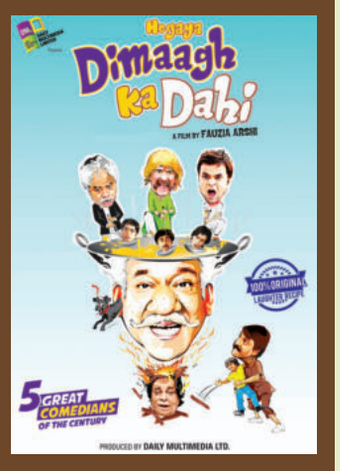

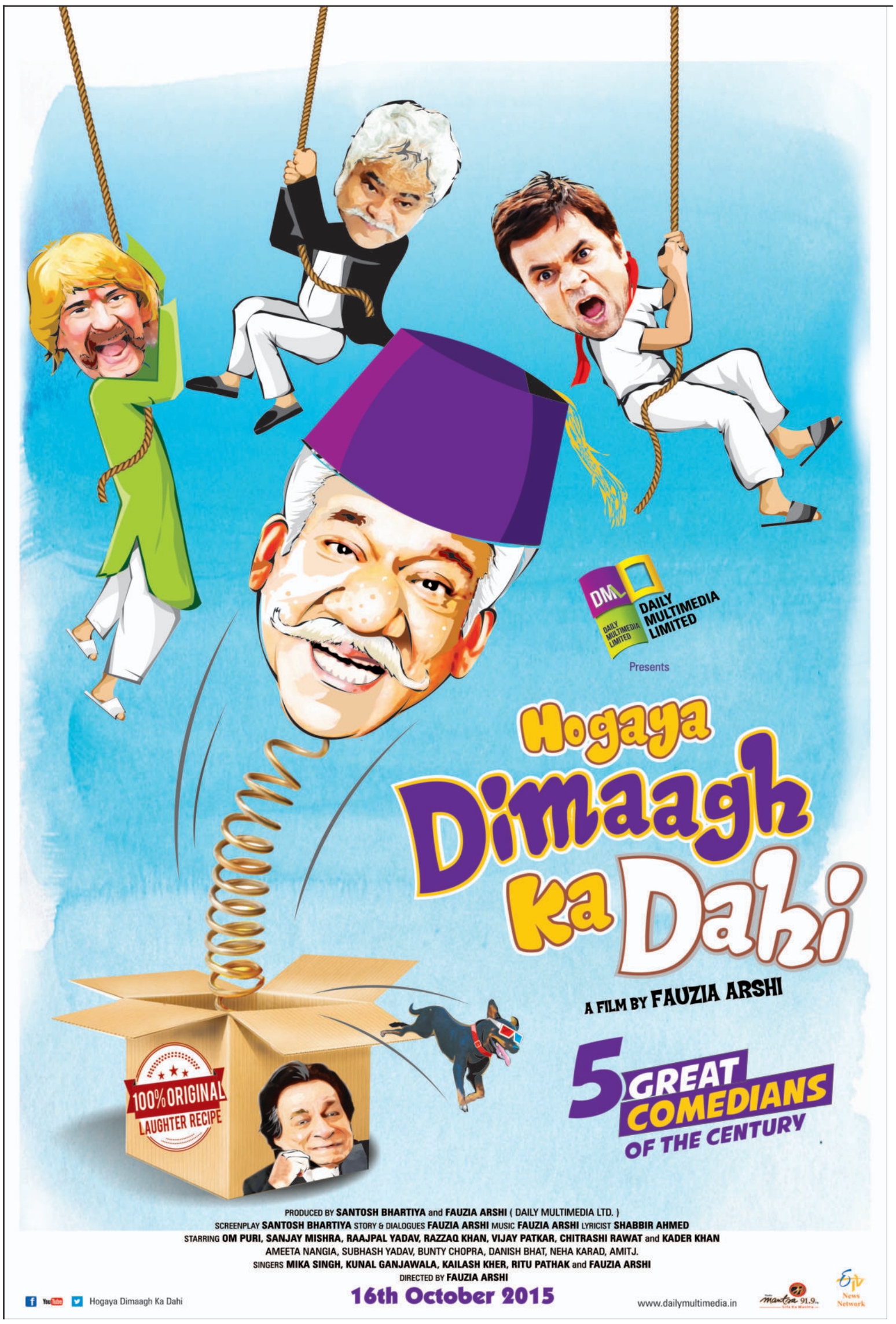

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार - झारखंड

07 सितंबर-13 सितंबर 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अरुण की शह, उपेंद्र की मात

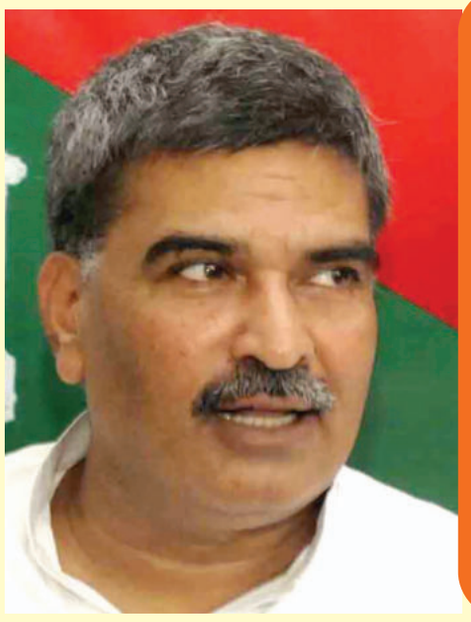

भाजपा नेताओं की बातों से लोजपा के अंदर बेचैनी तो थी पर इतनी नहीं कि वह लक्ष्मण रेखा पार कर सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी शुरू कर दें. लेकिन इस बीच रालोसपा में दूसरी ही खिचड़ी पक रही थी. इस बात में अब कुछ ऐसा छिपाने के लिए नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच के रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रह गए हैं. सार्वजनिक मौकों पर भले ही ये दोनों नेता एक दूसरे के अगल-बगल नजर आते हैं पर लोकसभा चुनाव और खासकर उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बन जाने के बाद अरुण कुमार उनसे दूर होते चले गए. यह अब तक स्थापित हो गया था कि तीन सांसदों वाली पार्टी के दो मंत्री नहीं बन सकते, इसलिए अरुण कुमार के लिए मन-मसोस कर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया.

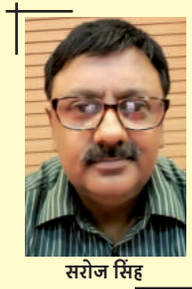

सरोज सिंह

नरेंद्र मोदी लहर पर मिशन बिहार को फतह करने का इरादा रख रहे एनडीए नेताओं के लिए पिछला पखवाड़ा अच्छा नहीं गुजरा. जिस बात की आशंका थी वह सच साबित हुई और सहयोगी दल लोजपा और रालोसपा के नेताओं ने मीडिया के माध्यम से भाजपा के प्रति अपनी भड़ास जमकर निकाली. सीट बंटवारे को लेकर सब्र का बांध टूट गया और भाजपा के दोनों सहयोगी दलों को ऐसा लगा कि दोनों भाई मिलकर भाजपा को बातचीत के टेबल पर ले आएंगे. मीडिया को माध्यम बनाया गया ताकि असर जल्दी हो जाए. लोजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और रालोसपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार मीडिया से रूबरू हुए और साफ कर दिया कि भाजपा को 102 सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहिए. बाकी सीटों को जल्द से जल्द सहयोगी दलों के बीच बांट देना चाहिए. देखा जाए तो कोई नई बात सहयोगी दलों ने नहीं रखी है. वैशाली के अपने सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव रालोसपा पास कर चुकी है. इसके बाद कई मौकों पर रालोसपा के नेताओं ने अपनी इस भावना से भाजपा के बड़े नेताओं को अवगत कराया. भाजपा बार-बार यही कहती रही कि सही समय पर सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा. इशारों ही इशारों में यह संकेत दे दिया गया कि प्रधानमंत्री की एक सितंबर की रैली के बाद ही इस पर बात संभव है. भाजपा नेताओं की इन बातों से लोजपा के अंदर बैचेनी तो थी पर इतनी नहीं कि वह लक्ष्मण रेखा पार कर सार्वजनिक तौर पर बयानबाज़ी शुरू कर दें. लेकिन इस बीच रालोसपा में दूसरी ही खिचड़ी पक रही थी. इस बात में अब कुछ ऐसा छिपाने के लिए नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच के रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं रह गए हैं. सार्वजनिक मौकों पर भले ही ये दोनों नेता एक दूसरे के अगल-बगल नजर आते हैं पर लोकसभा चुनाव के बाद और खासकर उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बन जाने के बाद अरुण कुमार उनसे दूर होते चले गए. यह अब तक स्थापित हो गया था कि तीन सांसदों वाली पार्टी के दो मंत्री नहीं बन सकते इसलिए अरुण कुमार के लिए मन मसोस कर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया. अरुण कुमार खुद ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पास सांसद से कहीं ज्यादा काम करने की क्षमता है पर लोकसभा के राजनीतिक गणित में उनकी यह तथाकथित क्षमता कुंद पड़ने लगी. राजनीतिक हालात को समझते हुए अरुण कुमार ने पार्टी पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया. हाल यह हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा के खास रहे पार्टी प्रवक्ता प्रो अभ्यानंद सुमन को बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए हुए रालोसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. उपेंद्र कुशवाहा के लाख चाहने के बावजूद अभी तक श्री सुमन की पार्टी में वापसी नहीं हो पाई है. इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा चाहते हुए भी अपने कई पार्टी नेताओं को रालोसपा में कोई जगह नहीं दे पाए. अब बात जब विधानसभा चुनाव की शुरू हुई तो टिकटों को लेकर भी अरुण कुमार इस तरह की चालें चलने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा के पास बहुत ज्यादा मौका न रह जाए. अरुण कुमार यह अच्छी तरह जानते हैं कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. वह सांसद बन चुके हैं और मंत्री बन नहीं सकते. इसलिए अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलवाकर विधायक बनाया जाए ताकि प्रदेश की सरकार में सिक्का चलता रहे. सूत्रों पर भरोसा करें तो इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से साफ कर दिया कि भाजपा से जो भी टिकट पार्टी के कोटे में आएगा इसका साठ फीसदी बंटवार वह खुद करेंगे बाकी की चालीस फीसदी सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा जिसे चाहे टिकट दे सकते हैं. जानकार सूत्र बताते हैं कि लोजपा को साथ लेकर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा के लिए 102 सीटों की सीमा तय करने के प्लान से उपेंद्र कुशवाहा बहुत सहमत नहीं थे. लेकिन अरुण कुमार चाहते थे कि भाजपा का गुड बॉय बनकर अब नहीं रहा जा सकता . बेचैन लोजपा को एक सहारा मिल गया और संयुक्त संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर दिया गया.

रालोसपा और लोजपा का यह तीर सही निशाने पर बैठा या नहीं बैठा इसे लेकर राजनीतिक पंड़ितों की अलग अलग राय है. कुछ लोगों का कहना है कि यह इसी साझे संवाददाता सम्मेलन का ही असर था कि बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव देर शाम चिराग पासवान से मिलने पहुंचे. भाजपा नेताओं के बयान आए कि सबकुछ मिलजुल करा ठीक कर लिया जाएगा. लेकिन सूत्रों पर भरोसा करें तो भाजपा नेतृत्व ने इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से लिया है. भाजपा ने अपनी अंदरूनी बैठकों में यह साफ कर दिया है कि पार्टी सहयोगी दलों के दबाव में नहीं आएगी. यही वजह है कि सीट को लेकर रामविलास पासवान के पटना स्थित आवास पर होने वाली बैठक रद्द कर दी गई. कहा गया कि सौदान सिंह सही समय पर पटना नहीं आ पाए इसलिए इस बैठक को रद्द कर दिया गया पर अंदरखाने की खबर यह है कि भाजपा यह संदेश कतई नहीं देना चाहती थी कि सहयोगी दलों के दबाव में यह बैठक हो रही है. सहयोगी दलों के रवैये खासकर रालोसपा के रवैये से भाजपा नेतृत्व बेहद खफा है. भाजपा के कई बड़े नेता आफ द रिकार्ड बोलते हैं आखिर उपेंद्र कुशवाहा को हमलोग इतनी तवज्जो क्यों दें. लोकसभा चुनाव में चुनाव में उन्हें दो सीट दी गई और वह दोनों सीट हार गए. विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए मारा मारी कर रहे हैं और प्रत्याशी है ही नहीं. नरेंद्र मोदी की कृपा से सांसद बने अरुण कुमार भाजपा को चेतावनी देते हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और किसी तरह जमानत बचा पाए थे. दरअसल अगर आज भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सख्त हुई है, इसकी वजह अरुण कुमार ही हैं. बिना वजह भाजपा को टारगेट करके रालोसपा की इमेज मित्र के बजाय दुश्मन की बनती जा रही है. अगर शिकायत भाजपा से थी तो आपस में मिलकर भी बात रखी जा सकती थी लेकिन मीडिया में बात रखकर आखिर क्या हासिल हुआ. उल्टा असर यह हुआ कि भाजपा ने तय कर लिया कि वह हर हाल में 160 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

भाजपा के सूत्र बताते हैं कि लोजपा का फार्मूला है कि सीटिंग और सकेंड रही सीटों पर उसका हक है. मांझी सीटिंग एमएलए और कुछ महत्वपूर्ण साथियों के लिए सीट मांग रहे हैं. लेकिन रालोसपा पर तो कोई फार्मूला लागू नहीं हो रहा. लोकसभा की सीटें एक आधार हैं तो इसके अनुसार 18 से 20 सीट रालोसपा की बनती है. लेकिन अनाप-शनाप मांग रखकर रालोसपा अपनी ही स्थिति खराब कर रही है. जानकार सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने प्लान बी के तहत नागमणि की पीठ ठोंक दी है. अगर उपेंद्र कुशवाहा अरुण कुमार को नियत्रंण में नहीं रख सके तो किसी अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. भाजपा का कहना है शकुनी चौधरी और उनके पुत्र सम्राट चौधरी तो साथ हैं ही. ऐसे में नागमणि को साथ लेकर कोई बड़ा फैसला लेने में दिक्कत नहीं आएगी. अरुण कुमार को लगता है कि अगर ऐसी नौबत आई तो आफत उपेंद्र कुशवाहा पर आएगी, खुद उनकी सेहत पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. वह सांसद थे और सांसद रहेंगे ही. यहां यह कहना भी जरूरी है कि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दोनों ही तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ही पिस रहे हैं. जानकार बताते हैं की जीतनराम मांझी की एंट्री से परेशान रामविलास पासवान किसी भी कीमत में भाजपा के खिलाफ नहीं जा सकते. इसलिए रालोसपा इस मुगालते में न रहे कि भाजपा के खिलाफ उसे हमेशा लोजपा का साथ मिलेगा. रालोसपा और लोजपा के कार्यकर्ता चाहते हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन मजबूती से बना रहे. लेकिन कुछ घटनाएं रिश्तों में खटास भर रही है. अब भले ही सीटों का बंटवारा कुछ कम वैसी करके हो जाए पर सहयोगी दलों के रिश्तों पर तो गांठ पड़ ही गई.■

feedback@chauthiduniya.com

नरेंद्र मोदी की कृपा से सांसद बने अरुण कुमार भाजपा को चेतावनी देते हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और किसी तरह जमानत बचा पाए थे. दरअसल अगर आज भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सख्त हुई है, उसकी वजह अरुण कुमार ही है. बिना वजह भाजपा को टारगेट करके रालोसपा की इमेज मित्र के बजाय दुश्मन की बनती जा रही है. अगर शिकायत भाजपा से थी तो आपस में मिलकर भी बात रखी जा सकती थी लेकिन मीडिया में बात रखकर आखिर क्या हासिल हुआ. उल्टा असर यह हुआ कि भाजपा ने तय कर लिया कि वह हर हाल में 160 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

एक नज़र
चुनावी हलचल

भाजपा टिकट के लिए दावेदारी

मुजफ्फरपुर जिले की सर्वाधिक प्रतिष्ठित विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर के लिए जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त संघर्ष होने की बात की जा रही है वहीं एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीदवारी को लेकर भी उफान मचा हुआ है. पार्टी के निवर्तमान विधायक सुरेश शर्मा के पुन: दावेदारी के बीच वहां से दो अन्य भाजपा नेताओं ने दावेदारी की भी चर्चा है. इसमें भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष [illegible] और भाजपा विश्व हिन्दू परिषद ,बजरंग दल आदि संगठनों में लंबे समय से काम करने वाले चौधरी श्याम सुन्दर का नाम है. अंदर की बात यह है कि भाजपा वैश्य मतों की बहुलता वाले इस सीट पर [illegible] कायम रखने के लिए निवर्तमान प्रत्याशी को बदलकर वैश्य उम्मीदवार को उतारना चाहती है ताकि महागठबंधन के उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी को मात दी जा सके. अगर पार्टी ऐसा करती है तो निश्चित रूप से चौधरी श्याम सुन्दर की दावेदारी एक नंबर पर होगी. आरएसएस से जुड़े चौधरी श्याम सुन्दर बिहार विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व में संयुक्त सचिव रह चुके है.पूर्व में ही बिहार प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान परिषद और भारतीय अग्रसेन सेवा समिति में भी सक्रियता से काम करते रहे है. उम्मीदवारी के संदर्भ में पूछने पर चौधरी श्याम सुन्दर ने बताया की पार्टी अगर टिकट और जिम्मेदारी देगी तो वह इसके लिए तैयार है. पार्टी जो भी फैसला करेगी मैं इसका पालन करूंगा. दल और देश के प्रति समर्पण के प्रति जो भाव है उसके लिए मैं आजीवन अविवाहित रहने और हमेशा पार्टी के लिए काम करने का फैसला लिया है.

– दिव्या त्रिपाठी

जनता तक भाजपा पहुंचायेगी पैकेज :वरुण

बिहार भाजपा में संगठन के वरिष्ठ नेता वरुण सिंह ने बिहार जदयू के नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को सवा लाख करोड़ का पैकेज दिया है, यह राज्य हित में बिहार में भाजपा की सरकार ही पैसों को इसके असली हकदार तक पहुंचा सकती है. लालू-नीतीश की जोड़ी की सरकार इस पैसे का बंदरबाट कर देगी और जनता अपने हक से महरूम रह जायेगी, और आम जनता इस बात को अच्छी तरह समझ भी रही है. बिहार में जब से एनडीए का शासन खत्म हुआ है और नीतीश कुमार ने अपने को [illegible] के साथ जोड़ा तभी से ही बिहार में परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है. [illegible] आए दिन लूट-मार, अपहरण, भ्रष्टाचार का दौर शुरू हो चुका है. और जनता इसे बदलने के लिए संकल्पित है. सुशासन बाबू का सुशासन केवल और केवल भाजपा सरकार ही दे सकती है.

– भारती

डीएम टेस्ट का सैंपल भेजा मोदी को

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुजफ्फरपुर में परिवर्तन रैली के दौरान की गई टिप्पणी के विरोध में जदयू के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया. धरना कार्यक्रम के दौरान लगभग चार सौ लोगों ने डीएनए टेस्ट के लिए नाखून और बाल दिए. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के पते पर भेजने का निर्णय लिया गया. धरना पर बैठे जदयू कार्यकर्ताओं को सदर विधायक पूनम देवी यादव, पन्ना लाल सिंह पटेल, विधान पार्षद [illegible], पूर्व विधायक [illegible] यादव ने संबोधित किया. जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष साधना देवी ने किया. इस मौके पर जदयू के [illegible] अध्यक्ष [illegible], [illegible] यादव, [illegible], अजय यादव, दीपक सिन्हा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

– गीता कुमार

आईएमजेयू का राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजित
कलम की ताकत का कोई मोल नहीं

राकेश कुमार

पत्रकारों का विचार हथियारों से ज्यादा ताकतवर होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता है. बशर्ते उनका विचार निष्पक्ष होना चाहिए. वहीं राजनेता उनके विचारों को आधार बना कर कार्य करें तो लोगों को अपने अधिकार के लिए बगावत करने की नौबत नहीं आयेगी. पत्रकार राष्ट्र के कर्णधार होते हैं. उक्त बातें सासाराम के ओझा टाउन हॉल में आयोजित इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के राज्य कार्यकारिणी के शपथ समारोह के अवसर पर आयोजित बड़ी बहस को संबोधित करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने कही. उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का आइना होते हैं, और इस आईने में लोकतंत्र की सही तस्वीर दिखाई देती है. इसलिए पत्रकारों को चाहिए कि इस आईने को धुंधला नहीं होने दें. उन्होंने इस अवसर पर पत्राकारों के लिए पेंशन देने के लिए सरकार की योजना एवं पत्रकारों को होने वाली गंभीर बीमारियों के इलाज में सहयोग के लिए राज्य सरकार को योगदान देने के लिए कमेटी गठित करने की बात कही.

कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह, शाहाबाद के डीआईजी मो. रहमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला भास्कर एस, राष्ट्रीय महासचिव अरुण शर्मा एवं उप विकास आयुक्त हाशिम खां ने संयुक्त रूप से किया.

शाहाबाद के डीआईजी मोहमद रहमान ने कहा कि चर्चा के विषय में ही अपनी दशा स्वयं महसूस की जा सकती है. बुद्धिजीवी होने के कारण पत्रकारों को समाज के नीचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की व्यथा को दूर करने की दिशा में अपने कलम का प्रयोग किया जाना चाहिए. पत्रकारों की भी लोगों को मदद करनी चाहिए. हर आदमी जानता है कि वह गलत कर रहा है या सही, यह फैसला अपने विवेक से करना पड़ता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला भास्कर एस ने कहा कि पत्राकारों को खबरों का संकलन करने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. पत्रकार अपनी जान हथेली पर रख कर अखबारों के लिए समाचार संकलन करते है. उन्होंने बताया कि पत्रकारों के हित के लिए हमारा संगठन हमेशा सरकार से संघर्ष करता रहेगा. उन्होंने पत्राकारों से अपील की कि उनके लिए इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन हर संभव मदद के लिए तैयार है.

राष्ट्रीय महासचिव अरुण शर्मा ने यूनियन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आईएमजेयू पत्रकारों के समस्याओं के निदान के लिए हमेशा संघर्ष किया हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में हैदराबाद में सार्क देशों के पत्रकारों का सम्मेलन हुआ, जिसमें फ्री मेडिकल एवं हेल्थ कैम्प लगाया गया था. 2004 में तिरुपति में साऊथ इंडियन जर्नलिस्टों का सम्मेलन हुआ. वर्ष 2005 में पुन: तिरुपति में राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन हुआ. जिसमें दस राज्यों के प्रतिनिधि के अलावा कई देशों के पत्रकार मौजूद थे. 2006 में दक्षिण भारत के करीमनगर में राज्यस्तरीय सेमिनार हुआ. इस दौरान चम्पारण प्रेस कल्ब के कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गौतम ने चम्पारण प्रेस कल्ब को आई एम जे यू से सम्बद्ध करने की घोषणा की. इसपर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंग वस्त्र से श्री गौतम का स्वागत किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार शैलेश कुमार तिवारी एवं संचालन प्रदेश महासचिव सूरज कुमार पांडेय ने किया. मौके पर यूनियन का स्मारिका एवं गीत की लॉचिंग हुई तथा राज्यकार्यकारिणी को शपथ दिलाया गया. वहीं सभी आगत अतिथियों का स्वागत आयोजक मंडल ने मां ताराचंडी का प्रतीक व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया. सम्मेलन को सासाराम विधायक जवाहर प्रसाद, काराकाट विधायक राजेश्वर राज, चेनारी विधायक श्याम बिहारी राम, उप विकास आयुक्त हाशिम खां, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक रंजन, राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन एशोसियशन के राष्ट्रीय महासचिव रामायण पांडेय एलौन, शिवनारायण सिंह यादव, गुप्तेश्वर नाथ दूबे, प्रो. शितला प्रसाद तिवारी, समाजसेवी महेंद्र चौबे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रोहितास सैन राजस्थान, अनिल मिश्रा दिल्ली, रामगोपाल शर्मा मध्य प्रदेश, राष्ट्र कवि हरि विठुल धूमकेतू, सतीश सक्सेना, रमेश वजयवाड़ा, विनीत मिश्रा, डुमरा, रंजीत पांडेय, अमिय पांडेय चंदौल, ज्ञानेश्वर गौतम, विकास विवेक, राकेश कुमार, श्रषि लाल, संतोष दूबे ने भी संबोधित किया. इस मौके पर पत्रकार रजनीकांत पांडेय, संजय कुमार तिवारी, सुरेंद्र तिवारी प्रभात खबर डिहरी, ओम प्रकाश पांडेय, मदन कुमार, गौतम कुमार, अमरेश पांडेय, विनोद कुमार सिह, अरुण वर्मा, निरंतर पांडेय, रमेश पांडेय, गंगेश्वर तिवारी, लाल बहादुर दूबे, दिनेश सिंह, शैलेश पाठक, रमेश कुमार सहित कई लोग मौजूद थे.■

feedback@chauthiduniya.com

सीवान
भाजपा व राजद का रहा सर्वाधिक कब्जा

शंभू प्रसाद अभय

feedback@chauthiduniya.com

विधानसभा चुनाव 2015 सितंबर-अक्टुबर में होने की संभावना प्रबल हो गई है, पूर्व सांसद मो. षहाबुद्दीन के साथ ही डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक व ब्रजकिशोर बाबू के सीवान में भी इसकी सरगर्मी काफी बढ़ गई है. नेता भी अब प्रत्येक चुनावों के भांति इस चुनाव में भी जनता के बीच जाकर लुभावनें आश्वासनों की बरसात करने तथा नए-नए सपनें दिखाने की तैयारी में लग चुके है. सीवान की जनता को पूर्व की सभी सरकारों द्वारा कई योजनाओं के सपने दिखाए गए, जिसके साकार होने का इंतजार आज भी जिले की जनता को रहती है. काफी समय तक अपराध को लेकर चर्चा में रहने वाले सीवान के लोगों को किसी वैसे मशीहा की तलाश है जो प्रलोभन नहीं दिखाते हुए जमीनी विकाश को पूर्ण करें. अगर, हम सीवान सदर विधानसभा पर नजर डाले तो शहरी इलाके को छोड़ कर ग्रामीण इलाको में काफी हद तक विकाश पिछड़ा है. लकड़ी दरगाह पानी टंकी लगभग दो दशक से बंद पड़ा है. गांवो में बिजली नदारद रहती है. कई स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक नहीं जाते हैं. जनवितरण प्रणाली के माध्यम से केरोसीन व राशन का वितरण भी सही समय पर नहीं हो पाता है. मनरेगा भी कागजों पर चल रहा है.

सीवान सदर सीट पर 1951 में सर्वप्रथम कांग्रेस नें अपना परचम लहराते हुए षंकरनाथ तिवारी को एमएलए बनाया, पुन: 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में रामबसावन राम नें कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर अपनी जीत दर्ज करायी. 1959 में कांगेस की सुंदरी देवी नें अपनी जीत दर्ज करायी. फिर क्या था 1962 में विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें जनसंघ के जनार्दन तिवारी नें कांग्रेस की उस अभेदुर्ग को ध्वस्त करते हुए अपनी जीत दर्ज कर ली. कांग्रेस भी अपनी उस हार को काफी गंभीरता से लिया तथा वर्ष 1967 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के राजाराम चौधरी नें पुन: जनसंघ के उम्मीदवार जनार्दन तिवारी को हरा कर अपनी जीत दर्ज करा डाली. फिर क्या था जनसंघ के नेता व कार्यकर्ता पुरी निष्ठा के साथ जनता के बीच अपना समय दिए तथा 1972 के चुनाव में एक बार फिर जनसंघ के जनार्दन तिवारी नें कांग्रेस को पटखनी देते हुए अपनी जीत दर्ज करायी, लेकिन 1977

के आंदोलन कि हवा भी खुब चली थी, उसी समय चुनाव हुआ जिसमें जनता पार्टी के गुलाम सरवर ने जनसंघ के जनार्दन तिवारी को बुरी तरह से पराजीत कर दिया. पुन: 1980 में हुए चुनाव में जनार्दन तिवारी नें भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा तथा विजयी हुए. उसके बाद यह सीट भाजपा के हाथों से भी छीन गई. 1985 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी नें भाजपा के जनार्दन तिवारी को पराजीत कर दिया. उसके बाद 1990 से फरवरी 2005 तक अवध बिहारी चौधरी राजद के टिकट पर यहा से एमएलए रहे, उसके बाद भाजपा ने 2005 के नवंबर के चुनाव में व्यासदेव प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाया जो राजद के अवध बिहारी चौधरी को पराजीत कर दिए. पुन: 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में व्यासदेव प्रसाद भाजपा के टिकट पर विजयी हुए. उन चुनाओं में दो बार राजद के अवध बिहारी चौधरी पराजीत हुए, लेकिन, अब चौधरी राजद से नाता तोड़कर जदयू का दामन थाम चूके हैं. गठबंधन की इस राजनीति खेल में कुछ ही दिनों के बाद राजद व जदयू का गठबंधन हो गया. अब देखना यह है कि सीट बटवारे के समय सीवान राजद के हिस्से में जाता है या जदयू के. पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौघरी के जदयू में शामिल होने के बाद फिकी पड़ी अपनी रंग को फिर चमकदार बनाने के लिए राजद लागातार प्रयासरत है, क्योंकि लंबे समय तक उस सीट पर राजद का कब्जा रहा है. राजद गठबंधन उसी सीट को अपने कब्जे में लेकर एक मजबूत व ताकतवर प्रत्याशी के तलाश में है. सुत्रों की माने तो राजद खेमें द्वारा एक दमदार उम्मीदवार की तलाश भी कर ली गई है, लेकिन यह वक्त ही बताएगा कि यह नया चेहरा कितनी मजबुत लड़ाई दे पाएगा. सीवान विधानसभा सीट पर 13 वर्षो तक जनसंघ व भाजपा के जनार्दन तिवारी नें अपना कब्जा जमाये रखा. वहीं जनता पार्टी व राजद के उम्मीदवार के रूप में अवध बिहारी चौधरी नें 20 वर्षो तक यहां से विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया. इस वर्ष होने जा रहे चुनाव में किसके माथे पर जीत का सेहरा बंधेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन सभी संभावीत उम्मीदवार अपने-अपने जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे है व मैदान में कुदने के लिए ताल ठोक रहे हैं. इस बार की चुनाव में कुछ दलीय तो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में होगें, जो अभी से ही जनता के सभी सुखों व दुखों में शामिल होने लगे है. बहरहाल मामला जो हो लेकिन यह जनता भी कम चलाक नहीं है इस बार जब नेताजी वोट मांगने के लिए गांवो में जाएगें तब जनता बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा तथा राशन-किराशन में गड़बड़ियों को लेकर कई सवाल करेगी जिससे नेताजी की परेशानी स्वत: बढ़ जाएगी, क्योंकि यह पब्लिक है सब जानती है.■

गड़बड़ा सकता है एनडीए का गणित

सुनील सौरभ

बिहार में राजनीतिक गठबंधन के उलट-पुलट होने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में गया जिले का राजनीतिक परिदृश्य भी बदल गया है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गंठबंधन (एनडीए) के साथ नये-नये दल जुट गये तो राजद गठबंधन के साथ पुराने दुश्मन दोस्त हो गये और दोस्त ने साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया. ऐसी परिस्थिति में गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों का भी चुनावी दृश्य बदल गया है. 2010 के चुनाव में जब भाजपा के साथ जदयू था तो गया जिले के दस में चार पर भाजपा तथा छह पर जदयू चुनाव लड़ती थी. लेकिन इस बार एनडीए में जदयू के साथ छुटने के बाद तीन नए दल जुड़ जाने के बाद भी लाभ भाजपा को ही मिला. जो स्थिति बन रही है, उसमें गया जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है.

गया शहर, वजीरगंज, बोधगया, गुरुआ से तो भाजपा के विधायक है ही पाचवें क्षेत्र शेरघाटी विधानसभा से भी भाजपा अपने प्रत्याशी उतार सकती है. शेष पांच विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के नये सहयोगी दल लोजपा, रालोसपा, तथा हम के प्रत्याशी उतारे जाने की संभावना है. संभावित स्थिति में टिकारी तथा बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र हम को मिल सकता है. क्योंकि टिकारी से फिलहाल जदयू के बागी पूर्व मंत्री अनिल कुमार विधायक है. वर्तमान में ये जीतन राम मांझी से जुड़कर हम के लिए काम कर रहे हैं. उम्मीद है कि एनडीए के समझौता में टिकारी हम के लिए रहेगा. बाराचट्टी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में जदयू की ज्योति मांझी विधायक हैं. ये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधीन है. इसलिए संभावना जतायी जा रही है कि चुनाव में ज्योति मांझी अपने समधी के 'हम' में शामिल हो सकती है. यदि ज्योति मांझी जदयू नही छोड़ी तो बाराचट्टी लोजपा को जा सकता है. ऐसे में लोजपा के लिए इमामगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र तथा बेलागंज देने की बात भाजपा गठबंधन के लोगों द्वारा की जा रही है. इमामगंज से वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी विधायक हैं. बेलागंज से पूर्व मंत्री डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव राजद से विधायक हैं. यहां से हम पूर्व मुख्यमंत्री के खास वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन शारिम अली को अपने दल का प्रत्याशी बनाना चाहता है. यह तभी संभव है जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधीन ज्योति मांझी जदयू से चुनाव लड़े. लेकिन लोगों को अनुमान है कि ज्योति मांझी विधान सभा चुनाव मे अपने समधी की पार्टी मे आ सकती है. उसी प्रकार टिकारी विधानसभा क्षेत्र में भी मामला फंसता नजर आ रहा है. यहां से जदयू के बागी अनिल कुमार विधायक हैं. अब वे जीतन राम मांझी के साथ हैं. इसलिए यहां से उम्मीद है कि हम से अनिल कुमार ही प्रत्याशी होंगे. लेकिन लोजपा टिकारी पर अपनी दावेदारी कर रही है. लोजपा सांसद चिराग पासवान यहां एक बड़ा कार्यक्रम कर उस बात को भी सार्वजनिक कर दिया है कि यहां से लोजपा दावेदारी करेगीं और प्रदेश संगठन सचिव अरविन्द कुमार सिंह यहां से लोजपा के प्रत्याशी होंगे. फरवरी 2005 के चुनाव में अनिल कुमार लोजपा से चुनाव जीते थे. लेकिन अक्टुबर 2005 में अनिल कुमार जदयू में आकर चुनाव लड़े और जीते. 2010 में भी अनिल कुमार जदयू से चुनाव जीते.

लोजपा का कहना है कि 2005 में लोजपा को तोड़कर जो नेता जदयू में चले गए थे, लोजपा उन सब के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी या गठबंधन के नेताओं से ऐसे लोगों को टिकट नही देने का अनुरोध करेगी. उन सब बातों को लेकर मामला यहां भी फंसा है. गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ता है. यहां के सांसद और रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार को लोकसभा चुनाव में अतरी विधानसभा क्षेत्र से अच्छा वोट मिला था. संभावना है कि यह सीट राल-ोसपा को एनडीए की ओर से मिल जाये. एनडीए के नेताओं को लगता होगा कि सब कुछ आसान है. विधानसभा चुनाव में जनता एनडीए को ही मत देगें. लेकिन विक्षुब्ध, बागी, गंठबंधन में टिकट मिलने से वंचित रह जाने वाले नेताओं की एक बड़ी लिस्ट हो जायेगी. जो पांच साल तक इंतजार नही कर सकते. ऐसे नेतागण अपने ही गठबंधन तथा दल के प्रत्याशियों को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाने का काम करेंगे. गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में भी ऐसा ही होगा और उसका सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को ही उठाना पड़ेगा. एनडीए के राजनीतिक गणित को गडबड़ाने के लिए तो बेलागंज से हम तथा टिकारी से लोजपा की दावेदारी काफी है.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी
रालोसपा ने भरी चुनावी हुंकार

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभियान को गति देना शुरू कर दिया है. सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर विधानसभा सीट पर वर्तमान में जदयू का कब्जा है. इस सीट पर दावेदारी को लेकर एनडीए के भाजपा, लोजपा व रालोसपा के संभावित प्रत्याशियों ने अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है. अब तक फैसला होना बाकी है कि इस सीट से एनडीए गठबंधन से किस दल का प्रत्याशी कौन होगा? बावजूद इसके सभी अपना राग अलापने में लगे हैं. पिछले दिनों रून्नी सैदपुर खादी वस्त्रागार परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष ने एक ओर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो दूसरी ओर महागठबंधन को बिहार को बर्बाद करने वाला बताया.

वाल्मीकि/विभा

बिहार विधानसभा चुनाव का समय करीब आने के साथ ही राजनीतिक दलों का चुनावी अभियान भी जोर पकड़ने लगा है. एक ओर केंद्र की भाजपा सरकार की नजर जहां बिहार की सत्ता पर टिकी है, वहीं दूसरी ओर बिहार की राजनीति का सारथी रहें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद व वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कांग्रेस किसी भी कीमत पर भाजपा को बिहार से खदेड़ ने की तैयारी में लगी है, जो स्थितियां बन रही हैं, उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि अबकी बार बिहार में आमने-सामने की टक्कर में एनडीए और महागठबंधन रहेगी. राजनीतिक कार्यक्रमो में महागठबंधन के नेता भाजपा को जुमलेबाज पार्टी की संज्ञा दे रहे हैं, तो भाजपा नेता व कार्यकर्ता लालू-नीतीश को बिहार के लिए घातक होने की बात कह कर अपने पक्ष में जनमत करने का प्रयास कर रहे हैं. मजे की बात यह कि राजनीतिक दलों का चुनावी खेल को करीब से समझ चुकी आम जनता फिलहाल तमाशबीन बनी है. जब गंभीरता से बात चलती है, तो कोई भी किसी भी दल के पक्ष में दिलेरी के साथ कुछ भी कहने से परहेज कर रहा है. मतलब साफ है कि वर्तमान में हर कोई अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है. यकीन नहीं हो रहा कि कौन पार्टी जनता हित को प्राथमिकता देगी? चर्चा यह भी चल रही है कि बड़ी उम्मीद से 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान कर केंद्र में मजबूत सरकार बनाने की दिशा में पहल की, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होता है, तो जनता के मुद्दे की बजाए नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप के बीच सत्र दम तोड़ दे रहा है. सरकारी खजाने से करोड़ो खर्च का आखिर मतलब क्या रह गया है? क्या जनता ने नेताओं को जनादेश केवल राजनीतिक व्यक्तियों पर आरोप-प्रत्यारोप के लिए दिया है? जहां तक बिहार विधानसभा का सवाल है तो गठबंधन की सूली पर लटकी विधानसभा का हश्र चुनाव के बाद क्या होगा? फिलहाल किसी के समझ में नहीं आ रहा. आम लोगों का कहना है कि 2005 के चुनाव में राजद शासन से मुक्ति को लेकर नीतीश ने जनादेश मांगा था. चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो निश्चित रूप से बिहार विकास के पथ पर अग्रसर हुआ. लेकिन 2010 के चुनाव के बाद राजनीतिक माहौल ने अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर बिहार के विकास पर एक बार फिर ग्रहण लगा दिया. अब आलम यह है कि राजद व जदयू, कांग्रेस के साथ मिल कर बिहार के विकास का नया इतिहास गढ़ने की बात कर रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अगर झांका जाए तो विकास की बजाए पार्टी पहली प्राथमिकता नजर आ रही है. मतलब है कि बिहार में महागठबंधन का पहला मकसद भाजपा को किनारे करना है. वहीं दूसरी ओर भाजपा गठबंधन केंद्र की तरह बिहार में भी सरकार बनाने को लेकर चुनावी गोटी खेल रहा है.

अब सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा जरूरी है. इस सीट पर वर्तमान में जदयू का कब्जा है. जदयू की गुडडी देवी लगातार दूसरी बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. अब 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक घेराबंदी को लेकर एनडीए तैयारी में लगी है. एनडीए से भाजपा, लोजपा व रालोसपा के संभावित प्रत्याशियों की इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई है. गठबंधन के तहत सीट किसके पाला में जायेगी, फिलहाल साफ नहीं है. मगर तीनों ही दल के संभावित प्रत्याशी से लेकर पार्टी नेता तक चुनावी कदमताल शुरू कर दिया है. 17 अगस्त को रून्नी सैदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित खादी वस्त्रागार परिसर में रालोसपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. पार्टी के जिलाध्यक्ष राम लक्षण सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पार्टी नेता मोहन कुमार सिंह ने किया. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात का संकेत दे रहा था, कि जनता के हित की बात करने वाला शासक ही बिहार की कुर्सी संभाले. मौके पर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र तेजी से विकास चाहता है, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि केंद्र से प्राप्त राशि का राज्य सरकार उपयोग ही नहीं करती है. साफ लहजे में कहा कि गरीबों की कल्याण की बजाए उपलब्ध राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है. सूबे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति के आधार पर बिहार को बर्बाद करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है. चुनाव को लेकर टिकट के दावेदारों को साफ शब्दो में समझाने का प्रयास भी किया कि सीट का निर्णय एनडीए को करना है. जनता की समस्या पहली प्राथमिकता है, पार्टी की नहीं. कार्यकर्ताओं से कहा कि व्यक्ति अथवा पार्टी को नहीं बल्कि इस चुनाव में एनडीए को देखना है.

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर झा आजाद, प्रदेश सचिव उर्मिला पटेल, उपाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष ललन पासवान, संभावित प्रत्याशी पंकज मिश्रा, जुल्फकार अली, रेखा कुमारी, श्याम कुमार कुशवाहा, रविंद्र शाही, मनीषा शर्मा, राम प्रवेश यादव, मो. आरिफ, अमित सहाय समेत अन्य की मौजूदगी में रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरूण कुमार सिंह ने कहा कि सूबे बिहार में हर जगह जालसाजो का राज है. केंद्र की बिजली योजना पर नीतीश राजनीति कर रहे हैं. सूबे की सरकार को जुल्मी व अराजक की संज्ञा देते हुए साल 1998 के सीतामढ़ी समाहरणालय गोलीकांड पर विस्तार से चर्चा की. कहा कि जिस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजी सरकार का सिपाही नहीं छू सका, उसे राजद शासन में बिहार पुलिस ने गोली मार कर हत्या कर दी. घटना में मारे गये पांच कार्यकर्ताओं को लकड़ी की बजाये टायर से एक ही चिता पर जलाया गया. इस बर्बर हुकूमत की वापसी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए. सांसद राम कुमार शर्मा ने कहा कि नीतीश विद्यालय की जगह मदिरालय खोल रहे हैं. अति पिछड़ा व अल्पसंख्यक को ठगने का काम किया जा रहा है. जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने वाले नीतीश को गरीबों का काम रास नहीं आया और मांझी को सत्ता से बेदखल कर दिया.

कुल मिलाकर सम्मेलन में चुनावी हुंकार भरते हुए रालोसपा नेताओं ने नीतीश व लालू के खिलाफ कार्यकर्ताओं से गोलबंद होने की अपील की. अब जदयू के कब्जे वाले इस सीट को बचाए रखने के लिए महागठबंधन का चुनावी पासा क्या होगा, इस पर सभी की नजर टिकी है. रालोसपा के संभावित प्रत्याशी पंकज मिश्रा की माने तो आम लोगों को अब केवल वैसे प्रतिनिधि की दरकार है जो स्थानीय समस्याओं के निदान की दिशा में सक्रिय रहने वाला हो. चुनावी साल में सभाओं का दौर अभी बाकी है. अब देखना है कि अबकी बार यह सीट एनडीए के तहत किस दल के पाले में जाती है.■

feedback@chauthiduniya.com

दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना बनेगा चुनावी मुद्दा

सुरेश चौहान/राम शंकर दास

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग बनेगा जबर्दश्त चुनावी मुद्दा, छात्रों, नौजवानों, अभिभावकों एवं बुद्धिजीवियों अर्थात समाज के सभी वर्गों की यह मांग अब विकराल रूप लेने लगी है. इस मांग का समर्थन तो सभी राजनीतिक दल करते हैं लेकिन विधायक बनते ही भूल जाते हैं. जिसका खामियाजा प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा. छात्र समुदाय इस मांग की पूर्ति के लिए विभिन्न जनतांत्रिक प्रावधानों तथा धरना, प्रदर्शन एवं अनशन के सहारे सरकार का ध्यान अपनी ओर कर रहे हैं. लेकिन सरकार का उस ओर ध्यान नही देना उसकी संवेदनहीनता का जोतक है. विवश होकर छात्र समुदाय नंग-धड़ंग प्रदर्शन एवं समाहरणालय गेट पर धरना दे रहे हैं.

यों तो सभी छात्र संगठन की यह मांग है कि बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर दिनकर विश्वविद्यसलय की स्थापना की जाय. लेकिन एनएसयूआई इस मांग को लेकर काफी मुखर है. वर्त्तमान में बेगूसराय जिले के सभी कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अधीन है. साथ ही दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले के भी सभी कॉलेज उस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में है. एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रतिनिधि निशांत कुमार कहते हैं कि बेगूसराय से दरभंगा की दूरी 125 किलोमीटर है. छात्रों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी विश्वविद्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है. उसमें पूरा दिन का समय लग जाता है और उसी दिन उसका काम हो जाएगा उसकी गारंटी नहीं होती है. जिससे छात्र परेशान होते हैं और अभिभावक की गांठ ढ़ीली होती है. छात्राओं की परेशानी की कल्पना की जा सकती है. मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन 47 अंगीभूत एवं 26 संबंध कॉलेज है. बेगूसराय के कॉलेजों में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग एक लाख है. 125 किमी दूर बैठे विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर नियंत्रण रखने में अक्षम साबित हो रहा है. जिससे अनेक समस्यायें उत्पन्न हो रही है. प्राध्यापकों की काफी कमी एवं वर्ग संचालन नहीं होने से छात्रों में अनुशासन हीनता बढ़ती जा रही है. सिर्फ नामांकन एवं परीक्षा तक छात्रों का संबंध कॉलेज से रह गया है. कॉलेज में असामाजिक तत्वों का बोलबाला है. अध्यनेतर क्रियाकलाप ठप है. छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव है.

निशांत कुमार कहते हैं कि बेगूसराय के जीडी कॉलेज का मिथिला विश्वविद्यालय में खास स्थान है. यहां पड़ोसी जिले खगड़िया, लखीसराय एवं जमुई से भी छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं. वर्त्तमान सत्र में 4 हजार सीट के विरूद्ध 90 हजार आवेदन नामांकन के लिए ऑनलाइन प्राप्त हुए. छात्र संगठनों एवं अभिभावकों की मांग पर कम से कम 25 प्रतिशत सीट की संख्या बढ़ाने के लिए प्राचार्य ने विश्वविद्यालय को मांग पत्र भेजा लेकिन 25 अगस्त तक कोई जबाव नहीं आया है. निशांत कुमार का कहना है कि छात्र संगठन का चुनाव समय से होने पर निर्वाचित छात्र नेता विश्वविद्यालय की बैठक में भाग लेते थे और छात्रों की समस्या उठाते थे. लेकिन विडम्बना यह है कि 1988 से ही छात्र संगठनों का चुनाव विश्वविद्यालय नहीं करा रहा है जिससे छात्रों की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है और कॉलेज का वातावरण खराब होते जा रहा है. निशांत कुमार का मानना है कि उपरोक्त सभी समस्याओं का एकमात्र निदान है बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना. जिससे कॉलेज के विकास, प्राध्यापकों की कमी, नामांकन के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने एवं छात्र-छात्राओं की अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से सीधा सम्पर्क एवं संवाद स्थापित होगा. छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों की उस न्यायोचित मांग को लेकर एनएसयूआई जनतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन-अनशन करते आ रहा है. संघर्ष को तेज करते हुए पिछले दिनों भी उस संगठन ने निशांत कुमार, टिंकु कुमार, अभिषेक कुमार, रवि कुमार, मो. जसीम, सुमंत कुमार, प्रिंस कुमार, राहुल कुमार आदि के नेतृत्व में समाहरणालय द्वारा पर नंग-धड़ंग प्रदर्शन करते हुए धरना देकर मांग पत्र डीएम को सौंपा. एनएसयूआई ने निर्णय लिया है कि विधानसभा चुनाव में इसे सशक्त मुद्दा बनाते हुए आन्दोलन तेज किया जाएगा.■

एक नज़र
चुनावी हलचल

योजनाओं में भ्रष्टाचार

हाजीपुर (वैशाली) जनता की समस्याओं को लकर प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय महआ के प्रागंण में क्रांतिकारी साम्यवादी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारी पार्टी कार्यालय मंगरू चौक से जूलूस की शक्ल में घूमते एवं नारे लगाते हुए महुआ थाना चौक तबदील हो गया. पार्टी का जनहित में मांग थी कि भूमि अधिग्रहन बिल वापस लो महगाई एव भ्रष्टाचार पर रोक लगे, बिजली बिल नियमित तथा विद्युत आपूर्ति 22 घंटे रहने की गारन्टी हो. इन्दिरा आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार बन्द हो आदि मांगो को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया. सभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्री लाल राय में संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार भूमि अधिग्रहण देश में लाकर हलचल पैदा कर दिया है. इससे एक ओर किसान तबाह तो दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग काफी खुश नजर आ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपने तमाम वादों से मुकर रही है. इसके अच्छे दिन के सपने भी बेनकाब हो चुकी है. अपराध, महिला उत्पीड़न, शैक्षणिक अराजकता बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि राजद एवं लोजपा परिवारवाद के शिकार हो चुके हैं. हमारी पार्टी 50 प्रतिशत महिला एवं 50 प्रतिशत नौजवानों को टिकट देने की घोषणा कर रही है. आज की सभा को मुनीन्द्र झा कुजात गांधी, नागेन्द्र यादव, मैनेजर यादव, राम बालक शर्मा, राम सेवक पासवान, श्यामनन्दन राय, चन्देश्वर पासवान, उमाकांत राय, शंकर पासवान, महेन्द्र पाल आदि लोगों ने संबोधित किया तथा अंत में अंचलाधिकारी को मांग की एक प्रति सौंपी.

– भारती

सुहेली ने भेजा मुख्यमंत्री को पत्र

परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी सुहेली मेहता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला खत भेजा है. पत्र में उन्होंने बीती 27 जुलाई को परबत्ता के नयागांव शिरोमणि टोला में दलितों पर हुए अत्याचार व प्रशासन की लापरवाही सहित पूरी घटना का जिक्र करते हुए पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगान की मांग की. श्रीमति मेहता ने कहा कि खगड़िया के परबत्ता के शिरोमनी टोला में अंतरजातीय विवाह को मुद्दा बनाकर 400 से 500 की संख्या में दबंगों ने दलितों के परिवारों पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने दलित महिला-पुरुष सहित परिवार के सभी सदस्यों को घर से निकालकर बुरी तरह पिटाई की. महिलाओं को नग्न कर पीटने के साथ-साथ मानवता को शर्मसार किया गया. श्रीमति मेहता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीड़ित परिवारों को गांव से दूर कहीं दूसरी जगह बसाने, जान-माल की क्षति का मुआवजा, दोषियों को बचाने वाले पुलिस प्रशासन के अधिकारी की भूमिका की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की. सुहेली मेहता ने बताया कि महिला होने के नाते वह महिलाओं के दर्द को बखूबी समझ सकती है. उन्होंने पीड़ितों का इंसाफ दिलाने के लिए हर दरवाजा खटखटाने का एलान किया है.

– गीता कुमार

रुन्नीसैदपुर में गरज रहा है विकास : राजेश

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास गरज रहा है. आम लोगों में राज्य सरकार के प्रति विकास को लेकर विश्वास कायम है. पिछले दिनों प्रखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं आइएपी योजना के तहत निर्मित सामुदायिक सुविधा केंद्र, गोदाम व सड़क का उद्घाटन करते हुए वरीय जदयू नेता राजेश चौधरी ने उक्त बातें कही.प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित हजार एमटी क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब धान व गेहूं क्रय के बाद रखने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. मौके पर बीडीओ नीरज आनंद, हरि शंकर सिंह, मुकेश कुमार, नरेंद्र सिंह, देवेंद्र दास, नागेंद्र सिंह, नवीन कुमार, हरि किशोर सिंह, रामजी मंडल, सुनील कुमार व नवल गुप्ता समेत अन्य थे. वहीं दूसरी ओर राजेश ने गिद्धा फुलवरिया पंचायत में 4.50 लाख की लागत से ईट सोलिंग, लालपुर में 7.30 लाख की लागत से पीसीसी सड़क, सोनबरसा में 7.30 लाख एवं बघारी में 7.40 लाख की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया. उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रमों में नजरे आलम, रामचंद्र राय, राम जतन बैठा, बच्चा झा, बिंदेश्वर सहनी, चुल्हाई साह, रामचंद्र गौड़, अरुण चौधरी, राम उदार राय, अवधेश साह, देवेंद्र पांडेय, कलाधर पांडेय व कमल साह समेत अन्य थे. वहीं प्रखंड के रामपुर व गायघाट गांव में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अलग-अलग दो सड़कों का उद्घाटन राजेश चौधरी ने किया. नानपुर प्रखंड के मोहनी पंचायत में नव निर्मित पीसीसी सड़क का भी उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान राजेश चौधरी ने कहा कि सूबे की सरकार की योजना को स्थानीय जदयू विधायक गुड्डी देवी की सक्रियता से कार्यान्वित कराया जा रहा है. इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलता रहेगा.

– विभा सिन्हा

पीएम ने दी है बड़ी सौगात : पूर्व विधान पार्षद

शिवहर स्थानीय निकाय के पूर्व विधान पार्षद वैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि 18 अगस्त बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद बिहार को विकसित बनाने पहली बार इतनी बड़ी सौगात दी है. जिला मुख्यालय डुमरा स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कहा कि सवा लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज हर बिहारी का सपना साकार करने में मददगार साबित होगा. श्री प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि पैकेज का स्वागत करने की बजाये सीएम ने इक्त पैकेज के लिए पीएम की आलोचना कर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है. मौके पर भाजपा विधायक मोतिलाल प्रसाद, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल, जिला महामंत्री अशोक ठाकुर व मीडिया प्रभारी नीरज गोयनका समेत अन्य थे.

– आदित्यानंद

नीरज बने भाजपा मीडिया प्रभारी

सीतामढ़ी जिला भाजपा संगठन ने आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. हाल ही में जिला पार्टी संगठन चुनावी अभियान व पार्टी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु नये मीडिया प्रभारी के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता नीरज गोयनका को कमान सौंपी है. गोयनका ने कहा कि पार्टी संगठन के दायित्वों का निर्वहन पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सीतामढ़ी जिले में मजबूत स्थिति में कायम है. विरोधियों के तमाम भ्रमजाल आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम के साथ ही टूट जायेगा. कहा कि पार्टी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ विकास विरोधी ताकतो को रोकने के लिए तैयार हैं.■

– विकास कुमार

सीतामढ़ी

जाति और पार्टी के बीच फंसा समस्या का निदान

पिछले तकरीबन डेढ़ दशक से सीतामढ़ी शहर जल जमाव का केंद्र बना हुआ है. जब बरसात के दिनों में दुकान से लेकर मकान और सड़क से लेकर गोदाम तक पानी घुसने लगता है, तब शहर के कोने-कोने पर सड़क जाम, धरना-प्रदर्शन का अखबारी दौर जोर-शोर से शुरू होता है. प्रशासनिक अमले से लेकर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों तक के खिलाफ लोग कुछ भी बोलने से परहेज नहीं करते हैं. शहर के मध्य से प्रवाहित होने वाली लक्ष्मणा नदी महज एक नाला बन कर रह गई है, लेकिन आज जब समस्या निदान के लिए ठेकेदार का चुनाव करने का वक्त आया है. तब ऐसा लगता है कि सभी की जुबान बंद हो गई है....

वाल्मीकि कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव सामने है. राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशी जहां अपनी दावेदारी को लेकर व्यस्त हैं, वहीं स्थानीय लोग जाति व पार्टी का झंडा बुलंद करने में मस्त हैं. इस बीच स्थानीय समस्या निदान का मसला मौन होकर रह गया है. सीतामढ़ी शहर को बाढ़ के संभावित खतरा से बचाव को लेकर साठ के दशक में रिंगबांध का निर्माण कराया गया था. तब शहर की आबादी भी बहुत अधिक नहीं थी. समय गुजरने के साथ ही शहरी क्षेत्र की आबादी बढ़ती गई और क्षेत्र की संकीर्णता में भी इज़ाफा हुआ. हाल के दशक में यह आलम है कि शहर के तकरीबन सभी वार्डों में बरसात के दिनों में जल जमाव एक गंभीर चुनौती बन जाती है. शर्मनाक तो यह कि शहर स्थित ऐतिहासिक जानकी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन मुश्किल हो जाता है, तो कोट बाजार बड़ी मस्जिद के समीप सड़क नाला के पानी में डूब जाता है, लेकिन अभी तक पानी निकासी का स्थायी उपाय नहीं किया जा सका. बरसात शुरू होने के साथ ही शहर के व्यवसायी से लेकर आम नागरिक तक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस परेशानी का मुख्य कारण शहर के पुराने नासी नाला का व्यापक स्तर पर किया गया अतिक्रमण है. नासी के जमीन पर दबंगों के कब्जा का यह आलम है कि अब महज एक मामूली नाला भर नासी नज़र आ रही है. ऐसा भी नहीं है कि जिला प्रशासन के आलाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उस सच्चाई से अनजान हैं, लेकिन कोई भी इस दिशा में पहल करना मुनासिब नहीं समझता है. जिला प्रशासन की जहां तक बात है, तो उसकी सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व में विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद ने जब मामले को सदन में उठाया था तब विभागीय मंत्री ने नासी की जमीन का मापी करा कर अतिक्रमण मुक्त कराने का फरमान भेजा था, लेकिन मनमानी प्रशासनिक कार्यशैली का आलम रहा कि मामूली कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे यथावत छोड़ दिया गया. नव पदस्थापित जिलाधिकारी राजीव रौशन ने उस गंभीर समस्या को दूर करने की दिशा में पहल का भरोसा पत्रकार सम्मेलन में दिलाया है. अब देखना है कि कुछ होता है अथवा पूर्व की तरह पुन: फाईल को दूसरे के भरोसे पर छोड़ दिया जाता है.

डीएम राजीव रौशन

डॉ. वसंत कुमार मिश्र

राम कुमार शर्मा

सज्जन कुमार सुंदरका

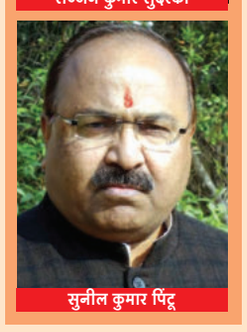
सुनील कुमार पिंटू

एक दूसरी अहम समस्या भारत-नेपाल सीमा से लेकर सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर व मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड तक के किसानों के लिए गंभीर बनी है. जिले के बीच से प्रवाहित होने वाली पावन लक्ष्मणा नदी में पानी का बहाव सालो पूर्व से बंद पड़ा है. नतीजतन त्यौहार के समय जहां लोगों को अपने दरवाजे पर कुंआ खोदना पड़ता है, वहीं किसानों को सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ता है. मगर जिले के जन-प्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक महकमा तक को उस समस्या के निदान करने की पहल करने की फुर्सत अब तक नहीं है. बरसात के समय जहां देश के कई प्रांतों में बाढ़ की तबाही से लोग परेशान हैं, वहीं सीतामढ़ी के इस पौराणिक नदी में जलकुंभी भरा पड़ा है. नदी के दोनों किनारे जंगल का साम्राज्य है.

जहां तक समस्या निदान को लेकर प्रतिनिधियों की सजगता का सवाल है, तो उस दिशा में कोई रूचि नहीं ले रहे हैं. सभी की नज़र सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों पर अटकी है. सड़क निर्माण से लेकर भवन, नाला समेत अन्य कार्यों में कमीशनखोरी की लूट मची है. जनप्रतिनिधि अपने चहेतों के बीच विकास योजनाओं का प्रसाद वितरण कर चुनावी किला फतह करने की योजना में लगे हैं. जानकारों की बातों पर यकीन करें, तो सरकार ज्यादा नहीं पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान कराए गए विकास कार्यों की जांच करा ले, तो स्वत: मामले की सच्चाई सामने आ सकती है. लेकिन ऐसा होना संभव नहीं दिख रहा है. सरकार में बैठे जिम्मेदार व ओहदेदार नेताओं से लेकर अधिकारी तक को सत्ता की चिंता सता रही है. जिले के मतदाताओं में जागरूकता का यह आलम है कि सभी चुनावी मौसम के दस्तक के साथ ही जातीय गणना के साथ पार्टी का परचम लहराने की योजना में लगे हैं. किस सीट से कौन प्रत्याशी किस दल के समर्थन से चुनावी समर में उतरेगा और राज्य में सरकार किसकी बनेगी? इस बात को लेकर ही दैनिक चुनावी चौपाल सज रही है, लेकिन स्थानीय गंभीर समस्याओं के निदान को लेकर प्रतिनिधियों के चुनाव की चर्चा मौन है. बरसात के समय सड़क जाम कर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने वालों को फिलहाल जाति व पार्टी की चिंता ही खाए जा रही है. समाज के प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि बहुदलीय झंडा ढ़ोने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि स्थानीय मामलों को लेकर चर्चा करने तक की फुर्सत किसी के पास नहीं रह गई है. सभी चुनावी मौसम आने के साथ ही जाति-पार्टी का गुणा-भाग करने लग जा रहे हैं. कुछ को इस बात का भी डर सताने लगता है कि कहीं कुछ बोलने के कारण अपने जाति के नेता को चुनाव में हानि न हो जाए.

सीतामढ़ी की गंभीर समस्या के सवाल पर रालोसपा के सांसद राम कुमार शर्मा का कहना है कि नासी को अतिक्रमण मुक्त कर भलाई के लिए शहर के प्रबुद्ध लोगों से आग्रह करते रहे हैं. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती एवं विभागीय पदाधिकारियों से नदी की समस्या का निदान करने का आग्रह किया है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिल सकी है. नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि शहर के नासी नाला के लिए 1 करोड़ 38 लाख की योजना स्वीकृत हो चुकी है. लीला साह पुल से लेकर लखनदेई नदी तक मिलाया जाएगा. लखनदेई नदी के सवाल पर कहा कि मामला अंतरराष्ट्रीय है. स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्रालय से समस्या के निदान का आग्रह किया है. लोक चेतना मंच के तहत समस्या निदान का गुहार लगाने वाले डॉ. बसंत कुमार मिश्रा नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि जिला के जन-प्रतिनिधि अब स्वयं का प्रतिनिधि बन कर रह गए हैं. जहां अपना लाभांश नजर आता है उसी ओर ध्यान लगाते हैं और समस्यों का निदान मुश्किल नजर आ रहा है. जदयू के जिला उपाध्यक्ष सज्जन कुमार सुंदर का कहना है कि नासी अतिक्रमण की शिकार है. कोई खाली कराने का साहस नहीं कर रहा है. नदी आम लोगों की प्राण है, लेकिन उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए सभी जन-प्रतिनिधि अब तक विफल रहे हैं.

अब देखना है कि मतदाता समस्या के निदान के लिए दुहाई देकर वोट मांगने वालों से पिछले वादों का हिसाब करती है अथवा पुन: जाति व पार्टी के नाम पर एक बार फिर अपनी आंखे मूंद लेती है. अगर जाति व पार्टी को प्राथमिकता देते हैं, तब उन्हें समस्या निदान के लिए सड़क जाम कर नारेबाजी करने का कोई हक नहीं बनता है. स्थानीय अखबारों में छपने की खातिर सड़क पर आने से भी परहेज करना होगा. प्रशासनिक तंत्र को चोर व कमीशनखोर कहने से बाज आना होगा अन्यथा प्राथमिकता के आधार पर समस्या निदान की मांग को चुनावी मुद्दा बनाने की योजना पर अभी से ही लगना होगा. आग लगने पर कुंआ की खुदाई करने वाली बात से अब शायद काम चलने वाला नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

बक्सर

बक्सर तथा भोजपुर के पांच विधायकों के टिकट पर ग्रहण

बक्सर तथा भोजपुर जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में टिकट हथियाने तथा काटने को लेकर हर दलों में शह और मात का खेल शुरू हो गया है. बक्सर की भाजपा विधायक तथा पूर्व मंत्री प्रो. सुखदा पाण्डेय तथा ब्रहम्पुर विधायक दिलमणी देवी दलीय नेताओं से मिल रही चुनौती के कारण खासे परेशान है. भाजपा के लोकल तथा बाहरी मुद्दो पर चल रही गूटबाजी पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के सामने ही उजागर हो गयी. सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने उनके समक्ष जमकर हंगामा करते हुए विधायक प्रो. सुखदा पाण्डेय के विरूद्ध नारे बाजी भी की. इसका खामियाजा भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप दूबे को निलंबन के रूप में भुगतना पड़ा. परिणाम यह हुआ कि दूबे के समर्थन तथा विधायक के विरूद्ध कार्यकर्ता सड़क पर आ गये.

जय मंगल पाण्डेय

इस बार विधानसभा चुनाव में बक्सर तथा भोजपुर जिले में कई तरह के उलट फेर होगें और नये समीकरण भी बनेगें. राजनीतिक कायासों के बीच भाजापा के दो, राजद में दो तथा जदयू के एक विधायक के टिकट कटने की संभावना व्यक्त करते हुए नये दावेदारों द्वारा टिकट हथियाने की होड़ शुरू कर दी गयी है. बक्सर में टिकट को लेकर भाजपा का धमासान सड़को पर आ गया है. दूसरी ओर गठबंधन दलों के नेताओं में टिकट को लेकर कई तरह के गांव बंधे हुए है. इस बार बक्सर तथा भोजपुर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी परिदृश्य काफी रोचक होगा. लेकिन राजद तथा जदयू के गठबंधन में कई दावेदारों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हासिये पर चली जाएगी. बक्सर तथा भोजपुर जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में टिकट हथियाने तथा काटने को लेकर हर दलों में शह और मात का खेल शुरू हो गया है. बक्सर की भाजपा विधायक तथा पूर्व मंत्री प्रा. सुखदा पाण्डेय तथा ब्रहम्पुर विधायक दिलमणी देवी दलीय नेताओं से मिल रही चुनौती के कारण खासे परेशान है.

भाजपा के लोकल तथा बाहरी मुद्दों पर चल रही गूटबाजी पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के सामने ही उजागर हो गयी. सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने उनके समक्ष जमकर हंगामा करते हुए विधायक प्रो. सुखदा पाण्डेय के विरूद्ध नारे बाजी भी की. जिसका खामियाजा भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप दूबे को निलंबन के रूप में भुगतना पड़ा. परिणाम यह हुआ कि दूबे के समर्थन तथा विधायक के विरूद्ध कार्यकर्ता सड़कों पर आ गये. विरोधी प्रो. पाण्डेय को 70 पार करने की दुहाई भी दे रहे है. वैसे सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने दूबे के निलंबन को गलत कहा था. अब दूबे प्रधानमंत्री की नीतियों की गांवो में अलख जगा रहे हैं. उसी प्रकार ब्रहम्पुर की भाजपा विधायक दिलमणी देवी भी दलीय विरोध से घिर गयी हैं. राजद को हरा कर 2010 में चुनाव जीतने वाली विधायक का दलीय नेताओं से छत्तीस के रिश्ते जगजाहिर है. उनके घटिया विकास कार्य तथा दलिय नेताओं की उपेक्षा की नब्ज पकड़ कर भाजपा के पूर्व विधायक डॉ स्वामी नाथ तिवारी ने अपने राजनीतिक मुहिम से दिलमणी देवी की मुश्किले बढ़ गयी है. और नेता बदलने की मुहिम दलिय नेताओं ने शुरू कर दी है.

भाजपा के एक-एक सीटों को जीतने की चुनौती से दोनों ही मैडम के राजनीतिक स्थिति पर कायास लगाते हुए दावेदार भी सक्रिय हो गये है. जिले में भाजपा के चार सीटों के लिए पूर्व विधायक डॉ स्वामी नाथ तिवारी, भाजपा बुद्धिजीवी मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष शंभूनाथ पाण्डेय, डुमरांव महाराज तथा पूर्व सांसद कमल सिंह के प्रपौत्र शिवांग विजय सिंह, परशुराम चतुर्वेदी, विश्वनाथ राम आदि नेता अलग अलग सीटो के प्रबल दावेदार है. भोजपुर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में चार भाजपा के कब्जे में है. शेष दो सीटो पर काबिज राजद विधायक पार्टी लाइन से हटकर खुद की परेशानी मोल ली है. जगदीशपुर से 2010 के चुनाव में जदयू के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को हराकर राजद के भाई दिनेश चुनाव जीत गये. फिर अपना कद बढ़ाने के लिए पार्टी के नीतियों से हटकर विकास के नाम पर राजनीतिक ड्रामा करने लगे. विधानसभा चुनाव में हारे भगवान सिंह कुशवाहा पाला बदल कर 2014 में आरा लोकसभा से राजद का टिकट हथिया लिया. राजद सुप्रिमों ने विधायक की महत्वाकांक्षा का पर कतरने के लिए उनके विरोधी को प्रत्याशी बना दिया, तो विधायक का पारा सातवे आसमान पर चला गया. उन्होने सुप्रिमों लालू प्रसाद के विरूद्ध खुलेआम बयनबाजी कर दलीय प्रत्याशी का कब्र भी खोदते रहे. फिर सांसद पप्पु यादव के डाक्टर विरोधी मुहिम की आड़ में राजद विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहे. राजद नेताओं ने उनके निहित स्वार्थ की कलई सुप्रिमों के पास खोल कर उन्हे बेटिकट करने के लिए सक्रिय है. क्षेत्र में ऐसी चर्चा है कि राजद विधायक सुप्रिमों की नाराजगी से वाकिफ है और दूसरे दल में भी विकल्प तलाश रहे है. बड़हरा में जदयू प्रत्याशी को हराकर 2010 में चुनाव जीतने वाले राजद के कदवार विधायक राधवेन्द्र प्रताप सिंह आरा लोकसभा से राजद टिकट के प्रबल दावेदार थे. लेकिन उन्हे निराशा हाथ लगी और उस कारण लोकसभा चुनाव में तटस्थ बने रहे. पार्टी लाइन से हटकर उनके वेबाक विचार तथा विकास के कार्यो के अलावे विश्वश्नीयता को लेकर बेटिकट होने की चर्चा आम है.

भोजपुर में तरारी विधानसभा के एकलौते बाहुबली विधायक सुनील पाण्डेय की आरा सिविल कोर्ट बम बालस्ट मामले में गिरफतारी के बाद जदयू की कलई ही खुल गयी. उसके अलावा पाण्डेय के विरूद्ध लंबित मामलो के फाइल खुलने से उनके राजनीतिक अस्तित्व पर संकट आ गया है. विधान परिषद के चुनाव में उनके भाई हुलास पाण्डेय से पार्टी ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया. आरा-बक्सर विधान परिषद में जदयू के टिकट पर 2009 में चुनाव जीतने वाले हुलास पाण्डेय का पता साफ करने के लिए जदयू ने समझौतें में यह सीट राजद को देकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी. फिर लोजपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ने वाले हुलास पाण्डेय और उनके भाई सुनील पाण्डेय का करिश्मा भी काम नही आया. चुनाव हारने के दूसरे दिन ही विधायक की गिरफतारी से यह तय हो गया कि जदयू अब दोनो भाईयों से अपना पिण्ड छुड़ाना चाहती है. फिलहाल दोनो का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है.■

feedback@chauthiduniya.com

सबका साथ - सबका विकास

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा के प्रवक्ता संजय मयूख ने अपनी पार्टी का चुनावी विज़न बताते हुए कहा है कि 2015 का विधानसभा चुनाव हम विश्वासघात के खिलाफ लड़ेंगे. बिहार की जनता के साथ जो धोखेबाजी हुई है. उसका जबाव नीतीश कुमार को देना होगा. हमने जनता को सुशासन का वादा किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने आंतकराज और जंगलराज से हाथ मिला लिया है. यह पूरी लड़ाई विकास और विनाश की लड़ाई है. जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास की बयार बह रही है वह बिहार में रुका हुआ है, यहां सिर्फ जंगलराज आंतकराज हो गया है. हमने बिहार को जंगलराज और आंतकराज से मुक्त करवाया था लेकिन उन्होंने जंगलराज और आंतकराज को पुन: कायम कर दिया है. हमारा मुख्य विजन विकास का है हम शिक्षा, स्वास्थ, बिजली, पानी उन सब चीजों पर काम करना चाहते हैं. यह सरकार केंद्र सरकार से कोई सहोयगात्मक रवैया नहीं अपना रही है. जिस कारण बिहार के विकास कि रफ्तार रुकी हुई हैं.

महिलाओं के प्रति हमारी सोच सकारात्मक है हमने ही पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण, लक्ष्मी लाडली योजना समेत कई कार्य किये हैं. यह सब हमारी देन है. हम सिर्फ वादे ही नहीं करते है उसको निभाते भी हैं. हम समस्या पर नहीं समाधान पर विश्वास करते हैं और हम समाधान ही करेंगे क्योंकि यहां समस्याओं का अंबार है. हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है. पिछले दिनों पटना में दिन दहाड़े भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है. पूरे राज्य में ऐसी ही घटना घटित हो रही है. यहां का आम जन जीवन आज फिर उसी तरफ अग्रसर है. हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है और उसका समाधान हम ही कर सकते है. हमारी प्रशासनिक क्षमता को सबने देखा है 7 वर्षों तक कहा था जंगलराज सभी अपराधी दुबक गऐ थे या फिर जेल में थे. हमारी पार्टी एक सशस्त विकल्प है उस सरकार का और जनता ने हमें चुन कर उसका एहसास दिला दिया है. आज तो लगभग सभी नियोजित लोग आंदोलन कर रहे हैं सब लोगों को इस सरकार ने भुलावे में रखा है. हम राज्य कि जनता को एक साफ-सुथरी एवं स्वच्छ सरकार देंगे. सबका साथ और सबका विकास जिस नारे के साथ हम दिल्ली में उतरे थे. उसी नारे के साथ हम बिहार में भी जनता के समक्ष जाएंगे.

डीएनए के बारे में बोलते हुए कहा कि हमने नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में डीएनए कराने की बात कही थी. आतंकराज-जंगलराज के बारे में कहा था. लालू यादव कभी नीतीश कुमार के विषय में कहा करते थे कि उनके पेट में दांत है यदि डीएनए का सैंपल दिया जाएगा तो. उसका भी जबाब लालू यादव को देना चाहिए.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

07 सितंबर–13 सितंबर 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

नेताओं को बर्बाद कर रहा सत्ता गलियारे का छह नंबर बंगला

मुख्यमंत्री आवास के बगल में भूत-बंगला!

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कालीदास मार्ग पर एक बंगला है. वह बंगला अब तक जिसे भी आवंटित हुआ और जो कोई उसमें रहने गया उसका राजनीतिक और निजी जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. वह तरह-तरह की परेशानियों में घिर गया. उत्तर प्रदेश के ऐसे कई नामी-गिरामी नेता और मंत्री हैं, जो उस बंगले में रहे, और आज तक कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं. जानिए इस बंगले की पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में...

मनोज दुबे

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कालिदास मार्ग वीवीआईपी इलाका है. यहां 5 नंबर बंगले में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सरकारी आवास है. मुख्यमंत्री का पड़ोसी होना किसी के भी लिए सौभाग्य और प्रतिष्ठा का कारण हो सकता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. पड़ोस के छह नंबर बंगले के बारे में अब यह बातें उड़ रही हैं कि यह भूत-बंगला है और इसमें रहने वालों के लिए उनकी बरबादी का कारण बन जाता है. इस बंगले में उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेता पांव रखकर पछता चुके हैं. बहुतों का तो राजनीतिक करियर ही दांव पर लग गया. कई अन्य राजनीतिक-प्रशासनिक हस्तियों को तरह-तरह की मुसीबतों और दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा. मुख्यमंत्री आवास के पड़ोस का यह बंगला क्या सचमुच दुर्भाग्य लाने वाला बंगला है? इसमें रहने वाले कुछ नेताओं के जीवन-अनुभव पर नजर डालें, तो इस सवाल का जवाब हां ही होगा. 6 कालिदास मार्ग के नाम से जानी जाने वाली कोठी में पिछले दिनों जावेद आबदी रह रहे थे. उन्हें यह बंगला उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाये जाने के बाद मंत्री स्तरीय हैसियत मिलने के चलते आवंटित किया गया था. आबदी साहब इसमें रहते हुए अपना पद बचाकर नहीं रख पाए. उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया. खबरें तो यह आईं कि उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिली थीं, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि उन्हें छह नंबर बंगला रास नहीं आया. वही बंगला उनकी बरबादी का सबब बन गया. उनका पद तो गया ही उन्हें पुत्र शोक का भी सामना करना पड़ा. यह किसी के भी लिए बहुत दुखद और त्रासद व्यक्तिगत क्षति है.

इस बंगले का जिक्र आते ही डा. वकार अहमद शाह का नाम जेहन में उभरता है, जो जीवित भी रहे तो मृतप्राय ही रहे. वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनी तो वकार साहब को उर्जा विभाग में मंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री आवास के पड़ोस में छह नंबर बंगला उन्हें आवंटित किया गया. इस बंगले में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही वकार साहब गंभीर रूप से बीमार हो गए और कोमा में ही पड़े रहे. उन्होंने एक बार जो बिस्तर पकड़ा तो फिर उठ नहीं पाए. बंगले को अपशकुनी छाया से बचाने की हजार कोशिशें भी काम नहीं आईं. इसी बंगले में बहुजन समाज पार्टी के शक्तिशाली नेता और किसी जमाने में मायावती के विश्वस्त रहे बाबू सिंह कुशवाहा एक लंबे अरसे तक रहे, लेकिन उनका जो हश्र हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है. उनकी मुसीबतें और उनका जेल-प्रवास इसी आवास में रिहाइश का नतीजा है, ऐसा लोग कहते हैं. बाबू सिंह कुशवाहा 2008 से लेकर 2012 तक छह कालिदास मार्ग में रहे और सत्ता का जरूरत से ज्यादा उपभोग किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका आने वाला वक्त छह नंबर बंगले में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे बीतेगा. कुशवाहा एनआरएचएम, लैकफेड जैसे घोटालों के शिकंजे में इस कदर जकड़े हैं कि जेल से बाहर आने के लिए तरस रहे हैं. उनका राजनीतिक करियर भी चौपट ही हो गया है. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों के वक्त अपना करियर बचाने के लिए उन्होंने भाजपा तक छलांग लगाने की कोशिश की लेकिन कुशवाहा के राजनीतिक करियर पर ऐसी छाया पड़ी कि उबर नहीं पाए. मुलायम ने भी पहले तो हाथ डाला, पर जल्दी ही हाथ पीछे खींच लिया. राजनीति के अखाड़े में अपना वजूद बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई, लेकिन वह भी उनके काम नहीं आई. लोग कहते हैं कि छह नंबर बंगले में लंबे अरसे तक रहने की वजह से ही बंगले की अपशकुनी छाया उनका पीछा नहीं छोड़ रही है.

एक जमाने में समाजवादी पार्टी के भीतर जिन अमर सिंह की तूती बोलती थी और जो आज सपा में प्रवेश के लिए गाहे-बगाहे मुलायम सिंह यादव की चौखट पर हाजिरी लगाते पाए जाते हैं, उनका भी इस छह नंबर बंगले से ताल्लुक रहा है. अमर सिंह को मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश विकास परिषद का ताकतवर और अति-प्रभावकारी पद दिया गया था. यह विचित्र किन्तु सत्य नुमा संयोग ही था कि वर्ष 2004 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश विकास परिषद का कार्यालय कालिदास मार्ग स्थित छह नम्बर बंगले में ही था. कभी टेलीविजन के परदों पर सपा का मुखड़ा बनकर छाये रहने वाले अमर सिंह आज कहां हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने वाले लोग बंगला नम्बर 6 की परिधि में झांकने लगते हैं. अमर सिंह का हाल यह हुआ कि सपा तो सपा, बॉलीवुड के उनके दोस्तों ने भी उनसे किनारा कर लिया और राजनीतिक दुनिया के उनके दोस्त उन्हें छूने से भी डरने लगे. जयप्रदा ने साथ दिया, नहीं तो अमर सिंह का नामलेवा भी कोई नहीं रहता. राजनीति में तो अमर सिंह को झटका लगा ही, व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें गुर्दे की कठिन और तकलीफदेह बीमारी से गुजरना पड़ा. अब वह प्रत्यारोपित गुर्दे के सहारे चल रहे हैं. क्या सचमुच अमर सिंह को इस हालत में पहुंचाने के पीछे छह कालिदास मार्ग पर मंडराती प्रेत-छाया मुख्य वजह है? इस सवाल का जवाब परिस्थितियां खुद ही हैं.

6 कालिदास मार्ग की मार झेलने वाले बाबू सिंह कुशवाहा ही अकेले बसपा नेता नहीं हैं. कभी बहुजन समाज पार्टी में कद्दावर हैसियत रखने वाले आरके चौधरी भी इस बंगले की मार झेल चुके हैं. एक जमाने में उन्हें बसपा नेतृत्व का विश्वास प्राप्त था और उनकी गिनती पार्टी के शक्तिशाली और असरदार नेताओं में की जाती थी, लेकिन भाग्य ने पलटा खाया और बात बिगड़ते-बिगड़ते इतनी बिगड़ी कि उन्हें पार्टी से ही रुखसत कर दिया गया.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सपा मुखिया मुलायम सिंह के खास लोगों में शुमार किए जाने वाले राजेन्द्र चौधरी को भी 2012 में छह कालिदास मार्ग आवंटित किया गया था. उन्हें खाद्य रसद और कारागार जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया गया था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि उनके पर कतर दिए गए और राजनीतिक पेंशन जैसे महत्वहीन विभाग का मंत्री बनाकर उन्हें किसी तरह कैबिनेट में बरकरार रखा गया. कहने वाले कहते हैं कि राजेन्द्र चौधरी इसलिए भी बच निकले कि वो छह नम्बर बंगला उनके नाम से एलॉट तो हुआ, पर वे उस बंगले में कभी रहने नहीं गए. वहां जाने की धमक से ही प्रकोप शुरू हो गया, तो उन्होंने बंगले से परहेज ही कर लिया. एलॉटमेंट कैंसिल कराया और अन्यत्र रहने लगे. छह नम्बर बंगले से चौधरी का रिश्ता निरीक्षण तक ही सीमित रहा, लेकिन इतने में ही उन्हें बंगले की तासीर समझ में आ गई. लिहाजा अपशकुन की गहरी छाया से वे बच निकले, लेकिन मुख्यमंत्री के अत्यंत करीबी होने के बावजूद महत्वहीन पद पर मंत्री बने रह कर उन्हें अपना ग्रह निवारण करना पड़ रहा है. लोग कहते हैं कि राजेन्द्र चौधरी को छह कालिदास मार्ग बंगले के अपशकुन होने का एहसास पहले ही हो गया था, इसीलिए उन्होंने इस बंगले से सुरक्षित दूरी बना ली.

मुख्यमंत्री के पड़ोस का यह बंगला वहां रहने वालों का सौभाग्य छीन लेता है, यह बात शायद बसपा मुखिया मायावती के खास सिपहसालार नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी पहले से पता थी. तभी वर्ष 2007 में सूबे में बसपा की सरकार बनने पर उन्हें यह बंगला आवंटित किये जाने के बावजूद काफी समय तक वे बंगले में दाखिल नहीं हुए. उनके न आने से बंगला बाबू सिंह कुशवाहा के हिस्से आया और सिर्फ बंगला ही क्यों, उससे जुड़ा दुर्भाग्य भी कुशवाहा के ही हिस्से आ गया. यह बंगला छोडने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी भले ही आज सत्ता से दूर हों और उत्तर प्रदेश के शासन में उनकी तूती न बोलती हो, लेकिन उनके राजनीतिक के सभापति की हैसियत से इस बंगले में रहे थे. लेकिन उसके बाद उन्हें न तो दोबारा यह पद प्राप्त हुआ और न उन्हें उतनी महत्वपूर्ण कोई दूसरी हैसियत ही प्राप्त हुई. बाद में वो यूपी एग्रो के चेयरमैन बने थे लेकिन धीरे-धीरे वो राजनीतिक परिदृश्य से गायब ही हो गए. 1991 की भारतीय जनता पार्टी सरकार में परिवहन मंत्री भी 6 कालिदास मार्ग में रहे, लेकिन उनका मंत्री पद बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि वह सरकार ही अल्पजीवी रही. सत्यप्रकाश विकल वैसे तो बाद में भी आगरा पूर्व से विधायक चुने जाते रहे, लेकिन मंत्री पद फिर उनकी पकड़ में नहीं आया. भाजपा नेता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव भी समाज कल्याण मंत्री की हैसियत से इस बंगले के निवासी रहे, लेकिन वो भी मंत्री पद का सुख लंबे समय तक नहीं भोग पाये.

मुख्यमंत्री के पड़ोस के इस बंगले की अपशकुनी छाया का प्रकोप झेलने वाले और भी कुछ नेता हो सकते हैं, लेकिन लगता है कि अपशकुन की यह छाया इक्कीसवीं शताब्दी में ही ज्यादा गहराई और वर्ष 2000 के बाद से इसमें रहने वाले नेता खुशहाल नहीं रह पाए. इस बंगले की अपशकुनी छाया के शिकार हुए नेताओं में ज्यादातर आपस में कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखने वाली बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से ही ताल्लुक रखते रहे हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि इस दौरान इन्हीं पार्टियों ने सूबे में लंबे समय तक सत्ता की कमान संभाली. वर्ष 2017 में सत्ता की देवी किस पर मेहरबान होगी यह कहना तो अभी संभव नहीं, पर यह देखना जरूर दिलचस्प होगा कि कोई मंत्री 6 कालिदास मार्ग बंगले में कदम रखना चाहेगा या नहीं. 2017 आने में अभी वक्त है और इस बीच यह बंगला किसकी जिंदगी में क्या उलट-फेर कर दे, इस पर निगाह बनाये रखना भी काफी दिलचस्प होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

कार्यालय नगर पालिका परिषद महराजगंज, जनपद-महराजगंज

15 अगस्त 2015 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद महराजगंज अपने नगर वासियों का हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत करती है तथा अपने नागरिकों से निम्न अपेक्षाएं करती है.

1. नगर को स्वच्छ रखने हेतु कूड़ा का निस्तारण निर्धारित स्थल पर ही करें.
2. जल ही जीवन है पेयजल की टोटियों को खुला न छोड़ें.
3. बकाया करों की अदायगी समय से करें.
4. जन्म एवं मृत्यु की सूचना कार्यालय नगर पालिका परिषद महाराजगंज में समय से दर्ज करायें.
5. सड़े गले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें.
6. नगर में स्थित विद्युत पोलों पर लगे प्रकाश उपकरणों को क्षति न पहुंचायें.
7. नगर पालिका की भूमि, नाला, नाली, पोखरियों में तथा सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण न करें.
8. पालिथीन का प्रयोग कदापि न करें.
9. गृहकर निर्धारण में सहयोग करें.

(पृथ्वीनाथ गुप्ता)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद महराजगंज
जनपद-महराजगंज

(श्री चन्द्रजीत भारती)
अध्यक्ष प्रतिनिधि
नगर पालिका परिषद महराजगंज
जनपद-महराजगंज

(रीता)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद महराजगंज
जनपद-महराजगंज

एवं
सम्मानित सदस्यगण

1. श्रीमती शशि जायसवाल 2. श्रीमती दुर्गावती देवी 3. श्री बालगोपाल 4. श्री सुग्रीव 5. श्री गामा प्रसाद 6. श्रीमती ब्रह्मावती देवी 7. श्री हीरा पासवान 8. श्री परमानन्द गौतम 9. श्री ब्रजभूषण प्रसाद 10. श्रीमती फूला देवी 11. श्री दीपक 12. श्रीमती रमावती देवी 13. श्री प्रदीप गौड़ 14. श्रीमती प्रभावती देवी 15. श्री अफजल अब्बासी 16. श्रीमती नीतू 17. श्री श्याम नरायण यादव 18. श्री सिद्धार्थ नाथ शुक्ला 19. श्री राघवेन्द्र मिश्र 20. श्री पवन कुमार सिंहानियां 21. श्रीमती शाहजहां 22. श्री विजई 23.श्रीमती दुर्गावती पाण्डेय

मनोनित सदस्यगण – 01-श्री अशफाक अहमद 02-श्री अमितेश गुप्ता 03-श्रीमती सोनी यादव 04-श्री रामा प्रसाद 05-श्री रामबेलास यादव,

पदेन सदस्य- श्री सुदामा प्रसाद (मा0 विधायक), श्री पंकज चौधरी (मा0 सांसद), श्री गणेश शंकर पाण्डेय (मा0 एम0एल0सी0/सभापति).

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

बनारसी साड़ी के साथ फिरोजाबाद की चूड़ियों का जिक्र न आए, यह असंभव है. अफसोस, महिलाओं को सुहाग की निशानी देने वाले कारीगर खुद मौत का शिकार होते जा रहे हैं. चूड़ी बनाने के दौरान यह कारीगर खतरनाक रासायनिक तत्वों के सम्पर्क में आते हैं, जिससे वह गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. उन्हें इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता कि वह अपना बेहतर इलाज करा सकें. जिला अस्पतालों में भी इन कारीगरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती है. इस कार्य में हजारों महिलाएं व बच्चे भी लगे हैं.

अपराधों पर परदा डाल रही है सरकार

अखिलेश सरकार ने कानून व्यवस्था के बड़े-बड़े अपराधों पर परदा डालना शुरू कर दिया है. पिछले दिनों ऐसी ही कोशिश के तहत हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष पुलिस तंत्र ने महिलाओं को सुरक्षा देने के ऐसे-ऐसे बेहतरीन आंकड़े प्रस्तुत किए कि मुख्यमंत्री की तबीयत भी हरी हो गई.

वैष्णवी वंदना

उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध बढ़े और सरकार की किरकिरी तेजी से बढ़ी तो रफूगीरी की रफ्तार भी तेज कर दी गई. मुलायम सिंह यादव की विवादास्पद टिप्पणी ने समाजवादी सरकार की और फजीहत कर दी. इससे निजात पाने की कोशिश में अखिलेश सरकार ने कानून व्यवस्था के बड़े-बड़े अपराधों पर परदा डालना शुरू कर दी है. पिछले दिनों ऐसी ही कोशिश के तहत हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष पुलिस तंत्र ने महिलाओं को सुरक्षा देने के ऐसे-ऐसे बेहतरीन आंकड़े प्रस्तुत किए कि मुख्यमंत्री की तबीयत भी हरी हो गई. कानून व्यवस्था को पंक्चर करने वाली पुलिस ने दावा किया कि महिलाओं की सुरक्षा में वह तत्पर है. वूमेन पावर लाइन को आधार बना कर पेश किए गए पुलिसिया आंकड़ों के समानान्तर आप महिलाओं पर हाल में हुए जघन्य अपराधों को ध्यान में रखें तो इन आंकड़ों के प्रायोजन का प्रयोजन समझ में आ जाएगा.

इन आंकड़ों की बाजीगरी से प्रसन्न मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कह दिया कि प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों की महिलाओं को वूमेन पावर लाइन-1090 का प्रभावी लाभ पहुंचाने के लिए इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. पुलिस ने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया कि वूमेन पावर लाइन की स्थापना से लेकर अब तक लगभग 03 लाख 97 हजार शिकायतों में से लगभग 03 लाख 88 हजार शिकायतों का निस्तारण भी कर दिया गया. मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अलमबरदारों से यह नहीं पूछा कि छेड़खानी-कंट्रोल के गणित में इतनी गति दिखाने वालों बलात्कार की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगा पाते? हाल के दिनों में महिलाओं पर हुए जघन्य अपराधों के कारण सपा सरकार की बदनामी से भन्नाए मुख्यमंत्री ने रफूगीरी करते हुए महिलाओं में इमेज बनाने की कोशिश की और कहा कि वूमेन पावर लाइन-1090 से अब तक लाखों महिलाओं एवं छात्राओं को राहत पहुंचाई गई है. महिलाओं को बेहतर सुरक्षा देने वाला समाज ही तरक्की कर सकता है. पुलिस के आंकड़ों के साथ अपना सुर मिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वूमेन पावर लाइन-1090 की स्थापना से लेकर अब तक लगभग 03 लाख 97 हजार शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके सापेक्ष लगभग 03 लाख 88 हजार शिकायतों का निस्तारण किया गया. साथ ही, सम्बन्धित शिकायतकर्ता महिला से उसका फीडबैक भी लिया गया. उन्होंने महिलाओं में विश्वास एवं सहयोग का वातावरण बनाने के लिए पावर एंजिल योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.

क्षतिपूर्ति के लिए सपा प्रवक्ता भी कूदे

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अंतरंग राजेंद्र चौधरी भी महिला पर हो रहे अपराध के कारण पार्टी और सरकार की हो रही क्षति की भरपाई के लिए मंच पर कूद पड़े. उन्होंने भी मुख्यमंत्री का डायलॉग दोहराते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए 1090 वूमेन पावर लाइन सेवा है. थानों पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं. महिला आयोग भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की सुनवाई करता है. महिला सशक्तीकरण पर पूरा जोर है. इस सबके बावजूद विपक्ष की मंशा सिर्फ सरकार को बदनाम करने की रहती है. वे प्रदेश में अपराध की निराधार बातें कर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की बदनामी कर रहे हैं. विपक्ष चाहता है कि विकास न हो, बाहर से उद्यमी न आएं, पूंजीनिवेश बाधित हो. विपक्षियों की यह इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है. चौधरी ने अपने बयान में सियासत पिरोते हुए कहा कि साढ़े तीन वर्ष होने को हैं, विपक्षी दल चुनावो में हुई अपनी करारी हार के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस तेजी से विकास एजेंडे को पूरा कर रही है उससे विपक्ष की बेचैनी और बढ़ती जा रही है. समाजवादी सरकार ने अपने पांच साल के लिए किए गए अधिकांश चुनावी वादे कम समय में ही पूरे कर दिए हैं. विपक्षी दलों को अपना भविष्य ही अंधकारमय दिखने लगा है. इससे निराश होकर ही वे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का झूठा हौआ खड़ा करने में लग गए हैं. राजेंद्र चौधरी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछली सरकारों और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कार्यप्रणाली के अंतर को भलीभांति महसूस कर रही है. पिछली सरकारों में अराजकता को छूट थी. कानून व्यवस्था का सबसे बुरा हाल तो बसपा के पांच सालों में रहा जब मंत्री विधायक तक लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार में शामिल रहे. पिछली सरकारों ने अपराध छुपाने की कोशिश की जबकि समाजवादी सरकार ने हर घटना की प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दे रखा है. समाजवादी सरकार बनने से बौखलाई बसपा अध्यक्ष मायावती तो पहले दिन से ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का राग अलापने लगी थी. अब भी उनका वह रिकार्ड जब-तब बजता ही रहता है. उनसे प्रेरणा लेकर बसपा के विधायकगण विधान मंडल में हंगामा करना अपनी फर्ज अदायगी समझते हैं. उनके पीछे कांग्रेस और भाजपा के विधायक भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने समय के पुराने कारनामों को ढकना रहता है. चौधरी ने कहा कि समाजवादी सरकार ने कानून व्यवस्था को हमेशा प्राथमिकता में रखा है. प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर कठोरता से अंकुश रखे जाने का स्पष्ट निर्देश है. शांति व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश है. इसके बावजूद अपराध क्यों नहीं रुक पा रहा, इस स्वाभाविक सवाल का जवाब देने से बचते हुए सपा प्रवक्ता राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल को मजबूती देने के लिए उसे आधुनिक संसाधनों से सज्जित करने का दावा करते हैं और कहने लगते हैं कि पुलिस थानों को हजार से ज्यादा जीपें दी गईं, गश्त की व्यवस्था सुधारी गई, गाजियाबाद, कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किए गए और पुलिस बल में बड़े पैमाने पर भर्तियां की गईं. लेकिन इन भर्तियों में अधिकांश सिपाही किस जाति के भर्ती किए गए? इस सवाल का जवाब जनता जानती है. ■

वूमेन हेल्पलाइन 1090 व्यवस्था को प्रभावी बनाने, इसके प्रचार-प्रसार तथा इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नामित छात्राओं को पावर एंजिल के रूप में जाना जाता है. इसके तहत कक्षा 10 एवं इससे ऊपर प्रत्येक कक्षा के हर सेक्शन से 02 से 03 तेज तर्रार छात्राओं को स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा चयनित कर अपनी संस्तुति के साथ वूमेन पावर लाइन को उपलब्ध कराया जाता है. ऐसी छात्राओं को पावर एंजिल (विशेष पुलिस अधिकारी) के रूप में नामित किया जाता है.

मुख्यमंत्री को पुलिस ने अवगत कराया कि वर्ष 2013 में वूमेन पावर लाइन के माध्यम से 01 लाख 42 हजार 113 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 01 लाख 41 हजार 949 का निस्तारण किया गया. वर्ष 2014 में 01 लाख 56 हजार 289 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें 01 लाख 56 हजार 114 का निस्तारण किया गया तथा वर्तमान वर्ष 2015 में माह जुलाई तक लगभग 97,000 दर्ज शिकायतों में से लगभग 89,000 का निस्तारण किया गया. शिकायतों के निस्तारण एवं गुणवत्ता से शिकायतकर्ता महिलाएं एवं छात्राएं संतुष्ट थीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जनपदों से प्राप्त शिकायतों से स्पष्ट है कि बड़े तथा शैक्षणिक रूप से जागरूक शहरों से शिकायतें अधिक प्राप्त हुई हैं. इससे जहां इन शहरों में वूमेन पावर लाइन के प्रति महिलाओं में जागरूकता का पता चलता है, वहीं अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों में इसके सम्बन्ध में और अधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता भी परिलक्षित होती है. उन्होंने अधिकारियों को इस व्यवस्था पर विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है. इस व्यवस्था की लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने इसके क्षमता विस्तार पर भी विचार करने का निर्देश दिया, जिससे प्रदेश के किसी भी कोने से फोन करने वाली महिला को होल्ड पर रखने की नौबत न आए. उन्होंने कहा कि इस सेवा को और अधिक सुगम बनाने के लिए मोबाइल-एप की सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज किए जाने तथा प्रत्येक जनपद में महिला हेल्प लाइन की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है, भले ही उसके जरिए शिकायत दर्ज करने की संख्या नगण्य हो. महिलाओं के विरुद्ध गम्भीर अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रत्येक जनपद में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का फैसला पहले लिया जा चुका है. लेकिन उसके कारगर होने में अभी वक्त लगेगा.

समाजवादी विचारधारा में महिलाओं के विशिष्ट महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के मान-सम्मान एवं सुरक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास गम्भीरता से किए जाने चाहिए. वर्तमान राज्य सरकार जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क है, वहीं उनके सशक्तिकरण के लिए भी तमाम योजनाएं संचालित की हैं. परिवार की महिला मुखिया को सम्मान दिलाने के लिए ही समाजवादी पेंशन योजना की धनराशि उसके खाते में प्रेषित की जा रही है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इस पेंशन योजना से लगभग 45 लाख परिवारों को आच्छादित किया गया है. जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष ये स्व-प्रशंसित आंकड़े पेश किए जा रहे थे उसमें पुलिस महानिरीक्षक (वूमेन पावर लाइन) नवनीत सिकेरा समेत अन्य आला पुलिस अधिकारी उपस्थित थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सियासतदानों ने पहन ली बनारसी साड़ी और फिरोजाबादी चूड़ी

कारीगर मुफलिसी और हिकारत की ज़िंदगी जी रहे हैं

वैदेही

अब फिर शादी का वक्त आएगा और फिर साड़ी और चूड़ी पर चकाचौंध मचेगी. घर में शादी हो और बनारस की साड़ी व फिरोजाबाद की चूड़ियों की खरीदारी न हो, यह हो नहीं सकता. इनके बगैर दुल्हन का श्रृंगार कैसे होगा. इनकी खरीदारी के नाम से ही महिलाओं की आंखों में चमक आ जाती है. यह तस्वीर का खूबसूरत पहलू है जहां केवल खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं. साड़ियों व चूड़ियों की चमक के पीछे उन कारीगरों की मुफलिसी छिपी रहती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस धंधे से जुड़े हैं. ये कारीगर साड़ी के साथ खुशियों की सौगात भी बुनते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर दुखों का ताना-बाना और आंखों में त्रासदी की दास्तां भरी पड़ी है. यह दोनों ही उद्योग उत्तर प्रदेश की पहचान और परम्परा दोनों से ही जुड़े हैं, जो समय के साथ समाप्त होते जा रहे हैं. इस आर्थिक मार से भदोही के कालीन उद्योग से जुड़े बुनकर भी कराह रहे हैं. उन कारीगरों की उंगलियों में जादू है. उनके बुने कालीन राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री निवास और देश-विदेश की नामचीन हस्तियों के घरों की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन खुद उनके घरों में टाट का पर्दा लटकता है. कारीगरों के कल्याण की सियासत तो खूब होती है, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है.

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस और उसके आस-पास के इलाके के लगभग पांच से छह लाख लोग बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़े हैं. इस उद्योग से जुड़े अनिल कुमार के मुताबिक बनारसी साड़ी बनाने वाले आधे से अधिक कारीगर काम धंधे की तलाश में पलायन कर गए हैं, जो घर के मोह में बनारस नहीं छोड़ सके, वह गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं. वजह भारतीय नारी के सुहाग और श्रृंगार का प्रतीक बनारसी साड़ी का उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है. इस काम में लगे हजारों कारीगरों की माली हालत काफी खराब हो चली है. बनारसी साड़ी उद्योग पर मंडरा रहे इस संकट का प्रमुख कारण सूरत और मऊ में बनने वाली सस्ती व सिंथेटिक और पॉलीस्टर की साड़ियां हैं. इस उद्योग में बिचौलियों की गहरी पैठ भी कारीगरों की दुर्दशा का एक अहम पहलू है. बिचौलिए और व्यापारी बनारसी साड़ी का कारोबार करके लखपति-करोड़पति बन गए, लेकिन कारीगर की आर्थिक हालत दिन-प्रतिदिन खस्ता होती गई. बनारस के इन बुनकरों के माली हालात खराब होने की वजह से उनके परिवार की शैक्षिक व सामाजिक स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हो सका. रोजी-रोटी की समस्या से परेशान बुनकर रिक्शा चलाने, होटल ढाबों में काम करने और फेरी लगाने को मजबूर हैं. जिन हाथों की उंगलियां कभी सुहागिनों को सजाने वाली रेशमी साड़ियां बुनती थीं, वह आज कप-प्लेट धोने को मजबूर हैं. बुनकरों के हालात सुधारने के लिए सरकार तक फरियाद भी पहुंचाई गई. जैसे सरकारी रिवाज है, इनके मामले में ठीक वैसा ही हुआ. सरकारी अमले ने बुनकरों को समय-समय पर आश्वासनों की पोटली थमाने से कभी परहेज नहीं किया, लेकिन इनका जीवन स्तर सुधारने, उन्हें बैंक से कर्ज आदि की व्यवस्था करने, बनाए गए माल की बिक्री के साधन उपलब्ध कराने और बिचौलियों को इस धंधे से बाहर का रास्ता दिखाने जैसे जमीनी कदम उठाने से हमेशा ही परहेज किया गया. सरकारी उपेक्षा का ही नतीजा है कि ये बुनकर महाजनों और स्थानीय गद्दीदारों के शोषण का शिकार होते हैं. उनके खुद के पास उतना पैसा नहीं होता कि वह कच्चा माल खरीद कर उससे साड़ी तैयार कर सके. ऐसे में बुनकर उन महाजनों से कच्चा माल लेकर साड़ी तैयार करते हैं और फिर उसे गद्दीदारों को सौंप देते हैं. उसके एवज में उनके हाथ में बहुत ही मामूली रकम आती है, जिससे उनका खुद का गुजारा चल पाना मुश्किल होता है. अगर बुनकर किसी तरह जुगाड़ करके कच्चे माल का इंतजाम कर भी लेते हैं, तो साड़ी तैयार होने के बाद उनके सामने उसे बेचने की दिक्कत होती है. मार्केट में गद्दीदारों का वर्चस्व होता है. थकहार कर बुनकर साड़ी सस्ते दाम पर गद्दीदार को ही सौंप देते हैं. उस वजह से उनकी माली हालत में सुधार न पहले हुआ था और न अब हो रहा है. बुनकर मोहम्मद सलीम के अनुसार उनके घरों के बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तक इस काम में लगी रहती हैं लेकिन फिर भी उनके हिस्से में भरपेट खाना नहीं आता है. बैंकों से उनके लिए ऋण की व्यवस्था भी नहीं है. सरकारी मदद का लाभ कुछ गिने-चुने बुनकर ही उठा रहे हैं. हजारों बुनकर बिजली के बकाया भुगतान की समस्या से भी परेशान हैं. साड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे का अंत तो उन्हें नजर आता है, लेकिन अपनी दुश्वारियों का अंत होता उन्हें दिखाई नहीं देता है.

बनारसी साड़ी के साथ फिरोजाबाद की चूड़ियों का जिक्र न आए, यह असंभव है. अफसोस, महिलाओं को सुहाग की निशानी देने वाले कारीगर खुद मौत का शिकार होते जा रहे हैं. चूड़ी बनाने के दौरान यह कारीगर खतरनाक रासायनिक तत्वों के सम्पर्क में आते हैं, जिससे वह गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. उन्हें इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता कि वह अपना बेहतर इलाज करा सकें. जिला अस्पतालों में भी इन कारीगरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती है. इस कार्य में हजारों महिलाएं व बच्चे भी लगे हैं. घातक बीमारियां इन्हें भी अपना निशाना बना रही हैं. चूड़ी उद्योग से जुड़े कारीगरों व मजदूरों की हर सांस के साथ कांच के महीन कण उनके शरीर के अंदर घुसते जाते हैं, जो अंततः उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता है. दूसरों को सुहाग की निशानी देने वाले उस उद्योग से जुड़े परिवारों में ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिनका खुद का सुहाग उजड़ चुका है. उनके बच्चे कम उम्र में ही घातक बीमारियों से पीड़ित हैं. सरकारी योजनाएं उनके लिए बेमानी है. उनके मुरझाए चेहरे चूड़ियों की चमक के सामने छिप जाते हैं. बनारसी साड़ी के बुनकरों जैसे खराब हालात भदोही के कालीन उद्योग से जुड़े कारीगरों की भी है. भुखमरी, कर्ज और बदहाली से परेशान उन बुनकरों ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है. आलम यह है कि कालीन बेल्ट में बुनकरों का अभाव हो गया है. यह इस उद्योग के लिए खतरनाक संकेत तो है, लेकिन बुनकरों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है. उन्हें इस उद्योग में रात-दिन खटने के बाद भी बदहाली का जीवन गुजर बसर करना पड़ता है. ऐसे में अधिकांश बुनकर बड़े शहरों की ओर पलायन कर गए हैं. अगर वह ऐसा नहीं करते तो शायद उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता. बीते तीन-चार वर्षों में कई बुनकर तंगहाली की जिंदगी जीने के बजाय मौत को गले लगा चुके हैं. एक अनुमान के अनुसार करीब साठ हजार बुनकर अपना पुश्तैनी धंधा छोडकर पलायन कर चुके हैं या फिर वह अब कोई दूसरा काम धंधा कर रहे हैं. बुनकरों की घटती संख्या से चिंतित कालीन निर्माता केंद्र सरकार से गुहार तक लगा चुके हैं. भदोही का कालीन विश्व प्रसिद्ध है, इस उद्योग पर संकट से उत्तर प्रदेश के कारीगरों का हुनर और उनकी अपनी अलग पहचान खोने का खतरा न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार को दिखाई देता है. कालीन निर्माता भारी मुनाफा कमाते हैं, लेकिन वह खुद यह कोशिश नहीं करते कि मुनाफे का वाजिब हिस्सा बुनकरों को भी मिल सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

एनएच के मजदूर इस स्थान पर सुधारीकरण के कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान पर न ही जल निकास नाली निर्मित की जा रही हैं और न ही लूज बोल्डरों को गिराने का काम किया जा रहा है. प्रांतीय व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश का कहना है कि आपदा के 28 माह गुजरने के बाद भी भूस्खलन वाले स्थान पर पक्का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है. गांव को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा दीवारें निर्मित नहीं की गई हैं. जिसके कारण गांव पर कभी भी आफत आ सकती है.

अमरमणि की राजनीतिक विरासत धराशायी हो गई

शत्रुन्जय सिंह रैकवार

सारा हत्याकांड में लखनऊ जेल में बन्द सपा नेता अमनमणि त्रिपाठी साजिशकर्ता हैं या खुद साजिश के शिकार, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे पूर्वांचल में इसकी जोरदार चर्चा है. सारा हत्याकांड ठीक उसी तरह का हाई-प्रोफाईल केस होता जाता रहा है जैसे 12 साल पहले लखनऊ का मधुमिता हत्याकांड हुआ था. नौ मई 2003 को लखनऊ के पेपरमिल कालोनी में जब कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामला सात समन्दर पार तक चर्चा का विषय बन जाएगा. पर जब इस प्रकरण की सीबीआई जांच शुरू हुई, तो वह सब हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. उस समय के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को न सिर्फ जेल जाना पड़ा बल्कि चार साल बाद कोर्ट ने दोनों की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया. ठीक उसी तरह अब अमरमणि के बेटे अमनमणि की पत्नी सारा की फिरोजाबाद में कथित सड़क हादसे में हुई मौत का मामला भी तरह-तरह की चर्चाओं में सुमार हो गया है. अमनमणि जहां इसे सड़क दुर्घटना बता रहे हैं, वहीं सारा के परिवार का कहना है कि सारा को नियोजित तरीके से मारा गया है. लोग कहते हैं कि अमनमणि भी अपने पिता अमरमणि के कदमों पर चल पड़ा है. इसकी नजीर पिछले साल 23 जुलाई को देखने को मिली जब उसने राजधानी लखनऊ में ऋषि पाण्डेय को अगवा कर लिया था. इस मामले में उसे गिरफ्तार करने व उसकी सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश तक हुआ, लेकिन वह खुलेआम घूमता रहा.

बीते दिनों लखनऊ से दिल्ली जा रहे अमनमणि और उसकी पत्नी सारा एक सड़क हादसे (कथित) का शिकार हुए, जिसमें केवल सारा की मौत हो गई, जबकि अमनमणि को खरोंच तक नहीं आई. अमनमणि अपनी पत्नी सारा के संदेहास्पद मौत के मामले में जेल में बंद है. देखा जाए तो मधुमिता हत्याकांड व सारा की संदेहास्पद मौत में काफी समानता है. मधुमिता व अमरमणि का सम्बन्ध अमरमणि की पत्नी को मंजूर नहीं था. इधर, अमनमणि व सारा का सम्बन्ध अमन के पिता अमरमणि के लिए नागवार था. मधुमिता हत्याकांड के समय अमरमणि प्रदेश सरकार में मंत्री थे और आज उसी समाजवादी पार्टी की सरकार है. सपा के उस कार्यकाल में पिता अमरमणि जेल गए और सपा के इस कार्यकाल में बेटा अमनमणि जेल में है. मधुमिता हत्याकांड के बाद मधुमिता की बहन निधि शुक्ला के संघर्ष का परिणाम है कि अमरमणि आजीवन कारावास झेल रहे हैं, तो इधर सारा की मां सीमा सिंह के संघर्ष का नतीजा है कि अमनमणि जेल में है और सारा की मौत का मामला सीबीआई की जांच की परिधि में है. मधुमिता हत्याकांड और सारा प्रकरण, दोनों में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणाली संदेह के दायरे में रही.

अमरमणि के पुत्र अमनमणि पर पत्नी सारा की हत्या का केस दर्ज होने के बाद मणि परिवार का राजनीतिक भविष्य दांव पर है. कवयित्री मधुमिता हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमरमणि अपने इसी इकलौते संतान में राजनीतिक भविष्य देख रहे थे. अमन की पत्नी सारा के घर वाले जिस तरह खुलकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे अब अमन का भविष्य भी अपने पिता की तरह ही संकट में फंसता दिख रहा है.

अमरमणि लक्ष्मीपुर से चार-बार विधायक रहे. उनकी छवि दबंग विधायकों वाली रही. क्षेत्र में उनकी पकड़ का आलम यह था कि 2007 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जेल से लड़ा और जीते भी. मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा होने के बाद उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में भाई अजीत मणि पर दांव लगाया मगर जनता ने उन्हें नकार दिया. 2012 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने बेटे अमनमणि को मैदान में उतारा. उनके समर्थकों ने वोटों की संख्या में इजाफा तो किया मगर अमन को जीत नसीब नहीं हुई. अमन की क्षेत्र में सक्रियता से माना जाने लगा था कि वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बीते वर्ष लखनऊ में गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि पांडेय के अपहरण के बाद जब अमन पर केस दर्ज हुआ, तबसे उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल छा गए. कभी अमन के करीब रहे ऋषि पाण्डेय के बेटे मानू ने इसी दौरान कथित रूप से एक वीडियो लीक कर दी, जिससे यह उजागर हुआ कि अमनमणि ने लखनऊ की सारा से गुपचुप शादी कर ली है. मणि परिवार ने इस शादी को कबूल नहीं किया. लोग कहते हैं कि इसी में सारा की हत्या कर दी गई, तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सारा के बहाने अमनमणि भी नियोजित कुचक्र के शिकार हो गए. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा की चाल से सकते में हरीश सरकार

राजकुमार शर्मा

स्टेट वॉर मेमोरियल के लिए जमीन चिहिंत कर पूर्व सैनिकों में हरीश रावत कि सरकार यह राय बनाने में जुटी है कि केंद्र के चीड़ बाग से उनका चयनित स्थल बेहतर है. देश की मोदी सरकार को अब तक हर मामले में आइना दिखाने वाले हरीश रावत एक बार फिर हम किसी से कम नही का संदेश देना चाहते हैं. भाजपा की केन्द्र सरकार से पटकनी खा चुकी प्रदेश सरकार को वन रैंक वन पेंशन आंदोलन से संजीवनी मिली है. उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में बनने वाले वॉर मेमोरियल पर भाजपा की सियासी चतुराई से चित्त हुई प्रदेश की हरीश सरकार उसका तोड़ तलाश रही है. उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल्य राज्य है. बरसों से जिस वॉर मेमोरियल का जिक्र शौर्य व विजय दिवस पर सजने वाले सियासी मंचों तक सीमित था अब उसके निर्माण पर केंद्र और प्रदेश सरकार आमने सामने है. भाजपा ने केंद्र से मिलकर चीड़ बाग में वॉर मेमोरियल के लिए भूमि सुनिश्चित कर शिलान्यास तय कर बाजी मार ली. अब प्रदेश सरकार इसका विकल्प ढूंढ रही है. इस प्रतिस्पर्धा के भले कई कारण हैं. सबसे अहम उस दस लाख की आबादी का वोट बैंक भी है, जो सीधे तौर पर शहीद और पूर्व सैनिकों से जुड़ा है और 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को सीधे रूप से प्रभावित करेगी. स्टेट वॉर मेमोरियल के निर्माण के लिए भूमि की तलाश वर्ष 2009 में तत्कालीन भाजपा सरकार के समय से शुरू होकर अब तक जारी थी. वर्ष 2012 में जब कांग्रेस को सत्ता मिली तो उन्होंने भाजपा से एक कदम आगे बढ़कर इसके निर्माण का बेड़ा उठाया पर भूमि का मसला उनकी राह का रोड़ा बना. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मीडिया ने यह मामला उठाया कि जांबाज जवानों के उस प्रांत की अस्थायी राजधानी में प्रस्तावित वॉर मेमोरियल आखिर कब बनेगा? उस अभियान की तपिश महसूस हुई तो सरकार ने मेमोरियल के लिए जमीन खोजने का अभियान तेज कर दिया. वॉर मेमोरियल के लिए सरकार में सक्रियता बढ़ी और उधर भाजपा खेमे में बेचैनी बढ़ी. मामला दोनों पार्टियों की सरकारों के तीन वर्ष में कोई प्रगति नहीं होने से बराबरी पर था. बाजी तब पलटी जब भाजपा सांसद तरुण विजय ने वॉर मेमोरियल के निर्माण का मुद्दा रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा. भाजपा ने बेहद चतुराई से मौके को लपक लिया. चीड़ बाग स्थित जिस भूमि के लिए भाजपा कांग्रेस कई बार प्रयास करती रही रक्षा मंत्रालय ने उस भूमि को सांसद की पहल पर देने के लिए हामी भर दी. सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत 26 जुलाई को भूमि चिंहीकरण के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बना रहे थे और उधर रक्षा मंत्री के समक्ष मेमोरियल के शिलान्यास तक फाइनल हो गया. लंबे समय से लटके मामले को केन्द्र की मोदी सरकार ने महज एक पखवारे में ही निपटा दिया. खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड पहुंच कर इसकी तसदीक भी कर दी. पूर्व सैनिकों से जुड़े इस बड़े मसले पर कांग्रेस पहले बैकफुट पर आई अब एकाएक उन्होंने अपने स्तर पर वॉर मेमोरियल निर्माण का वादा पूरा करने का नया वादा कर दिया. हरीश रावत चीड़ बाग में केन्द्र सरकार द्वारा मेमोरियल निर्माण से ही अनभिज्ञता जता रहे हैं. केन्द्र के वार मेमोरियल के फाइनल होने के बाद अब हरीश सरकार अलग से स्मारक निर्माण के लिए भूमि चयन की कसरत कर रही है. अब ऐसा लगता है कि बरसों तक एक वॉर मेमोरियल के लिए तरस रहे पूर्व सैनिकों को दो स्मारक एक साथ मिलेंगे. सरकार ने खुद को पूर्व सैनिकों से किए वायदे पर खरा उतरने के लिए एकाएक पुरानी जेल परिसर को स्मारक के लिए हस्तांतरित करने के निर्देश दे दिए. रक्षा मंत्री का दौरा टलने से मिले समय में सरकार ने स्मारक का शिलान्यास कर बाजी पलटने की तैयारी शुरू कर दी है.

प्रदेश सरकार की कोशिशें

स्टेट वॉर मेमोरियल के लिए 2009 में सर्वप्रथम चीड़बाग सैन्य भूमि चयनित की गई. उसके बाद रक्षा मंत्रालय से भूमि स्वीकृति का मामला दो वर्ष तक अधर में लटका रहा. वर्ष 2011 में सर्वे आफ इंडिया की चयनित 10.4 हेक्टेयर भूमि प्रस्ताव पर एनओसी नहीं मिली. वर्ष 2012 में ग्राम डांडा लखौड़ में 1.6 हैक्टेयर आवंटित भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई. वर्ष 2013 में पुरानी जेल के पास चयनित भूमि का प्रस्ताव बाद में खारिज हुआ. ■

न तुम जीते और न हम हारे की तर्ज पर सहमति बनी

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तराखंड पुलिस में फैल रहे आन्दोलन की चिंगारी को शोला बनने से पहले ही मुख्यमंत्री हरीश रावत उसे रोकने में सफल रहे. पुलिस जवानों की वेतन संगति को लेकर सरकार में कुछ इसी तरह की सहमति बनी कि न तुम जीते और न हम हारे. आक्रोशित पुलिस जवानों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार में सहमति बन गई है. सरकार ने फिलहाल सैद्धांतिक तौर पर पुलिस कॉस्टेबलों को नोशनल (काल्पनिक) इंक्रीमेंट देने का फैसला लिया है. इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार को 50-60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार वहन करना होगा. इस बारे पुलिस मुख्यालय ने ही शासन को प्रस्ताव भेजा था. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अचानक बैठक बुलाई और अपनी सहमति दे दी. आक्रोशित कॉस्टेबलों के रिवाइज ग्रेड-पे दिसंबर 2011 के आधार पर शासनादेश की तिथि से ही काल्पनिक व वास्तविक दोनों माना गया है. यदि इस काल्पनिक आदेश को जनवरी 2006 से मान लिया जाए, तो खर्च भी कम होगा और भविष्य में ज्यादा लाभ मिलेगा. कुछ इसी तरह का प्रस्ताव पीएचक्यू ने तैयार किया. वेतन विसंगतियों के खिलाफ पुलिस कर्मियों के मिशन आक्रोश के खिलाफ अब पुलिस मुख्यालय सख्त हो गया है. पुलिस कर्मियों को उकसाने के मामले में उत्तरकाशी में तैनात एक कांस्टेबल के साथ ही कालसी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में बाहरी लोगों के साथ ही पुलिस कर्मियों को चिहिंत कर इसके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. उत्तराखंड में 16 अगस्त के पुलिस कर्मियों ने अप्रत्यक्ष रूप से मिशन आक्रोश के रूप में आंदोलन की शुरूआत की थी. सोशल मीडिया के जरिए पुलिस कर्मियों को लामबंद करने के साथ ही चरणवार आंदोलन की घोषणा की गई थी. आंदोलन के तहत एक दिन कुछ स्थानों पर रिजर्व पुलिस के जवानों ने बांह में काली पट्टी भी बांधी. साथ ही कुछ स्थानों पर दिन के भोजन का बहिष्कार भी किया. पुलिस कर्मियों के आंदोलन के मद्देनजर डीजीपी बीएस सिद्धू को मैदान में उतरना पड़ा. उन्होंने पुलिस कर्मियों को टीवी चैनल के जरिए संदेश देकर अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाया. साथ ही आश्वासन दिया कि 31 दिसंबर तक उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा. अब पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस मामले में उकसाने वाले पुलिस कर्मियों के साथ ही बाहरी लोगों को चिहिंत किया जा रहा है. एलआइयू की रिपोर्ट पर देहरादून कोतवाली में बाहरी लोगों के साथ ही कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को उकसाने के आरोप में कालसी थाना पुलिस ने राकेश तोमर पुत्र छेल सिंह निवासी डुमेट बाड़वाला को गिरफ्तार किया है. इसके खिलाफ कालसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

भूस्खलन के कारण केदार नाथ हाईवे से नज़दीक गांव पर ख़तरा

रेनू शर्मा

केदारनाथ हाईवे से सटे खाट गांव के नीचे लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते गांव पर खतरा मंडरा रहा है. भूस्खलन वाले स्थान का शीघ्र पक्का ट्रीटमेंट न किया गया तो हाईवे के साथ गांव कभी भी जमीदोंज हो सकता है. वर्ष 2013 में खाट गांव के नीचे मंदाकिनी नदी के कटाव से हाईवे के किनारे स्थित प्राचीन डोल्या देवी मंदिर भी आपदा की भेंट चढ़ गया था. इसके साथ ही केदारनाथ हाईवे भी लगभग बीस मीटर ध्वस्त हो गया था. जिसके चलते खाट गांव के 75 परिवार भी खतरे की जद में आ गए थे. स्थानीय ग्रामीणों के भारी दबाव के कारण बीआरओ ने मार्ग के दुरुस्तीकरण के साथ ही कच्ची सुरक्षा दीवारें निर्मित कर हाईवे को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया था, बरसात और भूस्खलन के कारण इस स्थान पर लगातार मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है. हाईवे के बायीं ओर स्थित खाट गांव के कई आवासीय भवनों में दरारें आ चुकी हैं साथ ही गांव की जमीन भी आपदा की भेंट चढ़ गई है. वर्तमान में केदारनाथ हाईवे एनएच को हस्तातंरित हो गया है. एनएच के मजदूर इस स्थान पर सुधारीकरण के कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान पर न ही जल निकास नाली निर्मित की जा रही हैं और न ही लूज बोल्डरों को गिराने का काम किया जा रहा है. प्रांतीय व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश का कहना है कि आपदा के 28 माह गुजरने के बाद भी भूस्खलन वाले स्थान पर पक्का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है. गांव को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा दीवारें निर्मित नहीं की गई हैं. जिसके कारण गांव पर कभी भी आफत आ सकती है. उन्होंने कहा कि इस स्थान पर जल निकासी नाली निर्मित न किए जाने से बरसाती पानी मार्ग में फैल कर स्थिति को और अधिक भयावह बना रहा है. कई बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी है. ■

स्थानीय ग्रामीणों के भारी दबाव के कारण बीआरओ ने मार्ग के दुरुस्तीकरण के साथ ही कच्ची सुरक्षा दीवारें निर्मित कर हाईवे को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया था, बरसात और भूस्खलन के कारण इस स्थान पर लगातार मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनायें
अजित कुमार त्रिपाठी
जिला खाद्य विपणन अधिकारी
जनपद महाराजगंज उ0 प्र0.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनायें

आर0पी0 सिंह
डी0एफ0ओ0
जनपद-कुशीनगर उ0 प्र0.